C O N T E N T S

Sixteenth Series, Vol.VII, Fourth Session, 2015/1936 (Saka)
No.3, Wednesday, February, 25, 2015/Phalguna 6, 1936 (Saka)

S U B J E C T	**P A G E S**
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No.21 to 24	8-45
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.25 to 40	46-123
Unstarred Question Nos.231 to 460	124-743

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 744-745

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
5th Report 746

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
Statements 746

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
264th Report 746

ELECTION TO COMMITTEE
Court of University of Delhi 747

MOTION RE: ELEVENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE 748

SUBMISSIONS BY MEMBERS
(i) Re : Problems faced by rubber growers in Kerala 754-757

(ii) Re : Problems faced by students of Jammu and Kashmir in getting scholarship under the Prime Minister Special Scholarship Scheme 761-764

MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILL AS RETURNED BY RAJYA SABHA WITH AMENDMENTS 774-775

MATTERS UNDER RULE 377 776-794

(i) Need to accord sanction for establishment of Bundelkhand University in Damoh, Madhya Pradesh

Shri Prahlad Singh Patel 777

(ii) Need to take steps for providing benefits and facilities to persons belonging to socially, educationally and economically weaker section as are available to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

Shri Ajay Mishra Teni 778

(iii) Need to provide funds for undertaking gauge conversion of railway line between Narkatiyaganj and Raxaul in Bihar

Shri Satish Chandra Dubey 779

(iv) Need to take suitable measures to prevent the damage to crops and disruptions in traffic due to intrusion of Nilgais in Chandauli Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Dr. Mahendra Nath Pandey 780

(v) Need to include Bargi dam project in Jabalpur, Madhya Pradesh in the scheme of national project

Shri Ganesh Singh 781

(vi) Need to provide rail connectivity between Sambhal and Gajraula in Uttar Pradesh

Shri Satyapal Singh 782

(vii) Need to revive multipurpose projects for development of various facilities in Ballia Parliamentary constituency, Uttar Pradesh

Shri Bharat Singh 783

(viii) Need to augment railway services in Mahasamund Parliamentary Constituency in Chhattisgarh

Shri Chandu Lal Sahu 784

(ix) Need to revive Barauni Fertilizer Factory in Bihar

Dr. Bhola Singh 785

(x) Need to send a medical team to contain the spread of Monkey Fever disease in Wayanad district in Kerala

Shri M. I. Shanavas 786

(xi) Need to impress upon the Government of Kerala to undertake repair of Shenbagavalli dam to facilitate release of water to Tamil Nadu

Shrimati M. Vasanthi 787

(xii) Need to grant permission as well as financial assistance for replenishing ground water in arid zones of Coimbatore, Erode and Tiruppur in Tamil Nadu

Shrimati V. Sathyabama 788

(xiii) Need to check the steep hike in prices of thread and yarn

Dr. Ratna De (Nag) 789

(xiv) Need to sanction financial as well as technical assistance to provide safe drinking water in the Nuapada district of Odisha

Shri Arka Keshari Deo 790

(xv) Need to address the problems of physically challenged STD/PCO booth operators at railway stations including the hassles being faced by such railway passengers in trains

Shri Rahul Shewale 791

(xvi) Need to bring in more transparency in implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

Shrimati Supriya Sule 792

(xvii) Need to take effective steps to make river Yamuna pollution free

Shri Dushyant Chautala 793

(xviii) Need to review the Dr. Meena Kumari report on deep-sea fishing

Shri N.K. Premachandran 794

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS 795-917

Shri Arvind Sawant 796-799

Shri M. Venkaiah Naidu 800-826

Shri Abhijit Mukherjee 827-832

Dr. Virendra Kumar 833-837

Dr. Ratna De (Nag) 838-841

Dr. Sunil Baliram Gaikwad 842

Shri Deviji M. Patel 843-844

Shri Mulayam Singh Yadav 845-854

Dr. Kulamani Samal 860-861

Shri R. Dhruvanarayana 862-864

Shri P.P. Chaudhary 865

Shri H.D. Devegowda 866-873

Shri Bidyut Baran Mahato 874-875

Shri Thota Narasimham 876-881

Shri Rahul Kaswan 882-884

Shri A.P. Jithender Reddy 885-893

Shri Mohammad Salim 894-899

Shri Mekapati Raja Mohan Reddy 900-903
Shrimati Supriya Sule 904-913
Shri Jay Prakash Narayan Yadav 914-917

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 918
Member-wise Index to Unstarred Questions 919-923

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 924
Ministry-wise Index to Unstarred Questions 925-926

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Prahlad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri Hukum Singh

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, February, 25, 2015/Phalguna 6, 1936 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Now,Q.No.21. Shrimati Rama Devi.

(Q.No.21.)

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदया, भारत के शहरी क्षेत्र में कुल 33510 मलिन बस्तियां होने का अनुमान हैं। इनमें लगभग 41 प्रतिशत अधिसूचित और 59 प्रतिशत अनधिसूचित हैं। यह संख्या कितनी सही है, यह बताना मुश्किल हो जाता है। मलिन बस्तियों में रहन-सहन की हालत ठीक नहीं है, मलिन बस्तियों में लोगों की बहुत भीड़, सफाई एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, कच्चे निर्माण, समुचित शिक्षा एवं पर्याप्त पेयजल न होने जैसी बुनियादी समस्याएं हैं।

जुलाई 2014 तक केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. (जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन) के तहत 14.42 हजार रिहायशी इकाईयों को निर्मित किया जाना था, जिनकी कुल लागत 37 हजार करोड़ रुपये के आसपास थी और जिसमें केन्द्र का योगदान 20 हजार करोड़ रुपये था। वहीं राजीव आवास योजना के अंतर्गत 1.20 लाख हजार घरों को निर्मित करने के लिए 6472 करोड़ रुपये की परियोजना थी, जिसमें केन्द्र का अंश 3500 करोड़ रुपये था। इस योजना के अंतर्गत कुल 166 परियोजनाएं अनुमोदित तो हुईं, फिर भी लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार नहीं हुआ। मैं यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार ने शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाने की योजना बनाई है?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि देश में 2011 की सैंसस के आधार पर 13.75 मिलियन लोग स्लम्स में रह रहे हैं। 2001 में यह संख्या 10.2 मिलियन थी, जो अब बढ़कर 13.75 मिलियन हो गयी है। There are three categories. One is, Slums, which are notified by the State Governments under various laws; and 4.97 million slum households are in the notified slums. Then, there are Recognised Slums, which are not notified but recognised as slums by the State Governments. They are 3.79 million households. Then, there are Identified Slums, which are neither notified nor registered but are identified as Slums. During the Census, their number is 4.99 million households. Thirty-eight per cent of the slum households are in 46 million plus cities. बड़े-बड़े शहरों में ये बस्तियां हैं। मलिन बस्ती के संदर्भ में इस शब्द पर भी कुछ लोगों ने आपत्ति व्यक्त की है, इसलिए मैं इन्हें गरीब लोगों की बस्ती कहता हूं और मैं उस विवाद में नहीं पड़ना

चाहता। स्लम्स में अपने प्रिमिसेज में केवल 19 परसैन्ट टायलेट्स हैं और बाकी लोग ओपन डेफेकेशन के लिए जा रहे हैं। दूसरा, स्लम इलाके में केवल 37 पर्सेंट ड्रेनेज सिस्टम है, common drainage, not individual drainage. तीसरा, 57 per cent of the households have drinking water in their premises. उस प्रिमाइसिस में है, घर पर नहीं है। 90.5 per cent households have electricity. बिजली तो है, आज-कल वहां स्थानीय दबाव के कारण पॉलिटिकल लीडर्स भी जाते हैं, सब मिल कर बिजली का कनैक्शन दिलवाते हैं। हमारे मंत्रालय की टैक्निकल कमेटी ने इस विषय के बारे में अध्ययन किया है। उन्होंने अभी तक आईडेंटिफाई किया है कि देश के अर्बन एरियाज़ में 18.78 मिलियन हाऊसेज़ का अभाव है, यह स्थिति है। इसमें economically weaker sections - 10.5 million and low income group - 7.4 million हैं। कुल मिला कर 96 per cent of the shortage, ई.डब्ल्यू.एस. और एल.आई.जी. कैटेगरी में है। टैक्निकल कमेटी ने यह भी एस्टिमेट किया कि 0.53 million homeless require houses. इनके लिए मकान का निर्माण करना सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी के ऊपर केंद्र सरकार ध्यान दे रही है। मगर जमीन स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट और सैंटर दोनों को मिल कर स्लम डिवेल्पमेंट की योजना बनानी चाहिए। केंद्र सरकार के द्वारा हम प्रदेश को, एक बार उन्होंने योजना बनायी तो हम viability gap fund के रूप में, नहीं तो direct upfront की अभी लेटेस्ट हमारी सोच है, 'Housing for All' नाम से जो नई योजना आने वाली है, उसमें डायरेक्ट अपफ्रंट देने की हमारी सोच है, ताकि वह पैसा वे बैंक में जमा कर सकें। बैंक में जो ई.एम.आई. पे करनी पड़ेगी, उसमें स्टेट गवर्मेंट को नहीं तो कर्जदारों को बहुत राहत मिलेगी, अभी हमारी यह सोच है।

श्रीमती रमा देवी : मैं आपके जवाब से संतुष्ट हूँ कि हमारी केंद्र सरकार बिहार सहित अन्य पिछड़े राज्यों में परियोजनाओं को सिर्फ अनुमोदित ही नहीं करेगी, बल्कि राज्य सरकार की मदद से उसे समय पर पूरा भी करेगी। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं, जो अभी भी इतनी दिक्कतों में हैं, जैसे मेरे प्रदेश बिहार में राजीव आवास योजना के तहत वर्ष 2013-14 में 29 परियोजनाओं की डी.पी.आर. तो आयी, परंतु 1 जुलाई, 2014 तक मात्र सात डी.पी.आर. को ही अनुमोदित किया गया है। इसके लिए अब कैसे आप चिट्ठी भेजिएगा, कैसे काम करवा लीजिएगा, यह हम जानना चाहते हैं? केंद्र सरकार तो मदद करती ही है, लेकिन अगर हमारी राज्य सरकार उसे पूरा कर दे तो हमारी जो जरूरत है, वह पूरी हो जाएगी और गरीबों की जो बस्तियां हैं, उनमें गुणात्मक सुधार हो जाएगा। जैसे मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर है, बिहार में गरीबों की जो बस्तियां हैं, कुल आबादी के हिसाब से बिहार सरकार में कितनी परियोजनाएं हैं, यह प्रस्ताव सरकार के पास

आया है और इसमें कितनी परियोजनाओं को स्वीकृतियां मिली हैं या कितनी परियोजनाएं स्वीकृति की प्रतीक्षा में हैं, लंबित हैं, यह हम जानना चाहते हैं?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : महोदया, जो दूसरा सप्लिमेंट्री है, उसमें दूसरा भाग स्पेसिफिकली अपने क्षेत्र के बारे में है। मैं जानकारी इकट्ठा कर के माननीय सदस्य को कनवे कर दूंगा।

दूसरा, जहां तक बात है कि केंद्र जो पैसा देता है, वह पैसा सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां की प्रगति कितनी है, उसके बारे में डिपार्टमेंट स्टेट लैवल पर हमेशा इसके बारे में समीक्षा करता है और स्टेट्स को मोटिवेट किया जाता है। जो उनकी पर्फामेंस होती है, उस हिसाब से हम पैसा देते हैं। कारण यह है कि जो पर्फामेंस अप टू मार्क नहीं है, तो हम स्टेट से कहते हैं कि आप पर्फामेंस इंप्रूव करो, क्योंकि, आपको ज्यादा फायदा होगा। इसी हिसाब से स्टेट और सैंटर को मिल कर काम करना होता है। केंद्र के द्वारा कोई दबाव डाल कर कुछ काम नहीं हो सकता है। यहां से हम केवल सैंक्शन कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, मगर इंप्लिमेंटेशन पार्ट स्टेट को देखना पड़ेगा।

श्री नाना पटोले: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ये राज्य सरकार से संबंधित होते हैं। केंद्र सरकार का रेल मंत्रालय हो, रक्षा मंत्रालय हो या केंद्र सरकार की अन्य बहुत सी जगहों पर भी झुग्गी-झोंपड़ियां बड़े पैमाने पर स्थापित हुई हैं। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की जगहों पर हों या केंद्र सरकार की जगहों पर झुग्गी-झोंपड़ियां हों, उनका पुनर्वास करने के बारे में केंद्र सरकार की क्या योजनाएं हैं? मुंबई में एस.आर.ए. के माध्यम से झोंपड़ियां बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं, बिल्डरों के माध्यम से उनको और बढ़ाया जाता है, बिल्डिंग नहीं बनती, झोंपड़ियां बनती हैं। ऐसी पॉलिसी के लिए, क्योंकि, मुबई जैसे शहर को हम शंघाई बनाने का सोचते हैं, लेकिन मुंबई शहर आज झुग्गी-झोंपड़ियों का शहर बनता जा रहा है।

महोदया, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहूँगा कि केन्द्र की जगह हो या राज्य सरकार की जगह हो, पुनर्वसन के लिए और शहरों को अच्छा बनाने के लिए केन्द्र सरकार की क्या पॉलिसी है?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : महोदया, यह बहुत कठिन समस्या है। यह आपको भी अवगत है और पूरा सदन भी इससे अवगत है। लोग गाँवों से शहर की ओर आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि एजुकेशन, इंप्लायमेंट, इंटरटेनमेंट, इकॉनामिक अपार्चुनिटी शहर में ज्यादा हैं, इसलिए गाँवों को छोड़कर शहर में आना स्वाभाविक बन गया है। लोग शहर में आएं तो उनको बसाने के लिए तुरन्त मकान उपलब्ध कराना किसी प्रदेश सरकार के लिए आसान नहीं है, ऐसा सम्भव भी नहीं है। इसलिए जहाँ जमीन है, स्थानीय जमीन है तो प्राइवेट वाले रखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की जमीन है तो स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, मगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर

अंडरटेकिंग्स की जो जमीन है, जैसा कि महानुभाव ने रेलवे, डिफेंस के बारे में कहा, वहाँ कोई व्यक्ति खड़े होकर उनको नहीं रोकेगा, इसलिए लोग वहाँ आकर बस रहे हैं, यह वास्तविकता है। इन लोगों को वहाँ से हटाना है या नहीं हटाना है, मानो कुछ इलाकों में रेलवे ट्रैक के दोनों साइड में लोगों ने अपना-अपना मकान बनाया है, जबकि रेलवे उनको हटाने के लिए प्रयास कर रहा है। लोग आकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, कलेक्टर से, स्टेट गवर्नमेंट से और हमसे भी आकर मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें वहाँ रहने दीजिए, वहाँ वर्टिकल बिल्डिंग बनाइए। रेलवे लाइन के इस तरफ और उस तरफ वर्टिकल बिल्डिंग बनाना प्रैक्टिकली सम्भव नहीं है। इस विषय का थोड़ा अध्ययन करने के बाद मैंने रेलवे मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय और केन्द्र सरकार की जो अन्य एजेंसीज हैं, उन सबके साथ एक प्रिलिमनरी मीटिंग की, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक फार्मूला नहीं बन पाया है, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ। इसका कारण यह है कि यह इतना आसान नहीं है। कोई भी विभाग अपनी जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वे लोग कह रहे हैं कि अगर आप इसको स्वीकार करेंगे तो लोग आगे भी ऐसा ही करेंगे। इसका समाधान क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ और सबसे बातचीत कर रहा हूँ। मकान के निर्माण के सन्दर्भ में स्लम डेवलपमेंट के बारे में जो माननीय सदस्य ने पूछा है, उसके बारे में मैं कहूँगा कि मैं महाराष्ट्र जाकर उस समय के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी से भी मिला, बाद में अभी नये मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की। जहाँ-जहाँ बड़े शहर हैं, वहाँ ज्यादा स्लम्स हैं। मैक्सिमम जो मुंबई में धारावी स्लम है, वह तो एशिया का बिगेस्ट स्लम है। वहाँ मकान निर्माण करने के लिए कुछ शुरूआत हुई है। उस शुरूआत में कुछ अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। जोशी जी के जमाने में भी आया, पृथ्वीराज जी या उसके पहले जो भी थे, कांग्रेस के जमाने में, बीजेपी-शिवसेना के जमाने में कुछ प्रगति हुई। वहाँ उन्होंने स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। इसमें एक कठिनाई आ रही है, मैं उसे हाउस से भी शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ-जहाँ इन बस्तियों का निर्माण हो रहा है, वहाँ वे लोग स्वेच्छा से नहीं रह रहे हैं, कुछ लोग उनको मैनेज भी कर रहे हैं। हिन्दी में उन्हें क्या कहते हैं, मुझे मालूम नहीं है, कुछ दमदार लोग इसके ऊपर कन्ट्रोल कर रहे हैं, दबंग लोग कन्ट्रोल कर रहे हैं।...(व्यवधान)

Hon. Madam, if there are some good advices from the hon. Members, I will be willing to take them into consideration and discuss them. I am already discussing it with the State Government also. There is not a simple or easy solution for it. Otherwise, I would have found a solution for it. Removing people is a problem and then construction of building there is also a problem. So, we are engaged in discussion with the respective State Governments to see that the new

slum rehabilitation policy or development policy will be launched soon as a part of National Housing Mission for all, both for urban areas and rural areas.

Hon. Prime Minister advised us that instead of coming up only with the urban housing programme let there be a programme for rural people also so that we will be able to achieve our aim of housing for all by 2022. That is the direction in which we are moving. I will definitely be sharing it with the House during the next session once the approvals are obtained and finally the things have been done.

माननीय अध्यक्ष : बहुत अच्छा, मंत्री जी ने बहुत प्रमाणिकता से बात सामने रखी है।

SHRI V. ELUMALAI: Madam Speaker, in the answer itself the hon. Minister agrees that the slum population in the country has increased from 5.23 crore in 2001 to 6.55 crore in 2011, *i.e.,* an increase of 25 per cent in the population of slum people.

Madam, may I know from the hon. Minister the steps taken by the Government to control the migration from rural areas to slum in the urban cities?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Madam, it is not that much simple, but the only thing is that we have to take care of the people's welfare in the rural areas also effectively with regard to education, employment, entertainment and better health facilities. Then only, they will stop going from rural areas to urban areas. That is a long term plan and one has to apply his mind. That is why, the Government of India is trying to focus its attention on providing proper infrastructure and basic facilities in the rural areas.

At the same time, you cannot send back the people, who have come to the cities, to their villages. That being the case, we have to take care of the people who are coming to urban areas also. That is why, in the recent meeting with Secretaries of Municipal Administrations, we have told them to prepare a plan for development of that particular city up to 10, 15 or 20 kilometres for the next 20 years and keep certain areas which will be available for housing also because housing is an important critical component in everybody's life. That is the direction in which we are working.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि पिछली केन्द्र सरकार ने जवाहरलाल नेहरू पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत आवास योजना में महाराष्ट्र के पिंपरी-चिचवाड़ शहर के लिए आर्थिक सहायता के तौर पर इस योजना के तहत 500 करोड़ से ज्यादा धनराशि दी थी, लेकिन यह योजना अभी तक अधूरी है। कई मकान बनाए गए हैं और कई अधूरे हैं। इस योजना का अभी तक गरीब परिवारों को कोई लाभ नहीं पहुँचा। महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवाड़ शहर में जवाहरलाल नेहरू पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत खर्च हुए आवास योजना की क्या केन्द्र सरकार जाँच करेगी?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : अध्यक्ष जी, यह एरिया स्पैसिफिक क्वैश्चन है। मैं पूरी जानकारी इकट्ठा करूँगा। उसमें कुछ गलत हुआ या दुरुपयोग हुआ तो तभी हम जाँच के बारे में सोचेंगे। पहले एक्ज़ैक्टली स्थिति क्या है, मैं यह समझने की कोशिश करूँगा और उसके बाद क्या करना है, वह तय करूँगा और मैं माननीय सदस्य को भी वह जानकारी दूँगा। वे बता रहे हैं कि 500 करोड़ रुपये दिये हैं, लेकिन मेरे ख्याल से किसी एक शहर के लिए 500 करोड़ रुपये मंज़ूर करना प्रैक्टिकली संभव होता नहीं है, वह पूरे स्टेट के लिए होगा। फिर भी उन्होंने कहा है तो मैं पूरी जानकारी इकट्ठा करके माननीय सदस्य को भी बता दूँगा और आगे क्या करना है, वह निर्णय करूँगा।

SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, the hon. Minister has mostly covered the whole arena of issues. He has very rightly said that land and colonisation are State subjects. One of my friends raised a question in respect of the defence land and the railway land. I want to ask only one question that when you are making a scheme – we have read it in the Presidential Address – Housing for All, will it cover the persons who are residing in the [illegible] areas on land belonging to the Railways and the Defence? What is your scheme?

You have said that the figure has increased. Is the Central Government going to increase financial assistance to the States for this project in the slum areas or not?

श्री एम.वैंकैय्या नायडू : अध्यक्ष जी, यह अच्छा सवाल है। सचमुच में कारण क्या है कि उनको वहाँ से अपने-अपने विभाग वाले हटाना चाहते हैं, मगर हटाकर उनको कहाँ रखना है, यह काम स्टेट गवर्नमैंट को देखना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमैंट को देखना है तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं है। इसलिए आपका जो सवाल है, उससे मैं सहमत हूँ कि लोगों को पब्लिक लैंड से, डिफैन्स लैंड से, रेलवे लैंड से या बाकी और

कुछ इलाकों में जहाँ वे बस रहे हैं, वहाँ से उनको हटाना है तो उनको आल्टरनेटिव अकोमोडेशन देना स्टेट का कर्तव्य है, मगर स्टेट को मदद करना सैन्टर का कर्तव्य है। जो हाउसिंग फॉर आल के बारे में आपने पूछा, उसमें जो लोग विस्थापित होंगे, the people, who will be displaced from the government land, will be given priority.

(Q.No. 22)

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN : Madam, I am extremely happy that the hon. Minister of Communications and Information Technology has launched National Optical Fibre Network at Idukki in the State of Kerala, making it the first district completely covered and connected by optical fibre. There was an assurance, at that time, by the hon. Minister that Kerala would be the first State to be fully covered by optical connectivity under the National Optical Fibre Network (NOFN) scheme by March 2015. I am very happy about the assurance. Assuming that the Government meets the target on time, I wish to know this. Who will be the service providers across the country -- and especially in Kerala -- where BSNL is running at a huge profit?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : Madam, the hon. Member is right that Idukki was the first District where I inaugurated NOFN in the presence of the Chief Minister and the Leader of the Opposition because this programme is a national programme. Our Prime Minister has been kind enough to say that 'Digital India' is more for the poor and underprivileged. Therefore, we propose to connect all the 2,50,000 Gram Panchayats of India within a time span of three years, and this fiber connectivity through NOFN would lead to a lot of services in e-education, e-health, e-entertainment and e-commerce creating a lot of business opportunities, employment opportunities and also empowerment. Therefore, the 'Digital India' programme, which is a Mission-mode programme, NOFN is an integral part of it.

As regards your specific question, let me tell you that this will be a non-discriminatory platform whereby anyone can plug in either for e-education, e-health, e-commerce or e-entertainment or any kind of information services. Madam Speaker, I want to share this with the hon. House that empirical studies show that wherever rural population has been more connected through broadband, it has led to greater growth. I just want to convey to this hon. House that smart-phone has got the biggest consumption in India after America. I see that once NOFN comes about barbers, carpenters, masons looking for their job opportunities

with this kind of platform being available would be empowered and warehouses for e-commerce, would be enabled.

As regards Kerala, Yes, BSNL is there. Hon. Member, you are a very senior Member. I want to inform this House that we have increased the speed 30 times more in comparison to the previous year, and by the end of this year not only Kerala, but Karnataka, Haryana, Punjab, Chandigarh and Puducherry will be provided with high speed internet through NOFN with the kind of speed that they are maintaining and also doing for other parts of the country.

I cannot say that only BSNL will take the call. A platform will be available through the by Government user network from the Blocks through the Gram Panchayats, and thereafter all the services will be available. It can be BSNL and it can be any other services. The idea is to reach every rural household.

SHRI MULLAPPALLY RAMCHANDRAN : Madam, it is well known that the 'Digital India' Mission launched by the hon. Minister is a continuation of the National Optical Fiber Network project launched by the UPA Government in 2011. The target of the Mission is to provide, as you rightly put, connectivity to all the 2,50,000 Gram Panchayats across the country by December 2016.

This being the case, I wish to know this. Does the Government intend to complete the project within the stipulated timeframe through BSNL in coordination with NHAI or does the Government intend to bring in private players in the process?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD : Madam Speaker, Yes, I admit that this programme of NOFN was initiated by the previous Government. But when our Government came to power, it was converted into a Mission-mode programme as a part of 'Digital India'.

I would just like to share one statistic. In one-and-a-half years, 2,000 kms. of fiber was laid down, and after we have come to power, as on 22 January, 32,855 kms. of PLB ducts and 18,444 kms. of cable have been laid down in only seven months. Therefore, 30 times speed has been increased.

As regards the implementation part, as you have very rightly pointed out, once this whole thing comes about, it is a national programme where the Central Government, the State Government, the local bodies -- all have to play a part, and this being a pro-growth platform being available for the rural India, I see a lot of incremental services building upon it. Yes, you are right, it is a big mission. I want to just convey to this House that ten lakh kilometres of fibre network was laid in India in 25 years, but our Government is going to lay seven lakh kilometres of fibre network in three years. That is the kind of mission that we are going to have. With the cooperation of all, we will surely do it.

SHRI K.C. VENUGOPAL : Following the Digital India programme, the Government is all set to launch high speed Internet connectivity in the Indian villages. I do appreciate the stand taken by the hon. Minister that it is a continuation of the programme launched by the UPA Government. At this time, I would like to respectfully remember the name of the late Shri Rajiv Gandhi, who brought communication revolution in our nation.

I would like to know one thing from the hon. Minister. Already, Shri Mullappally Ramchandran pointed out the difficulties being faced by BSNL. At present, the Government has proposed to take up the programme through public enterprises like BSNL in a State like Kerala. However, has the Government noticed the customers' disillusionment with the functioning of the Company? Long time users of the network cite a fall in service levels in recent times, from frequent call drops to Internet connectivity issues. The employees point out that the issues related to the shortage of equipment has prevented the Company from upgrading its service to meet the increasing customer base.

How does this Government propose to set up such a massive digital programme with poor connectivity and network problems? I would like to know whether the Government has proposed any stringent measures to overcome the problems.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, a specific query about BSNL should not be a part of this, but since a senior hon. Member has asked me this question, I would like to share with him that it is a fact that BSNL is in problem. I wish to say with full sense of responsibility that, in the last seven or eight years, the kind of treatment given to BSNL certainly left much to be desired. Under the instructions of the Prime Minister, restoring the health of BSNL has been one of the priority areas of our Government. In the seventh phase programme, I want to convey that 27,000 new towers are going to be installed by this year end by BSNL – 11,000 towers for 3G and 16,000 towers for 2G. The total cost is going to be Rs. 4,804 crore, all to be generated by BSNL itself. Similarly, at a cost of Rs. 1,050 crore, the existing landline network of 14 million lines is going to be upgraded to the next generation network. I am personally monitoring it.

However, as far as NOFN is concerned, the larger issue is that it is being implemented by BSNL, RailTel and also by Power Grid. Many State Governments have come up with their own models. The Andhra Pradesh Government has said that they want to go further and they are quite open to other models as well. The larger objective is also to bring in other models to make NOFN a big success which, indeed, is a national programme.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के 'डिजीटल इंडिया' कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार का सपना देश भर में ब्रॉडबैण्ड की पहुंच को आसान बनाना है। जैसे आज केबल टी.वी. घर-घर पहुंचा है, वैसे ही ब्रॉडबैण्ड को भी घर-घर पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय को उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के संबंध में बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना विविधताओं से भरी हुई है। वहां विंध्याचल के पहाड़ हैं, बुंदेलखण्ड के पहाड़ हैं, सतपुड़ा के पहाड़ हैं और चम्बल के बीहड़ हैं। ऐसे स्थानों पर राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नहीं होने पर, वहां जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं की समय पर सूचना नहीं पहुंचने के कारण कई बार लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए। बुंदेलखण्ड का जो हमारा इलाका है, वहां

पास के राज्यों से अपराधी आकर घटनाएं घटित करके चले जाते हैं और समय पर पुलिस नहीं पहुंच पाती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो 1613 ब्लॉकों में से 1275 ब्लॉकों में कार्य प्रारंभ किया गया है तो क्या मध्य प्रदेश के इन विशिष्ट स्थानों को चिन्हित करके इसी चरण में उन पंचायतों को भी राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा?

श्री रवि शंकर प्रसाद : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बहुत विनम्रता से सूचित करना चाहूंगा कि हमारी सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है। हम देश के पूरे ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना चाहते हैं। यह तीन चरण में होगा। मैंने अपने विभाग को यह निर्देश दिया है कि इस बात की भी चिंता करें कि अगर गति को आगे बढ़ाने के लिए तीन चरणों को दो चरणों में करना हो, जैसा कि प्रधान मंत्री जी का निर्देश है, वह भी करने की कोशिश करें। ऐसी ग्राम पंचायत, जहां पहाड़ी या दुर्गम इलाके होने के कारण फाइबर लगाने के कार्य में कठिनाई है तो मैंने अपने विभाग को यह निर्देश दिया है कि वैकल्पिक तकनीक के माध्यम से उसे भी जोड़ने का प्रयास करें। जैसे मैंने इदुक्की की बात की, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि मेरे लिए जीवन का वह सबसे बड़ा क्षण था, जब तिरूअनंतपुरम में मैंने उस आदिवासी गांव के सरपंच से बात की, जहां से सड़क 18 किलोमीटर दूर है। हम तकनीक के माध्यम से उनसे बात कर पाए। आपने जो सुविधा, स्वास्थ्य और शिक्षा की बात कही, उसी के लिए एन.ओ.एफ.एन. है कि हम ई-एजुकेशन, ई-हेल्थ, इन सारी बातों को दे सकें। आपने अपने विशेष इलाके बुंदेलखंड की बात कही है, मैं स्वयं देखूंगा कि वहां पर गति को त्वरित करने के लिए और क्या कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA : Thank you Madam for giving me an opportunity to speak on this occasion. The hon. Minister has elaborately answered on the broadband connectivity provided to the country. It is a dream of the Prime Minister that India should become digital in a few years.

In my constituency, Araku, which is a remote area in Andhra Pradesh, we are facing a serious problem of connectivity which is mainly affecting the minimum amenities like health, education and infrastructure. The people of my constituency are facing a lot of hardships. Even in the Government offices which are now connected with broadband 3-G internet are not functioning and the officers have to come to the plain area to operate the internet to give small

administrative certificates to the people. Even today, my constituency is not having 20 per cent connectivity.

I would like to ask the hon. Minister if the Government is working out a strategy for providing connectivity. For the last two decades, many private providers have also come to this area to provide connectivity but unfortunately, connectivity was not provided in this area.

So, I would also like to ask the hon. Minister if there is any action plan or any stringent measures to provide connectivity in such hilly areas in my constituency.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Madam, since the hon. Member comes from the State of Andhra Pradesh, I had a very elaborate meeting with hon. Chief Minister. I had gone to Hyderabad. Hon. Chief Minister Shri Chandra Babu Naidu has come with an idea of further taking it to all the villages and to all the households. He has come with a model which we have approved in principle in Telecom Commission. We are going to work upon it.

We are going to all other Chief Ministers that if the Andhra Pradesh model as suggested becomes a success model, other State Governments can also work on it. NOFN programme, as the PM has directed me, is a non-political, non-discriminatory national programme where the State and the Centre have to work together.

Madam, you talked about cable. I was drawing upon my experience as the former Information and Broadcasting Minister, I had told my officers to please work with the cable operators as to whether they can give broadband. I am very happy to inform that they have become very excited by tweaking of technology through the cable network and we can give broadband to various areas. As far as other specific problems of that constituency are concerned, I will look into them.

(Q.No.**23)**

श्री केशव प्रसाद मौर्य : महोदया, देश की सुरक्षा और विकास से जुड़े स्वदेशी उपग्रह के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न पूछने का आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदया, स्वदेशी उपग्रह के सम्बन्ध में मैंने दो-तीन दिनों में जानने का प्रयास किया है। हमारे देश में स्वदेशी उपग्रह लगातार लॉच किए जा रहे हैं। हमारे मंगलयान के कारण से पूरी दुनिया के अन्दर भारत की क्षमता का प्रदर्शन हुआ। हम विश्व में इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। एक जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि पिछले दिनों हमारी सेना के अंदर, यह बहुत संवेदनशील क्षेत्र है, एक ह्यूज नाम की अमेरिकन कम्पनी है, उसको सी.एस.डी., मतलब सेना के जो कैंटीन स्टोर्स होते हैं, उन स्टोर्स के लिए इस कम्पनी को ठेका दे दिया गया। अगर अपने देश की किसी कम्पनी को ठेका देते, तो हमारी जानकारी देश के अन्दर ही रहती, लेकिन अब वह जानकारी अमेरिकन कम्पनी को प्राप्त हो रही है।

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो हमारी क्षमता है, कई प्रकार की क्षमता है, जैसे के. बैंड है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। पिछले प्रश्न में ही यह विषय आया था कि स्मार्ट फोन हमारे देश में बड़ी संख्या में बढ़ गए हैं।

महोदया, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि चाहे गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, सबके हाथों में मोबाइल फोन है लेकिन हम डी.टी.एच. (डायरैक्ट टू होम) डिलीवरी की जो सेवा दे सकते हैं, हम उसे देने का काम नहीं कर पा रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि हमारी उपग्रहों की जो क्षमता है, हमारी 'के-बैण्ड' की जो क्षमता है, उस क्षमता के माध्यम से क्या हम डी.टी.एच. सेवा मोबाइल पर भी उपलब्ध करा सकते हैं? क्या 'के-बैण्ड' की पूरी क्षमता का उपयोग हो रहा है?

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, पिछले दिनों स्पेस और उससे संबंधित जो अनेकों पहल हुई हैं उनको लेकर आदरणीय सदस्य ने कुछ चिन्ता भी जताई है और कुछ सुझाव भी दिये हैं। मैं इनके प्रश्न का सीधा-सीधा उत्तर देने से पहले यह कहना चाहता हूं I have the pleasure and pride to share with this august House that notwithstanding all the other apprehensions expressed by the hon. Member, in recent times and particularly in the last seven to eight months, India has made rapid strides in the area of space technology. While, on the one hand, India aspires to become a world power in the next few years or decades, we can very rightfully claim that India has already become a world leader in the area of space.

Having said that, let me also because I wish to start the answer to this question on an optimistic note, say that the success story in the present year began in the month of June when we had the privilege and honour of launching five commercial satellites from some of the most advanced countries of the world. I wrote a small note that with this, India has entered into the area of space marketing. … (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Is it started by this Government?

DR. JITENDRA SINGH: No, it is an on-going process. I am not denying that, certainly not. But my job today is to just put the record straight in the interest of the national achievements.

In the same way, as far as the Mars Mission is concerned, at least to me, it appears that we have made a significant headway on three counts. Firstly, the world today knows our capability which is totally indigenous. It has, in fact, become the most significant symbol of the 'Make in India' concept – the Indigenous Mars Mission. Secondly, it has paved the way for future space missions. Thirdly and very importantly, it has given us a huge strategic importance, a strategic advantage over other countries.

Now coming directly to what the hon. Member has pointed out, I also have the pride and satisfaction to share that another landmark is going to be recorded just ten days later, that is, on the 9th of March. We have what is known as the Indigenous Regional Navigation Satellite System (IRNSS), which is going to be directly related to the question and the apprehension put forward by the hon. Member. Under this programme, we have planned launching a series of seven satellites. Three have already been launched; they are already in the space. The fourth one will be launched on the 9th of March. Why I call it landmark is that once four satellites are in place, the navigation, the communication process will take a huge jump and all these issues put forward by him will begin to be addressed. In another year or so, when there are another three satellites and we

have seven satellites, we would also have the other communication problems taken care of. We are certainly way ahead of several other nations.

Let me also point out, as far as the specific K Band issue is concerned, we already have 95 KU Band transponders in place. Right now, India has 27 satellites in space. Out of them, as many as 11 are dealing with communication, to which the hon. Member has pointed out. With the IRNSS coming in, we will have further enhancement. The DTH is also being adequately taken care of. In addition to communication, we are also taking care of the other aspects. We have 12 satellites looking after the geo-observation applications. We have three navigation satellites.

Not only that, as was also pointed out by hon. Prime Minister during one of the visits to Sriharikota, we are also on way to assuming a leadership role in the SAARC countries by way of a SAARC satellite. When this IRNSS, which I was pointing out a few moments ago, becomes operational on March 9, it will offer services also to other parts of the subcontinent and Southeast Asia. … (*Interruptions*) I am not denying what the other Government has said. I am only trying to take humble credit for having carried forward in right earnest, right honesty, what was expected of us.

श्री केशव प्रसाद मौर्य : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी का देश के लिए बहुत संतोषजनक उत्तर आया है। अपने वैज्ञानिकों और माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देते हुए मेरा एक और प्रश्न है। हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहे हैं। इस प्रगति से देश का विकास और देश की सुरक्षा दोनों जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में रोजगार की कितनी संभावना है? दूसरा, हमारे देश की पूर्ववर्ती सरकारों के जैसे भी काम रहे हों, मैं उन पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के कारण नासा सहित दुनिया के अनेक अनुसंधान केन्द्रों पर हमारे देश के तमाम वैज्ञानिक वहां जाकर शोध का कार्य कर रहे हैं। अगर दुनिया में नासा जैसे तमाम अनुसंधान केन्द्रों का डंका बज पाया है तो उसमें भारतीय प्रतिभाओं का बहुत योगदान है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे देश के ऐसे कितने वैज्ञानिक हैं, जो विदेशी अनुसंधान केन्द्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? आने वाले समय में हमारे देश की प्रतिभाओं को पलायन न करना पड़े, वे देश के लिए काम करें, देश की सुरक्षा, देश के विकास के लिए उनकी प्रतिभा का उपयोग हो सके, इस संबंध में सरकार की क्या योजना है? देश की सुरक्षा बड़ी चुनौती है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, जैसे आदरणीय सदस्य ने कहा, यह सत्य है कि वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह प्रत्येक क्षेत्र में होता है, विज्ञान के क्षेत्र में अधिक होता है, भले ही वह फिज़िक्स विज्ञान हो या चिकित्सा विज्ञान हो। परन्तु यह कहना उचित नहीं होगा कि इसमें केवल हम अपने लाभ के लिए जाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि इस आदान-प्रदान के परिणामस्वरूप विदेश के वैज्ञानिकों को हमसे लाभ मिला है और हमारे पास जो रिसोर्स मैटीरियल और इन्फ्रास्ट्रक्चर है, we have a huge, huge experiment provision. साथ ही इसमें यह बात भी जोड़ दूं, because this is evidence-based age I do not wish to sound in a generalized manner and will give you a couple of examples. हाल ही में चंद्रयान-II, हालांकि वह इस विषय से सीधा जुड़ा नहीं था, आपको स्मरण होगा, चंद्रयान-II का लॉन्च थोड़ा डिले हो गया, यह प्रश्न भी उठ सकता है। उसके पीछे जो कारण है, उससे शायद हमें कहीं न कहीं थोड़े संतोष का एहसास हो, क्योंकि Chandrayan-II was planned as a part of a joint Indo-Russian venture. परन्तु उसी दौरान रूस का एक और मिशन विफल हो गया and Russia went on the back foot. Therefore, we started afresh doing it all on our own. In other words I wish to say that even as a consequence of this interaction or frequent exchange of the scientists between the two countries, we are not at disadvantage, we are at advantage. Now we have a number scientists coming over to India to study. In fact, the commercial satellite launching which I referred to, उसमें यह हुआ कि जो छोटे वज़न के सैटलाइट्स हैं, उन्हें लॉन्च करने के लिए बहुत से विकसित देशों को ज्यादा खर्चा पड़ता था। हमने उन्हें यह सुझाव दिया कि यदि आप हमारे यहां से लॉन्च करते हैं तो आपको खर्च कम पड़ेगा। In fact they have now started looking towards us. So, that is a very optimistic piece of information.

As far as China is concerned, because that is another country with which we had frequent interaction and interchange of the scientists, China was mostly ahead of us in launching knowledge or launching abilities whereas we were ahead in space applications. They were ahead of us in navigation. But this IRNSS, which I just referred to, would place us at par. As far as Moon is concerned, both of us are looking towards Moon. So I think we are now almost at par with most of the advanced space savvy countries of the world who began much longer before us. … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Hon. Speaker Madam, the genesis of space technology in our country lies in the year 1975 when the Aryabhatta was launched. The fact is that our space programme was started in a very humble church in South India and now a church is being vandalized in our country by religious fanatics. But the space technology was set in motion from a humble abode of a church. The Minster himself appeared to be very restive of appropriating the credit of the NDA Government insofar as space technology is concerned but the fact is, since 1975 we have been undergoing a long and arduous journey before achieving our self-sufficiency, especially for cryogenic technology.

माननीय अध्यक्ष : यह सब जानते हैं। आप अपना प्रश्न पूछिये।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: In spite of the technological apartheid imposed upon India in the wake of our nuclear explosion, we have been able to achieve cryogenic technology indigenously. Even the Prime Minister admitted that the most economical Mangalyaan was launched by our country at a cost less than the cost of a Hollywood film 'Gravity'.

HON. SPEAKER: Do you not have any question?

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: May I ask the hon. Minister what is our programme insofar as space shuttle programme is concerned including manned mission?

DR. JITENDRA SINGH: I totally endorse what the hon. Member has said and cutting short and putting his entire presentation in a single sentence, I would tell the hon. Member that certainly if 1975 had not happened, 2015 would not have happened. So, I think that is a compliment to both the sides in the House. This is an on-going process. We have carried forward in 2015 what was begun in 1975 and I think we deserve some credit for having not failed in this on-going process which cuts across the party lines.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: My question was about space shuttle programme. The question has not been answered by the hon. Minister.

माननीय अध्यक्ष : आप इतना बोले कि आपका प्रश्न इधर उधर चला गया।

SHRI TATHAGATA SATPATHY: In this madness, in this cross-fire, each one is claiming credit for something which neither of them have done, neither this side nor that side. It is some scientists sitting in the beach near Orissa or in Bangalore or in Andhra Pradesh or somewhere else, who have done the R&D and who have actually brought this country to what it is today. It is neither this side nor that side. We should stop this blame game and desperation to take credit. I agree with the hon. Minister that if in 1975 the world had collapsed, today in 2015 the world would not have existed. I would like to specifically ask from the hon. Minister what kind of payload are we able to deliver to space now. Is it economical or is it again another ego game where we are trying to claim that we are sending satellites? All the satellites with heavy payloads which are actually being used by Indian Government for weather forecasting and for television are being launched from French Guyana in South America. The satellites with lighter payloads are being delivered to space from within India. Is this going to be economically viable? Today, the world is looking at all these activities through the eyes of economic viability. Are we proposing or do we have any plan to make these payloads? With regard to the ones that we are sending ourselves through French or European agencies, are we planning to make them go to space through our own rockets? Will they be viable? When we are asking foreign countries to come and launch their satellites from our facilities, are we able to match up to international standards in economic parameters? Or, are we doing this, incurring losses on one hand where on the other hand we are not able to give even simple clean drinking water for which this country is suffering? Let this be very clear.

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये, आप कहां से कहां जा रहे हैं।

DR. JITENDRA SINGH: Madam, in the elaborate multi-part question asked by the hon. Member part of the answer is already included. But just to put things straight, with your permission, I will start from where he ended.

माननीय अध्यक्ष : आपको बाकी सब बातों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है।

DR. JITENDRA SINGH: Starting from the drinking water, of course, that is not my prerogative today to answer. But coming back to the launching side, certainly we have achieved perfection, as he was saying, at the State level. We are now way ahead of several other countries in accurately forecasting our weather and even the monsoon and disaster prophecies whether it was the Uttarakhand or the Hudhud.

Secondly, as far as the launching part is concerned, I thought I made a reference of it in the earlier question. It is true that we are launching several of our satellites from foreign launching stations and the reason being that for heavier satellites we are not yet in a position to have the launching pads. But I think what you could appreciate to an extent that we had the innovative idea of offering our launching pads to other countries for smaller size and smaller weight satellites which could generate a certain amount of economy and revenue for us. This would also refer to your concern that it would also help us generate some economy, some commerce by way of all this.

As far as the quality or the ability of our launching facility is concerned, I think the evidence lies in the fact that we have been in the last six months launching commercial satellites from countries like France and US. These are some of the countries who would not risk or hasten to jump in if they were not sure about our ability. So, we are trying to make up where we have already achieved excellence and we are trying to achieve excellence where we are yet to reach. Your concern is well taken. We are already making an earnest, honest endeavour in that direction.

(Q.No.**24**)

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने मूल प्रश्न का जो जवाब दिया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। देश में बच्चों को मध्याहन भोजन उपलब्ध कराने की जो परिकल्पना थी, वह आज सही मायने में प्रैक्टिकल नहीं रह गयी है। इस विषय पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। देश के करीब 23 राज्यों/संघ राज्यों, विशेषकर झारखंड में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 में 58,758 बच्चे कम शामिल हुए। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार के द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं?

श्री उपेन्द्र कुशवाहा : माननीय अध्यक्ष जी, यह बात ठीक है कि इस स्कीम में कुछ राज्यों में कमी आई है लेकिन यह कह देना कि मध्याह्न भोजन की स्कीम व्यावहारिक नहीं है, ठीक नहीं है। इस स्कीम के कई लाभ हैं, इस स्कीम में जो गरीब बच्चे स्कूल आ रहे हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था और भी कई आब्जेक्टिव्स हैं। तमाम ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए इस योजना को चलाना जरूरी है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष जी, देश में 38 मोनिटरिंग संस्थान इस विषय की जांच पड़ताल में लगे हुए हैं। सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा एम.डी.एम. की समीक्षा की जाती है। इसके बावजूद इस योजना के तहत विद्यालय में जहरीला भोजन परोसा जाता है। 2011 से लेकर 2014 के दौरान देश में कुल 2375 बच्चे खराब गुणवत्ता के भोजन के कारण बीमार पड़े और इसमें लापरवाही भी हुई। यह डाटा भारत सरकार का है। आज की तारीख में डिब्बा बंद भोजन ठेकेदारों द्वारा विद्यालयों में दिया जा रहा है। आप समझ सकती हैं कि यह कितने दिन पहले बना, कहां बना। इसकी स्थिति अखबार के माध्यम से बताई गई है कि विद्यालय में कोई बच्चा इसे खाने के लिए तैयार नहीं है। यह कई बार एक्सपाइरी डेट का भी होता है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न पूछिए। प्रश्न एक वाक्य में पूछते हैं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : रसोइसा, सेविका और सहायिका भोजन बनाने में लगे हैं उनके द्वारा पहले भोजन बनाने की व्यवस्था थी, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस परियोजना में है कि अब उनको इससे वंचित किया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार वर्तमान में एमडीएम की पैकेट भोजन आपूर्ति रोकने के लिए सेविका, सहायिका द्वारा फिर से पहले की तरह भोजन व्यवस्था की शुरुआत करेगी? इसमें जो शिक्षक लगे हुए हैं, उनका आधा समय भोजन को देखने में गुजर जाता है। अगर कोई चीज इसमें गिर गई तो उसकी सारी जिम्मेदारी टीचर, सेविका और सहायिका पर होती है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय सदस्य से कहना चाहती हूं कि राष्ट्र में मध्याह्न भोजन की स्कीम के बारे में इस सभा में कह

देना कि जहरीला भोजन बच्चों को परोसा जा रहा है, यह अपने आप में गलत होगा।...(व्यवधान) केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर मध्याह्न भोजन स्कीम की मॉनिटरिंग करती है। मैंने स्वयं सभी माननीय सदस्यों को जुलाई 2014 में एक पत्र के माध्यम से निवेदन किया था कि डिस्ट्रिक्ट स्तर पर अपनी कांस्टीटुएंसी के जिले में मध्याह्न भोजन किस प्रकार से पकाया जाता है, परोसा जाता है, इसके बारे में स्वयं वहां जाकर अपने आपको अवगत करा सकते हैं।

मैं आपके माध्यम से सभा से निवेदन करना चाहती हूं कि हमें प्रदेश से जब सूचना आती है कि मध्याह्न भोजन के माध्यम से कहीं न कहीं कोई चुनौती प्रस्तुत हुई है तब प्रदेश स्वयं कार्रवाई करके केंद्र सरकार को अवगत कराता है। माननीय सदस्य का विशेष चिंतन रहा है कि सेफ्टी पैरामीटर्स को देखा जाए। मिनिस्ट्री आफ फूड, मिनिस्ट्री आफ हैल्थ और न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ एक गाईडलाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है और विशेषतः सभी प्रदेशों को आगाह किया गया है कि किस गाईडलाइन के तहत मध्याह्न भोजन बनाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस सभागार में एक बात और स्पष्ट करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जिससे हर स्टेट को अवगत कराया गया है कि मध्याह्न भोजन has to be a hot cooked and not the *dubba* meal as the hon. Member is saying. But if he has a complain he can bring it to our notice.

12.00 hrs.

HON. SPEAKER: Shri Mahtab, put a question quickly.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) ... *

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Enrolment of children in school shows that it has increased manifold. Attendance in Government schools above 90 per cent is only in three States, namely, Kerala, Mizoram and Himachal Pradesh. I would like to know whether the Government is aware that States like Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Manipur and West Bengal has attendance of less than 60 per cent. The larger issue is retention after enrolment. Will the Government make the MDM more attractive so that learning levels increase? If the Government has any plan, then they may share it with the House.

* Not recorded.

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I would like to inform the hon. Member through you that firstly as the answer reflects that in terms of enrolment into schools, if you look at the census data that has been given, you will see that birth rates have dipped in many a State… (*Interruptions*) I am answering your question in its entirety and beg your indulgence insofar as my complete answer goes.

In terms of learning outcome it is incorrect to say that it is only the MDM which will result in increase of learning outcomes. We have, in the month of August, initiated a programme called '*Padhe Bharat, badhe Bharat'* where from classes I, II and III for early reading, writing, comprehension and numerical, learning outcomes have been looked at by providing additional teaching and learning aids to the classrooms. For classes VI to VIII, learning outcomes which have dipped in the field of mathematics and science is also an area of concern for us for which additional teaching and learning aids have been given. Mid-day Meal scheme helps in addressing issues like classroom hungers, it is not aimed at addressing learning outcome enhancement in schools.

———————

12.02 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, papers to be laid.

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 42 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एस/321/23/2011 जो 29 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो नालन्दा विश्वविद्यालय परिनियम, 2012 में उसमें उल्लिखित और संशोधन किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

(Placed in Library, See No. LT 1810/16/15)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2014 जो 10 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 311-35/2014-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(Placed in Library, See No. LT 1811/16/15)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 2014 जो 5 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 873(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

(Placed in Library, See No. LT 1812/16/15)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. रामशंकर कठेरिया): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमीरपुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमीरपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1813/16/15)

(3) (एक) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इलाहाबाद के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1814/16/15)

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दुर्गापुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1815/16/15)

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़, रोपड़ के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1816/16/15)

(8) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(Placed in Library, See No. LT 1817/16/15)

(9) (एक) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(तीन) सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(Placed in Library, See No. LT 1818/16/15)

12.02 ½ hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

5th Report

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, I beg to present the Fifth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions.

12.03 hrs.

STANDING COMMITTEE ON AGRICULTURE
Statements

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं " पशुपालन क्षेत्र की रोजगार सृजन क्षमता का इष्टतमीकरण " के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 53वें प्रतिवेदन तथा कृषि मंत्रालय (पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग) की " अनुदानों की मांगों (2013-14) " के बारे में 48वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की-गई-आगे कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.03 ½ hrs.

STANDING COMMITTEE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
264th Report

डॉ. भागीरथ प्रसाद (भिंड) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक, 2014 के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 264वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

12.04 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE
Court of University of Delhi

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Madam, I beg to move:

> "That in pursuance of Statute 2(1) (xix) and (3) of the Statutes of the University of Delhi, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Court of University of Delhi, subject to the other provisions of the Statutes. The members so elected shall not be the employees of the University of Delhi or of a recognized college or Institution of that University."

HON. SPEAKER: The question is:

> "That in pursuance of Statute 2(1) (xix) and (3) of the Statutes of the University of Delhi, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the Court of University of Delhi, subject to the other provisions of the Statutes. The members so elected shall not be the employees of the University of Delhi or of a recognized college or Institution of that University."

The motion was adopted.

12.05 hrs.

MOTION RE: ELEVENTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा 24 फरवरी, 2015 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

HON. SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Eleventh Report of the Business Advisory Committee presented to the House on 24th February, 2015."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Now we may take up 'Zero Hour'.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Madam Speaker, I wish to draw the kind attention of the House to a serious matter.

I urge upon the Government to repeal the Unlawful Activities (Prevention) Act without further delay.

The aim and objective of this Act was to curb unlawful activities. But it is quite unfortunate that this law has been misused like anything and it is dangerous than POTA and TADA. It is reported that thousands of people are in jails. They have not done anything anti-national and it is because of the misuse of this Act. Everybody can imagine the pathetic condition of these people and the ill-affected families. This law gives freedom to the police on interpreting or defining as to what exactly are terrorism and unlawful activities. They do it according to their own will and pleasure. Unfortunately, nobody can agree with this.

Madam, this is a black law. I agree that we must fight terrorism at any cost but a law made for fighting terrorism cannot be misused for victimization. This House is having a great tradition of making clean and historic legislation. But this is a black law. With all politeness, I wish to say that we are duty-bound to repeal this black law. I urge upon the Government to withdraw or repeal this anti-democratic law.

Regarding UAPA, I wish to say one more point. The Government should repeal it forthwith. A judicial review on all the cases charged under UAPA may be reviewed forthwith.

With this humble submission, I conclude.

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Madam Speaker, with your permission, I would like to draw the attention of the Minister for Home Affairs to a serious issue.

We all take pride of our glorious history especially of the Indian National Army, INA, and the Azad Hind Fauj Government of Netaji Subash Chandra Bose.

Madam, I may be permitted to read from a circular which has been issued by the Home Ministry. This is a copy of a letter sent to a lady who is 85 years old, a widow of an INA veteran. In this letter, it has been said:

> "You are, therefore, requested to appear in person alongwith the following documents before the undersigned in the first or second week of December, 2014 on any working day in Second floor, NBCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi."

Madam, this letter has been sent to a lady of my constituency living in Kadakkavur of Thiruvananthapuram. She is 85 years old. She cannot travel at this age. It is highly humiliating to the INA veteran to ask his wife to come to Delhi for physical verification alongwith the documents. The Government of India should definitely give a direction to the concerned Section Officers and the Secretaries that the verification should be done at the concerned District Collector's Office.

If it is necessary they can put the web camera there and they can verify the person and verify the documents. This is highly humiliating to the INA.

माननीय अध्यक्ष: शून्य काल में कोई उत्तर नहीं मिलता है। आप अपनी बात कह सकते हैं और आपने वह कह दी है इसलिए अब आप बैठ जाएं। श्री रवनीत सिंह।

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): We cannot humiliate the INA veterans. That lady has written a letter to me requesting that I have to forward this letter to the Speaker herself. She is saying that she is very aged, she is 85 years old and that she is suffering from various illnesses. She cannot visit Delhi. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: In 'Zero Hour' I cannot ask the Minister to respond. Let him write to the Minister.

Sarva Shri N.K. Premachandran, P.K. Biju, Innocent Jose K. Mani, Joice George and M.B. Rajesh are allowed to associate themselves with the matter raised by Dr. A. Sampath.

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सन् 1988 में नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अधीन एक योजना देश के 12 जिलों में शुरू की गई थी, जो आज 271 जिलों में चल रही है। यह योजना यूपीए सरकार की देन थी। इस योजना के तहत देश में 6000 स्कूल्स में करीब दस लाख ऐसे बच्चें पढ़ रहे हैं जो पहले बाल श्रमिक के तौर पर ईंट भट्टों पर, चाय की दुकानों पर, कारखानों और उद्योगों में काम कर रहे थे। उन्हें पढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। लेकिन इन स्कूल्स में जो अध्यापक काम कर रहे हैं, उन्हें 1 साल से वेतन नहीं दिया गया है। हम लोगों को यह चिंता है कि कहीं ऐसा न हो कि ये स्कूल बंद हो जाएं और जो दस लाख बच्चे इनमें पढ़ रहे हैं, वे फिर से चाय की दुकानों, फैक्टरीज आदि में काम करना न शुरू कर दें। मैं पंजाब की बात करूं तो वहां लुधियाना में इस तरह के 40 स्कूल्स हैं और उनमें 200 टीचर्स हैं। मैंने खुद तीन स्कूल्स को विजिट किया और देखा कि वहां दर्दनाक स्थिति है। यूपीए सरकार ने 2013-2014 के वित्तीय वर्ष में 55 लाख रुपए भी पंजाब को दिए, लेकिन डेढ़ साल हो गया, उन टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली है। अमीर और गरीब के बीच जो यह खाई है, उसे भरना जरुरी है। यह देश गरीबों के लिए भी बराबर का है और उनके लिए भी स्कूल्स बने हैं उनका चलना जरूरी है। मेरा लेबर मिनिस्टर जी से निवेदन है कि इन स्कूल्स के टीचर्स को तुरंत वेतन का भुगतान किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भगवंत मान, श्री राजीव सातव को श्री रवनीत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. UDIT RAJ(NORTH WEST DELHI): Hon. Speaker, thank you very much for giving me this opportunity to raise the problems of rural people of my constituency that is situated in Narela. In Narela, the Delhi Development Authority acquired land in 1996 to build sub-city over there. So far not much has been done. Not only that, integrated freight corridor was to be set up which could have been done very easily. It is connected with road and rail. The only thing is that the warehouses have to be built over there. They are there. But the DDA and the Government have not taken pain to regularise them. Apart from that, in the 2010 Zonal Plan, plans have been made for a number of recreational and educational institutions. But so far land has not been allotted. About 1,000 hectares of land were allotted for recreational activities and 500 hectares of land were allotted for recreational activities. But till today, the Ministry of Urban

Development and the DDA has done nothing. Thousands of flats are lying vacant. They have not been allotted. People are homeless.

माननीय अध्यक्ष: एक ही बात को न दोहराएं। आप चाहते हैं कि आपको कनेक्शन चाहिए और जीटी रोड तक हो जाए। इतना ही कहें।

DR. UDIT RAJ: If metro is extended to that area, then those houses can be allotted and people will willingly go and occupy those houses. Thank you so much for giving me this opportunity.

श्री अश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदया, भारत किसानों का देश है, जहां 80 फीसदी किसान गांवों में बसते हैं, किंतु उनकी हालत फटेहाल है। देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर बिहार में किसानों के लिए धान क्रय केंद्र राज्य सरकार द्वारा काफी विलम्ब से खोले जाने के कारण लाखों किसानों का धान अधिप्राप्ति नहीं हो पा रहा है। बिहार में 15 नवम्बर, 2014 से धान क्रय केंद्र खुलना था, लेकिन जनवरी के अंत और फरवरी के प्रथम सप्ताह में खोला गया है, लेकिन वह भी व्यवस्थित नहीं चल रहा है। किसानों के बीच अफरा-तफरी मची हुई है, जिससे अधिकांश किसानों को शादी-विवाह तथा अन्य आवश्यक कार्यवश बिचौलियों एवं साहूकारों के यहां बाध्य हो कर औने-पौने भाव में काफी कम कीमत पर धान बिक्री करना पड़ रहा है। यहां तक कि उन्हें लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता है। सरकार द्वारा समय पर धान का समर्थन मूल्य 1660 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त नहीं होने के कारण किसानों द्वारा महाजनों का सूद चुकाना तो दूर खाने के भी लाले पड़े हुए हैं।

मेरा संसदीय क्षेत्र बक्सर शाहबाद धान का कटोरा कहलाने वाला आज कटोरा ले कर भीख मांगने की स्थिति में है। प्रशासनिक स्तर पर धान क्रय में काफी भ्रष्टाचार व्यापत है। यही हालत उत्तर बिहार एवं मध्य बिहार के अंतर्गत मगध एवं भागलपुर क्षेत्र के किसानों की है। किसान आत्महत्या करने के लिए विवश है एवं सभी किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य प्राप्त हो, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करने का तथा एलपीसी के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से समर्थन मूल्य सरकार द्वारा दिया जाए, साथ ही पंचायत स्तर पर अप्रैल 2015 तक धान क्रय केंद्र की अवधि बढ़ाई जाए। राज्य में रबी फसल हेतु यूरीया खाद का आबंटन कम होने के कारण किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। खाद की कालाबाजारी धड़ल्ले के साथ जारी है।

माननीय अध्यक्ष : आप केवल पेडी सेन्टर बढ़ाने की बात बोलिए।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: यहां तक कि 300 रुपए प्रति बोरा खाद की जगह 500-600 रुपये प्रति बोरा खाद ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है और कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है। इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित

किया जाए कि वह कालाबाजारी पर प्रतिबंध लगाए और किसानों को खाद का आवंटन अधिक से अधिक किया जाए।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदया, मेरा संसदीय क्षेत्र महाराजगंज बिहार राज्य का एक अत्यंत ही पिछड़ा क्षेत्र है। कृषि ही एकमात्र जीवनयापन का साधन उस क्षेत्र के लोगों के लिए है। इसलिए स्वाभाविक तौर पर कृषि संबंधी विकासात्मक एवं रचनात्मक कार्य की यहां विशेष आवश्यकता है। हमारे क्षेत्र में ही नहीं ब्लकि सारण प्रमण्डल के सीमा से जुड़े बिहार के अन्य जिलों में भी कृषि संबंधी कोई उच्च शैक्षणिक संस्था नहीं है। अतः भविष्य में कृषि के क्षेत्र को विकसित करने तथा कृषि क्षेत्र में नयी-नयी और शोधपूर्वक शिक्षण कार्य संचालित करने के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के जलालपुर बनियापुर, एकया, इसुआपुर, तरैया, लहलादपुर या मांझी प्रखण्ड में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वहां कृषि विश्वविद्यालय खोलने से वहां के किसानों को लाभ मिलेगा, आगे किसान उसका लाभ उठाएंगे। उनका जीवनयापन उच्चस्तरीय होगा। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि वहां कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए जमीन की कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में जमीन वहां उपलब्ध है।

DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Madam, I rise to raise an important issue about the repeal of the infamous Armed Forces (Special) Powers Act (AFSPA), 1958. I am supported by the fact that the Justice Jeevan Reddy Committee appointed in 2005 has recommended the repeal of the Act.

Again, the report of the Second Administrative Reforms Commission (2007), headed by the former Union Minister Dr. M. Veerappa Moily, has recommended the repeal of the Act. At the same time, the present Vice-President of the country Shri Hamid Ansari as Chairman of the Working Group on Confidence-Building Measures in Jammu & Kashmir has also recommended repeal of the Act. Lately, once again, the Justice J.S. Verma Committee, set up to suggest amendments to laws relating to crime against women, has recommended and I quote:

> "There is an imminent need to review the continuance of the AFSPA and AFSPA-like legal protocols in internal conflict areas as soon as possible."

So, now, time has come to revisit the AFSPA. I urge upon the Union Government , particularly, the Home Ministry to repeal this AFSPA, 1958 immediately. Thank you very much.

एडवोकेट शरदकुमार मारुति बनसोडे (शोलापुर): अध्यक्ष महोदया, मेरे शोलापुर लोक सभा चुनाव क्षेत्र के तहसील मंगलडा में 35 गांव पीने के पानी और सिंचाई से वंचित हैं। अगर शोलापुर के उजनी डैम के राइट केनाल (किलोमीटर 91) से माण्ड नदी पर गुंजेगावं के यहां बैराज के एसकैप चैनल से पानी छोड़ कर वहां से दो स्टेजेस में लिफ्ट ईरीगेशन किया जाता है तो इन 35 गांवों को पानी की किल्लत से मुक्त किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने दो टीएमसी पानी उपलब्ध कराने के लिए मंगलवाड़ा लिप्ट इरीगेशन स्कीम के लिए 530 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है मगर पर्याप्त निधि न होने के कारण और सेन्ट्रल गवर्नमेंट से एनवॉयरनमेंट क्लिअरेंस न मिलने के कारण लिप्ट इरीगेशन स्कीम अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पा रही है। इन 35 गांवों में पीने का पानी न मिलने के कारण टैंकर से पानी की सप्लाई करनी पड़ती है और अकाल के कारण यहां के किसान अपनी खेती भी नहीं कर पाते हैं। इसलए आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि मंगलवाड़ा की लिप्ट इरीगेशन स्कीम को जल्द से जल्दी एनवॉयरनमेंट क्लिअरेंस दिया जाए और एज ए एक्सेपशनल स्पेशल केस के रूप में निधि उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद।

SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): Madam Speaker, I would like to raise a very important issue pertaining to improvement of teaching standards for all the school teachers in the country. Education system in India is faltering because of lack of good teachers. Planning Commission Report of the 12th Five Year Plan stated that there are 8.1 lakh untrained teachers in the country. In addition, there are a large number of qualified *ad hoc* teachers who are virtually running primary schools in many States of the country. Around 40 per cent of the teachers in primary schools have been appointed on a temporary basis. Many of them have studied only up to higher secondary and draw paltry salary of about Rs.5,000 to Rs.7,000 per month.

Therefore, I would like to urge the Union Government to take effective and immediate measures to improve educational standards by imparting proper training to teachers. Teachers have to be encouraged by providing them job

security and higher salaries to motivate them to upgrade their skills so that the nation as a whole can benefit.

12.21 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS

(i) Re : Problems faced by rubber growers in Kerala

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): My submission is in respect of the fall in rubber prices totally in India. Kerala is very much concerned about the fall in prices of natural rubber. About 11 lakh small scale rubber cultivators face crisis due to fall in prices of rubber. The main reason for decline in rubber prices is indiscriminate import of natural rubber. In order to arrest the price fall, import of rubber should be stopped with immediate effect. Import of rubber is increased due to less import duty of rubber and rubber products. At present, rubber price has come down to Rs.120 per kg. which was about Rs.240 per kg. a few years back. This has made rubber cultivation not remunerative at all and farmers are leaving rubber cultivation. This affects the economy of the State also.

Madam, 95 per cent of the rubber cultivation is from Kerala. So, an appropriate scheme for natural rubber price stabilization or Income Stabilization Fund to support the small and marginal farmer is necessary and essential. I also urge upon the Government of India to restrict the import of natural rubber from outside. This is a very serious matter to be considered. … (*Interruptions*) In the last Session also, we have raised the same issue but no response is coming from the Government. It is very unfortunate. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Adv. Joice George has given a notice. Hon. Members, please take your seats.

… (*Interruptions*)

ADV. JOICE GEORGE (IDUKKI): Madam Speaker, I am also raising a very same issue. This morning, I have received a rubber sheet from my constituency. People of my constituency are saying that this rubber is cheaper than paper there. This is a very serious issue. In Kerala, 80 per cent of the people are depending on

rubber for their livelihood. Due to deep fall in prices of rubber, people are finding it very difficult to meet the expenses of educational expenses of their school going children, repay their loans and to meet their medical expenses. It has become a very social issue there.

Hence, I urge upon the Government to look into the issue. There should be a Price Stabilization Fund as pointed out by my learned friend, Shri N.K. Premachandran. Some concern should be showered by the Government. Otherwise, it would lead to very disastrous consequences in my State. I urge upon the Government to initiate some measures to mitigate the problem being faced by the people of Kerala. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: All the hon. Members who wanted to associate with the issue raised, may do so. I cannot compel the Government. Yes, the problem is serious. I can understand. You can associate with the issue.

Shri P.K. Biju, Shri M.B. Rajesh, Dr. A. Sampath, Shri Innocent, Shri Jose K. Mani, are allowed to associate with the issue raised by Adv. Joice George. Shri Dhruvanarayana, Shri B.N. Chandrappa, and Shri B.V. Naik are allowed to associate with the issue raised by Shri D.K. Suresh. Shri P. Karunakaran is allowed to associate with the issue raised by Shri N.K. Premachandran.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : No response has come from the Government.… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam, I appreciate the issue raised by Mr. N.K. Premachandran and all other colleagues from Kerala. It is certainly a very important issue. It has been raised several times in the House. I remember because I have also dealt with this issue as a former

Commerce Minister. I understand the issue of rubber price. A lot of factors do affect it but we are all concerned about the farmers. It is a major source of the economy there in Kerala. Seeing the concerns of the farmers, I would definitely request the Commerce Minister to hold a meeting with the Members of Parliament and do the needful.

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Thank you, Madam Speaker. Madam, I would like to place a very important issue before this House. I am very sorry to say that within nine weeks, five Christian churches were attacked in the city of Delhi. In the last Session also, we had raised the issue. The Home Minister had come in the House and promised that a special team would be set up and necessary action would be taken. I am sorry to say that even after that, four churches were attacked. I do not know why the Government is silent on this issue. It is not merely to take some money from the churches. But, there is really a very big apprehension among the people, especially the minority people in the city. It was not done in the very interior places of India, but it was done in the heart of Delhi, that is the Capital city of India. So, really, the minorities, not only in our country, in Delhi but in other places also are very anxious and apprehensive with regard to this issue.

The Prime Minister has come out with an address condemning it last week but, at the same time, five churches were attacked and no one was arrested. I want to get the reply from the Government as to what action the Government is going to take. The Home Minister has promised in this House that he would take all measures, but no action has been taken. You see, within nine months, five churches were attacked. So, I can imagine that within five years how many churches would be attacked. So, what action the Government is going to take? What is the present position as far as the investigation is concerned? The Home

Minister said that a special team is set up. Then, what is its report? The Government should come, the Home Minister should come in this House and make a statement as to what is the present situation and what action the Government has taken in this regard. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri P.K. Biju, Shri Innocent, Shri M.B. Rajesh, Adv. Joice George, Shri Jose K. Mani, Dr. A. Sampath, Shrimati P.K. Shreemathi Teacher and Shri Md. Badaruddoza Khan are permitted to associate with the issue raised by Shri P. Karunakaran.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बार-बार ऐसा नहीं करते, प्लीज आप बैठिये।

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एन.एच.-76 जो इलाहाबाद से कांडला को जोड़ता है, उसकी कोटा शहर से जुड़ने वाली कनेक्टिविटी सड़क का जो साठ किलोमीटर का इलाका है, उस साठ किलोमीटर की सड़क को पार करने में पौन घंटा लगता है, उस सड़क की हालत बहुत खराब हो गई है।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिस तरीके से एन.एच.-76 का डबल सी.सी.रोड बना है, उसी तरह से कोटा शहर की कनेक्टिविटी सड़क, जो गवर्नमैन्ट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, उस कनेक्टिविटी सड़क को बनाया जाए, वहां बहुत सी दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं और भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए, उसे रोकने के लिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के समक्ष एक जरूरी विषय लाना चाहता हूं। कल स्टार्ड क्वैश्चन नम्बर चार पर माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि आज हमारे देश के अंदर 13 लाख मीट्रिक टन यूरिया की डिमांड है। हमारे देश के अंदर 23 मिट्रिक लाख टन यूरिया पड़ी है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जब यूरिया की जरूरत थी, हमारे देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि हमारी माताओं-बहनों को थाने में जा कर पर्चियां कटवा कर यूरिया लेनी पड़ी। हरियाणा के अंदर, जहां दिसंबर के माह में डेढ़ लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत थी, वहां केवल अस्सी हज़ार मीट्रिक टन ही यूरिया उपलब्ध थी। उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हरियाणा से पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बहुत भारी मात्रा में यूरिया की कालाबाजारी हो रही थी। माननीय मंत्री जी से निरंतर मुलाकात

कर के भी, प्रदेश सरकार को भी बता कर हमने यह प्रयास किया कि किसी तरह कालाबाजारी रोकी जाए। एक तरफ तो माननीय प्रधान मंत्री जी हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की शुरूआत करते हैं और दूसरी ओर हमारी माताओं-बहनों को पुलिस चौकियों के अंदर जा कर यूरिया की स्लिप कटवा कर लानी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अपील करता हूँ कि इस पर एक डिटेल्ड इंक्वायरी करवा कर इसकी जांच करवाने का काम करें।

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, मैं दुखी मन से एक बार फिर जो डिफेंस का मामला है, उसको उठाने का काम कर रहा हूँ। मैं आपसे भी आ कर मिला था। आपने भी हमको यहां पर कॉलिंग अटेंशन मूव करने का अवसर दिया। पहले के डिफेंस मिनिस्टर अरूण जेटली जी से हम मिले थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से कहा कि यह इल्लिगल सर्क्युलर है, इसको हम तुरंत विदड्रॉ करेंगे। लेकिन उसके बाद में पर्रिकर जी आ गए, उन्होंने भी इसके बारे में सकारात्मकता दिखाई, क्योंकि वे इस विषय के भुक्तभोगी हैं। महोदया, मैंने महाराष्ट्र की सरकार को भी यह सर्क्युलर विदड्रॉ करने के लिए 07.11.2014 को पत्र लिखा था। बहुत ही खुशी की बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने इस सर्क्युलर को विदड्रॉ कर लिया है। आगे के लोगों को इससे बहुत ही राहत मिलेगी। लेकिन सन् 2011 का जो सर्क्युलर डिफेंस ने निकाला था, उससे चार साल से सबके काम बंद पड़े हुए हैं, उनको फिर एक बार यह मौका दिया गया है कि वे तीस दिन तक इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन हो तो रेज करें। अगर फिर एक बार ये ऑब्जेक्शन करते हैं तो और बहुत लंबा समय लगेगा। मैं बहुत ही नम्रता से आपसे निवेदन करता हूँ कि बिना विलंब, अनकंडिशनल यह सन् 2011 का सर्क्युलर विदड्रॉ कर दिया जाए, ताकि मुंबई शहर के जो हज़ारों इफेक्टिड लोग हैं, उनको साथ लेने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। लोग बहुत ही दुखी हैं। चार साल से लोगों के काम बंद पड़े हैं। बिल्डिंगें तैयार हैं, लेकिन लोग उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। मैं आपके माध्यम से एक और मांग करूंगा कि जो दोषी अधिकारी हैं, सरहद पर लड़ने वाले जो सैनिक हैं, उनका हम सब आदर करते हैं, लेकिन डिफेंस के जिस ऑफिसर ने यह इल्लिगल सर्क्युलर निकाला है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस लोक मंदिर के माध्यम से यह मांग करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज - उपस्थित नहीं।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity. As the House is well aware, the State of Andhra Pradesh has been devastated by the Hudhud Cyclone. It was an unprecedented cyclone in the history of this country. It had caused a large scale destruction to the crops, infrastructure, flora and fauna.

The Government of Andhra Pradesh has requested the Central Government to sanction Rs. 21,000 crore as a relief fund to undertake the rehabilitation works. In this connection, the hon. Prime Minister was kind enough to announce the financial relief of Rs. 1,000 crore immediately. Up till now, the Central Government has released only Rs. 600 crore. They have yet to release Rs. 400 crore. In the absence of this amount, we are not able to provide relief and rehabilitation to all affected people in a comprehensive manner.

I would further like to request the Central Government to sanction the sufficient amount asked by the Government of Andhra Pradesh in order to cover all affected people. In the last Session also I have raised the same issue. Already five months are over. Our hon. Venkaiah Naiduji had already witnessed this problem. So, the balance amount should immediately be released. No capital is there in our State. We are already running a deficit budget. Our hon. Chief Minister is running the State with a very great difficulty.

Therefore, through you, I urge upon the Ministry of Finance, Government of India, to release the remaining amount of Rs. 400 crore immediately.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रंजीता रंजन। यह हिंदी का तो कोई मतलब नहीं है। हिंदी तो सदन में चलती है।

श्रीमती रंजीत रंजन : महोदया, मैं आपके माध्यम से बाल श्रम के ऊपर बोलना चाहूँगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बाल अधिकार को लेकर वर्ष 1980 से आज तक बहुत कानून बने। दो महत्वपूर्ण कानून, बाल श्रम (उन्मूलन और विनियमन) अधिनियम, 1986 और शिक्षा का अधिकार, 2009 संसद ने बनाये हैं। इन दोनों कानूनों में अंतर्विरोध है। वर्ष 1986 का कानून अधकचरा होने के साथ लचर भी है। एक तरफ हम शिक्षा का अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ उसी कानून में कहा जाता है कि 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे खतरनाक काम नहीं करेंगे, लेकिन काम कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि इस कानून को अमेंडमेंट के लिए जल्द से जल्द लाया जाए।

कैलाश सत्यार्थी जी पिछली बार भी 400 एमपीज से मिले, इस बार भी तकरीबन 50 सांसदों से वे मिल चुके हैं। कैलाश सत्यार्थी जी के साथ मैं इस बात को पर्सू भी करती हूँ कि हम लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि बाल श्रम के कानून में जल्द से जल्द अमेंडमेंट करके, यह जो तर्क है, उसे हटाया जाए। चाहे खतरनाक काम हो या कोई भी काम हो, पूरी तरह से बाल श्रम को खत्म किया जाए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं बुंदेलखंड के पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्र की बात यहाँ उठाना चाहता हूँ। जिसमें एक बहुत ही प्रतिष्ठित सर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय है, इसको वर्ष 2012 में सेन्ट्रल यूनिवर्सटी बना दिया गया। इन दो वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार ने दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर जिलों में लगभग 13 शासकीय महाविद्यालय खोले और कुछ प्राइवेट खुले। चूँकि सागर केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गया है, यहाँ पर मानव संसाधन मंत्री जी उपस्थित हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो सेन्ट्रल यूनिवर्सटी बन जाती है, नोटिफिकेशन के बाद जो कॉलेज बनते हैं, उनको वे संबद्धता नहीं देते हैं। इस पिछड़े क्षेत्र में राज्य सरकार ने तो कोशिश की कि वहाँ महाविद्यालय खुल जाएं, लेकिन संबद्धता न देने के कारण वहाँ के बच्चों का जीरो ईयर होने वाला है। मेरी आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्री जी से प्रार्थना है कि सागर विश्वविद्यालय को इस बात का सन्देश पहुँचायें, ताकि इस वर्ष उन शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों को संबद्धता देकर बच्चों को रेग्युलर होने का मौका दें, ताकि उन गरीब छात्रों का नुकसान न हो। हमारे टीकमगढ़ और सागर के सांसद भी सदन में उपस्थित हैं। मैं सभी की तरफ से मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि आप कृपा करके इसमें संरक्षण दें ताकि हमारे बच्चों का वर्ष न खराब हो।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप दोनों इस विषय के साथ एसोशिएट कर सकते हैं।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। मेरी उनसे इस संबंध में प्रार्थना है।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. वीरेन्द्र कुमार और श्री लक्ष्मी नारायण यादव अपने आपको श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): महोदया, आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारे लोक सभा क्षेत्र अकबरपुर के कानपुर नगर के विकासखंड बिधनू के अंतर्गत विद्युत की लाइनें अत्यंत जर्जर हैं। इसके कारण गंभीर घटनायें आए दिन होती रहती हैं। वहाँ बड़ी मात्रा में आवागमन रहता है। अभी विगत 19 तारीख को एक किसान अपने खेत में पानी लगाने गया था।

माननीय अध्यक्ष : यह स्टेट मैटर है।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले: विद्युत की अतिवृष्टि होने के कारण उसकी वहाँ आकस्मिक दुर्घटना में मौत हो गई। हम लोगों ने, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने तमाम बार अधिकारियों और कर्मचारियों को अवगत कराया, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता है। वहाँ विद्युत पोलों की अत्यधिक दूरी है, लाइनें जर्जर हैं, उनकी क्वालिटी ठीक नहीं हैं, आये दिन विद्युत की आपूर्ति भी बाधित रहती है। कभी बिजली रात में आती है और कभी दिन में आती है।

माननीय अध्यक्ष : यह स्टेट मैटर है।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले : महोदया, इस तरह की भीषण दुर्घटनाएं लगातार वहाँ घट रही हैं। मेरा निवेदन है कि इस पर अविलम्ब हस्तक्षेप करके मदद करने की कृपा करें।

12.39 hrs.

SUBMISSIONS BY MEMBERS....Contd.

(ii) Re : Problems faced by students of Jammu and Kashmir is getting scholarship under the Prime Minister Special Scholarship Scheme

सुश्री महबूबा मुफ़्ती (अनन्तनाग) : महोदया, मैं आपका और इस हाउस का ध्यान एक बहुत ही सीरियस मामले की तरफ दिलाना चाहती हूँ। It concerns hundreds of students from Jammu and Kashmir. पिछली सरकार के टाइम में जम्मू-कश्मीर के हालात को देखते हुए वहाँ के गरीब लड़के-लड़कियों के लिए एक प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम बनाई गई थी। इसकी वजह से हमारे जम्मू-कश्मीर के कई लड़के-लड़कियों को मुल्क के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कई माह से ये स्टूडेंट्स, जिनको दो साल से भी ज्यादा अरसा हो गया है, बहुत कंफ्यूजन का शिकार हैं, क्योंकि बदकिस्मती से जिस वक्त इनका एडमिशन हुआ है, जो बीच में एडमिशन करने वाले लोग थे, चाहे एन.जी.ओज. थे या दूसरे थे, उन्होंने कई ऐसे कॉलेजेज में उनका एडमिशन किया है, जो लिस्टेड नहीं थे। कई ऐसे कॉलेजेज में उनका एडमिशन हुआ है, जहाँ का कोटा 20 का था, लेकिन 50 स्टूडेंट्स का वहाँ एडमिशन कर दिया। हालाँकि इसमें स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं है। उनके दो-ढ़ाई साल हो गए हैं और आज उन स्टूडेंट्स से डिफरेंट कॉलेजेज फीस के लिए डिमांड करते हैं। वे फीस कहाँ से लाएं? होस्टल से बाहर निकालने की कोशिश होती है और कई बच्चे बच्चियाँ होस्टल से बाहर आ गए हैं। मेरी गुज़ारिश है कि जैसे मैं आनरेबल एच.आर.डी. साहिबा से भी मिली, मेरी आपसे भी गुज़ारिश है कि यह बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि इस वक्त मेरे ख्याल में 400 से लेकर 700 जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के स्टूडैन्ट्स हर दरवाज़े पर जा रहे हैं कि हम कहाँ जाएँ, क्योंकि वे गरीब परिवारों से हैं, उनके पास क्षमता नहीं है, उनके पास इतना पैसा देने की ताकत नहीं है। इसमें सरकार इंटरवीन करे और इस मसले को कम से कम जो आज तक के स्टूडैंट्स हैं, उनके मसले को रिसॉल्व करें और जो आगे आने वाले स्टूडैन्ट्स हैं, उसमें खास ध्यान रखा जाए कि यह गलत हाथों में, गलत इंस्टीट्यूशंस में न चला जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसमें इंटरवीन करके इस मसले को रिसॉल्व करने में हमारी मदद करेंगी।

HON. SPEAKER: Yes, hon. Minister, do you want to say something?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Yes, Madam.

The hon. Member had reflected her agony over this issue, in person, to me before, and I had brought it to her notice that there are certain individuals/NGOs as she referred to in her statement, who have misled students to get admitted in such institutions that were not a part of this scheme. I have, in my conversation with the hon. Member privately, also told her that we are exploring various possibilities where these institutions and those individuals who have misled these students be brought to book.

I am hoping for some kind of a resolution in favour of the students but I am challenged because the institutions or the individuals concerned that have been expressed by the Members, have deliberately misled these students two years ago.

So, I can only say this Madam to the hon. Member that I am exploring avenues in these challenging times.

HON. SPEAKER: Okay.

SHRI P.P. CHAUDHARY (PALI): Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity to speak during 'Zero Hour.'

महोदया, मेरा इश्यू रेल मंत्रालय से संबंधित है। जोधपुर और दिल्ली के बीच में 600 किलोमीटर की दूरी है। उसके बीच में बिलाड़ा और बर का 40 किलोमीटर का एक मिसिंग रेल लिंक है जो ब्रिटिश टाइम से पड़ा है। इसके लिए रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दी। उसके बाद 1997 में तत्कालीन रेलवे मंत्री जी ने घोषणा की और शिलान्यास भी कर दिया। लेकिन प्लानिंग कमीशन ने उसको इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि कॉमर्शियली वायेबल नहीं है। लेकिन मैं रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे भारत की जो रेल हैं, सिर्फ कामर्शियल वायेबिलिटी पर नहीं चलती हैं, सोशल वायेबिलिटी और कामर्शियल वायेबिलिटी को हमें बैलैंस रखना पड़ता है। लेकिन अभी by afflux of time, पुनः परीक्षण करें तो वहाँ लाइम स्टोन की काफी माइन्स हो गई हैं और वहाँ सीमेंट प्लांट आ गए हैं। उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन रोड के द्वारा होता है। इसके अलावा वहाँ हैंडीक्राफ्ट का मार्केट है, और ग्वार गम और वहाँ एक्सपोर्ट ओरियेंटेड यूनिट्स भी आ गई हैं। रक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह रेल लिंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैसैंजर इसमें 70 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके जाते हैं और उसके बीच में कहीं रेल लिंक नहीं है। इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण रेल लिंक जो आल्टरनेट रेल लिंक है जोधपुर से दिल्ली के बीच में, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे कल जो बजट पेश कर रहे हैं, उसको इसमें लें। बहुत बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री पी.पी.चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Madam Speaker, I raising a very important and urgent matter during Zero Hour today.

The Draft Civil Aviation Policy has proposed to develop only six international airports as travel multi-modal hubs. The Draft has limited its scope by selecting six metropolitan airports of Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangaluru and Hyderabad that would be developed as major international hubs and would, in future, be the main access point for international travel to and from India. This is what the Draft Policy states. This proposal is, indeed, discriminatory and raises serious concern to States like Kerala, which has higher air traffic compared to any of the proposed airports.

In 2013-14, Cochin International Airport Limited in Kerala carried 3.27 million passengers, or seven per cent of country's total traffic, which is higher than Bangaluru and Hyderabad put together. In fact, if passengers from Kerala's three international airports – Kochi, Kozhikode and Thiruvananthapuram – are clubbed, the State's traffic at 7.38 million is substantially higher than even Chennai. If implemented, the Policy will work against the interest of people of various regions, and will badly affect the development of various airports.

Hence, Madam, I would request that the concerned authority should not implement such a discriminatory proposal and should take much more inclusive steps for the development of various airports in the country

HON. SPEAKER: The names of Shri Mullappally Ramachandran, Shrimati P.K. Shrimathi Teacher, Shri P.K. Biju, Shri Innocent, Adv. Joice George and Shri N.K. Premchandran will be associated on this issue raised by Shri K.C. Venugopal.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

महोदया, पश्चिमी राजस्थान में अकाल हमारा सहोदर है, हमारा सगा भाई है, हमारे साथ जन्मा है। पिछले सालों में से 42 साल पूरा या थोड़ा अकाल पड़ा है। इस बार भी परिस्थिति कमोबेश वैसी ही है। राजस्थान की सरकार ने 13 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया है और 5841 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। जो प्रदेश अभावग्रस्त घोषित होता है, उस क्षेत्र में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की स्कीम्स के तहत राहत कार्य चलाए जाते हैं। देश की सरकार राहत कार्य चलाने के लिए सिर्फ 90 दिन ही प्रदान करती है कि 90 दिन तक ही राहत कार्य चलाए जा सकते हैं। इस वर्ष परिस्थिति इतनी गम्भीर है कि कुछ क्षेत्रों में तो केवल 3 एमएम बरसात ही हुई है। देश में बरसात का एवरेज 1200 एमएम है और देश में जब 50 प्रतिशत वर्षा होती है तब उसको भयानक अकाल कंसीडर किया जाता है। हमारे यहां केवल 3 एमएम बरसात हुई है जो 330 एमएम का केवल एक प्रतिशत है और पूरे क्षेत्र की आजीविका का साधन पशुपालन है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां दस किलोमीटर दूर से महिलाएं सिर पर पानी रख कर लाती हैं। यह बहुत ही गम्भीर ही स्थिति है। जब हजारों गाय मर रही थीं, तब राज्य सरकार ने 90 दिन की अवधि में एनडीआरएफ के पैसे से पशु शिविर और पेयजल की सुविधा को प्रारम्भ किया गया। उस 90 दिन की

अवधि में शिथिलता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने देश की सरकार को लिखा और देश की सरकार ने उस फाइल को टर्नडाउन कर दिया है। अगर उन नार्मस में शिथिलता प्रदान नहीं की गई, तो लाखों गाय एक महीने में काल कवलित हो जाएंगी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि लाखों गायों और हजारों महिलाओं की तकलीफ को देखते हुए देश की सरकार एनडीआरएफ के नार्मस में 90 दिनों का जो बैरीयर है, इसे समाप्त करे, वरना हमें लाखों गायों की मृत्यु को अपने सामने काल कवलित होते देखना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.पी. चौधरी और श्री सी.आर. चौधरी अपने आपको श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करते हैं।

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Madam Speaker, thank you so much for giving me an opportunity.

The tribal population of our country has been suffering endlessly right after Independence. I am bringing this issue because no justice has been made to them for the last 60-70 years. Madam Speaker, in my constituency there is a large population of Kudumi community and the Constitution of India categorizes them as a Backward Class community whereas they have been demanding the status of tribal class. The Census record very clearly demonstrates and shows that in 1931 they were classified as 'primitive tribe' and in 1941, they were classified as 'tribal Hindus'. Madam Speaker, when the Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas, formed in 1946, excluded this Kudumi community while submitting their report, which resulted in the non-inclusion of Kudumi community when the Constitution finalized the Constitution (Scheduled Tribes) Order in 1950.

Why were they excluded? I will just say one line which will make things abundantly clear to this august House. The Advisory Committee's scope was limited to India excluding the Princely States, as they existed in 1946 when this Committee was formed. However, over the years, many of the States had integrated into the neighbouring provinces and they should have been included in

the Scheduled Tribe population. The Orissa Princely States is a classic example of such inclusion and integration into the neighbouring provinces.

In Odisha alone, there are 25 lakh primitive tribes of the Kudumi community. In my constituency alone, there are 75,000-76,000 Kudumi are living. Madam Speaker, though they belong to the Scheduled Tribe community, they have long been deprived of this facility, and this august House had debated this issue in 1949 that yes there is a demand to include them.

So, I would sincerely urge upon the Government of India to take cognizance of this serious problem of Kudumi tribes and include them in the Schedule Tribe category so that the long pending and long suffering of this tribe can be taken care of. Thank you so much.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से झारखण्ड प्रदेश के गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत गिरिडीह-कोडरमा रेल लाइन, जो वर्ष 2000 में शुरू की गयी थी और रेलवे द्वारा लखारी, बक्सीडीह के मौजा का भूमि अधिग्रहण किया गया। भूमि अर्जन पदाधिकारी द्वारा भू-स्वामियों को लगभग दस करोड़ रुपये का मुआवज़ा भुगतान कर दिया गया। पुनः रेल विभाग द्वारा उक्त भूमि पर रेल परियोजना को स्थगित करते हुए पुनः अंदूडीह, चंदाडीह, सिहोडीह, दिघरिया कला होते हुए रेल परियोजना शुरू करने और भूमि अधिग्रहण करने का संशोधित निर्देश दिया गया है। परिणामस्वरूप भूमि का मुआवज़ा, भूमि का अधिग्रहण 11/19 नए नियम के तहत भूमि के स्वामित्व का भुगतान करने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व की भूमि अधिग्रहण की धारा 5.6 के अंतर्गत भूमि मुआवज़ा प्रदान करने की कार्रवाई की गयी थी। प्रश्न यह है कि रेलवे के संशोधित निर्णय के कारण उक्त रेल परियोजना कार्य में विलम्ब होने से हजारों रेल उपभोक्ताओं को सजा मिल रही है। ज्ञातव्य है कि कोडरमा-हज़ारीबाग रेल परियोजना की शुरूआत वर्ष 1999 में प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गयी थी, जिसे 20 जनवरी को संपन्न होना था और इस मार्ग की रेल परियोजना शुरू होने वाली थी। परन्तु, इसमें विलम्ब होने के कारण यह अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।

अतः हमारा सरकार से, रेल मंत्रालय से आग्रह है कि गिरिडीह-कोडरमा रेल लाइन की अविलम्ब शुरूआत की जाए और इसे पूर्ण कराया जाए।

SHRI C. GOPALAKRISHNAN (NILGIRIS): Hon. Speaker, first of all, I pray to my leader, Puratchi Thalaivi Amma. I raise an important issue to ban iodised salt

and thereby giving life to thousands of common people indulging in common salt business.

Based on some false reports of some international bodies, the Government has banned usage of common salt in day to day life in India. I urge that this programme should be reviewed with reference to the latest inputs and research data.

The Government had made mandatory consumption of only iodised salt on the ground that iodine deficiency causes a wide spectrum of disorders, ranging from goiter, mental retardation, lower IQ and neuromotor defects.

After imposing a ban on common salt, the price of salt has gone high almost by five times. Earlier it was Re.1 per kg which is now Rs.10 per kg. The corporate companies involved in the business raised the price of salt at least 500 per cent to 800 per cent. Also, they are indulging in unfair trade practices mentioning the diet salt as low iodized salt etc.

When people who do not suffer from iodine deficiency are forced to take iodized salt regularly, there is a risk with many of them developing complications induced by higher intake of iodine and increase in iodine levels. Consumption of iodized salt in larger quantity cause metallic taste, teeth and gums problem, burning in mouth and throat, increased saliva, throat inflammation, stomach upset, diarrhea, wasting, depression, skin problems and many other side effects.

Hence I urge upon the Government to take immediate steps to ban the mandatory use of iodized salt which is provided by big corporate companies making unscrupulous benefits and help the common salt producers who are common people. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी जी, आपका इश्यू भी सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित नहीं लगता है। आप बताएं।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): अध्यक्ष जी, यह सेंट्रल गवर्नमेंट से ही संबंधित है।

अध्यक्ष जी, मैं संत कबीर नगर संसदीय क्षेत्र से आता हूं जो तीन कमिश्नरियों में विभाजित है। हमारे अम्बेडकर नगर के आलापुर तहसील में किसानों की समस्याओं के आधार पर गन्ना विकास के लिए विगत दस वर्ष पहले एक सर्वेक्षण किया गया था। उसमें यह बात उभर कर आयी कि अगर यहां पर चीनी मिल की स्थापना कर दी जाती है तो यहां के किसान खुशहाल होंगे।

ऐसी परिस्थिति में हमारा आपसे आग्रह है कि अगर आप केन्द्र सरकार के माध्यम से सहकारिता के आधार पर वहां एक चीनी मिल खुलवाने का आदेश देने की कृपा करेंगी, तो हमारे आलापुर तहसील के किसानों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है।

SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR): Madam, I want to raise an important issue regarding the pathetic conditions of the hostels for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students, which are run by the State Government under the schemes of the Central Government. There are two schemes from the Central Government – one scheme called Babu Jagjivan Ram Chhatravas Yojana from the Ministry of Social Justice and Empowerment and anone scheme called Eklavyashala from the Ministry of Tribal Affairs. The funds are provided by the Central Government for construction of hostels and their maintenance, but these hostels are run by the State Government. The condition of that hostel and basic facilities were not good in comparison to Kendriya Vidyalaya and Jawahar Navodaya Vidyalaya. Their standard of education is also very low.

In this connection, the Supreme Court on 30th January had advised the Central Government to stop framing schemes if it cannot monitor and implement them. Since the standard of education is very low and the basic facilities are not being provided by the State Government, my request, through you, to the Central Government – the Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of Tribal Affairs - is to establish a monitoring mechanism and to ensure that the State adheres to the basic standards in constructing and managing hostels.

Thank you.

HON. SPEAKER: Shri D.K. Suresh, Shri B.N. Chandrappa and Shri B.V. Naik are permitted to associate with the issue raised by Shri R. Dhruvanarayana.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : महोदया, अपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपका ध्यान नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कोठिया घाट की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपद लखीमपुर और बहराइच में नेपाल से आने वाली गेरूहा नदी में मिलकर कोठियाघाट, जो कर्तिनियां घाट के पास है, वहाँ पर बहराइच में घाघरा नदी आगे परिवर्तित होकर एक विशाल नदी में बदलती थी। पूर्व में उक्त कोठिया घाट में जहाँ पर यह नदी विशाल रूप लेती है, नेपाल के पर्वतों से बहकर आये पत्थरों को यहाँ निकाला जाता था। इससे नदी की गहराई भी बनी रहती थी तथा जल बहाव बना रहने के कारण उक्त सीमावर्ती क्षेत्र बाढ़ से मुक्त रहते थे। क्षेत्रीय लोगों के पत्थर निकालने के कारण वहाँ पर रोजगार का अवसर भी उपलब्ध रहता था। लोगों की फसल और मकान बाढ़ न आने के कारण बचे रहते थे। पूर्ववर्ती केन्द्रीय सरकार के द्वारा उक्त कोठिया घाट से पत्थरों को निकालने का काम बन्द कर दिया गया, जिसके कारण वहाँ पर नदी की सतह ऊँची हो गई है। इस कारण अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित उन गावों में बाढ़ आने लगी है। वहाँ के लोगों का रोजगार भी बन्द हो गया है, जिससे उनकी आमदनी पर भी असर पड़ा है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि उक्त कोठिया घाट में पुनः पत्थर निकालने का काम प्रारम्भ कराया जाए, जिससे नदियों की गहराई भी बनी रहेगी, उक्त क्षेत्र बाढ़ से मुक्त होगा और लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री दहन मिश्रा को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, I wish to raise a matter of urgent public importance which is related to my parliamentary constituency.

There is a Pamba-Achankovil-Vypar Rivers Linking Project. Since the time of the said proposal, Kerala State is vehemently opposed to, and did not approve of, the proposal of linking River Pamba and River Achankovil with the River Vypar due to various reasons. The Pamba and the Achankovil are not long distance rivers and they traverse only in Kerala; they are not inter-State rivers. They are not perennial but rain-fed rivers.

A sizeable portion of this coastal wetland zone lies at or below sea level. It is a thickly populated region a major part of which – Kuttanad with 54 villages

spread over three districts – is known as the rice bowl of Kerala and is famous for its distinctive patterns of cultivation, sometimes carried out up to two metres below the sea level, with the fields being prone to floods as well as salt water intrusion from the sea.

The linking of the Pamba and the Achankovil will not only hamper the lives of good people of Kuttanad but will also lead to total ecological disaster. So, we strongly object to the proposal to link the Pamba, the Achankovil and the Vypar rivers and request the Government to drop the proposal outrightly.

Thank you.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Madam, we are all associating.

माननीय अध्यक्ष : आप एसोशिएट कीजिए।

Shri N.K. Premachandran is permitted to associate with the issue raised by Shri Kodikunnil Suresh.

माननीय अध्यक्ष : श्री भगवंत मान, यह आपने क्या दिया है? पूरे हिंदुस्तान को आप इसमें लेना चाहेंगे, सभी योजनाओं का एक साथ थोड़े न देते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप बोलिए।

श्री भगवंत मान (संगरूर): मैडम, केन्द्र की जो योजनायें गरीबों के लिए हैं, जैसे मनरेगा है या इंदिरा आवास योजना है, असल में वे बीपीएल कार्ड पर बेस्ड हैं। अगर आपके पास कार्ड है तो आपको उस योजना का लाभ होता है। कुछ ताकतवर लोग अपने चहेतों के कार्ड बनवा लेते हैं। जिनके लिए योजना बनाई गई थी, उनके कार्ड नहीं बनते हैं।

13.00 hrs.

वे लोग भी सभी योजनाओं का लाभ लेने लगते हैं। जब हम निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं तो सबसे पहले लोग यही कहते हैं कि हमारा मनरेगा का कार्ड नहीं बना। बी.पी.एल. कार्ड बनाने की जो क्राइटिरिया है उसकी ऑन-गोइंग प्रोसेस की भी जांच होनी चाहिए। यह सरपंचों पर छोड़ दिया जाता है और सरपंच राजनीतिक प्रभाव में कुछ ऐसे लोगों के कार्ड बना देते हैं जिनको इन योजनाओं की जरूरत नहीं थी। इन्दिरा आवास योजना, मनरेगा, बुढ़ापा पेन्शन योजना या सस्ता राशन लेने की जो योजनायें हैं।...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि बी.पी.एल. कार्ड बनाने की जो प्रोसेस है, क्राइटिरिया है, उनकी नियमित जांच हो ताकि उन लोगों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंच सके, जिन लोगों के लिए योजनाएं बनायी गयी हैं। धन्यवाद।

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Thank you, Madam Speaker. I would like to raise a matter of public importance relating to the Ministry of Agriculture. The Central assistance for construction of fishing harbours and fish landing centres under the Centrally-Sponsored Scheme has been reduced.

Presently, the State of Kerala is availing Central assistance of 75 per cent under the Centrally-Sponsored Scheme. There are 24 fishing harbours in the State including those under construction. The Government of India is giving assistance of 75 per cent for seven on-going fishing harbours and fish landing centres. Unfortunately, the Government of India has now issued a circular to enforce 40 per cent ceiling on capital cost of infrastructure.

Kerala has a long coastline of 570 kms. and fishing is a traditional occupation in the State with over 12 lakh fishermen engaged in this sector. The fisheries sector contributes 10 per cent of the total GDP of the State. Kerala is also the largest marine exports State in the country.

The fishing sector needs fast technological changes including availability of deep-sea fishing vessels, satellite-aided probable fishing zone identification, advanced fish processing technology, etc. Therefore, the present decision will not only adversely affect the upliftment of the sector and the fishing community, but it will also face cost escalation in all the Centrally-Sponsored Schemes and burden the State exchequer. With Kerala being a consumer State, this will heavily burden the State's economy, especially, when the fishing sector contributes 10 per cent of the GDP of the State.

Madam, through you, I would like to again request the Government of India that the amended decision of 40 per cent should be withdrawn immediately, and the 75 per cent Central assistance should be restored. Thank you, Madam.

13.03 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA AND BILL AS RETURNED BY RAJYA SABHA WITH AMENDMENTS *

HON. SPEAKER: Now, Secretary-General.

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2015 which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 24th February, 2015."

(ii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2014, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th December, 2014, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 24th February, 2015, with the following amendments:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line *l, for* the word "Sixty-fifth", the word "Sixty-sixth" be *substituted.*

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 4, *for* the figure "2014" the figure "2015" be *substituted.*

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

* Laid on the Table.

2. Madam Speaker, I lay on the Table the Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Bill, 2015, as passed by Rajya Sabha on the 24th February, 2015 and the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2014, as returned by Rajya Sabha with amendments.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2 pm.

13.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.00 hrs.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

(Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members, who have been permitted to raise Matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over the text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to accord sanction for establishment of Bundelkhand University in Damoh, Madhya Pradesh

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड में सागर विश्वविद्यालय एक ख्यातिलब्ध विश्वविद्यालय है जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय बन गया है। परिणामस्वरूप केन्द्रीय बनने के बाद जो नये महाविद्यालय खोले गये, उनको केन्द्रीय विश्वविद्यालय संबद्धता नहीं दे रहा है। परिणामस्वरूप शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के छात्रों का एक वर्ष शून्य होने वाला है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कारण गरीब मध्यवर्गीय एवं निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के छात्रों की उच्च शिक्षा पर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय को तत्काल स्वीकृति प्रदान कर उसे दमोह में स्थापित करने की त्वरित कार्यवाही की जाए।

(ii)Need to take steps for providing benefits and facilities to persons belonging to socially, educationally and economically weaker section as are available to Scheduled Castes and Scheduled Tribes

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : केन्द्र सरकार द्वारा जून 1999 में ऐसी विभिन्न जातियों को जो अनुसूचित जाति/जनजाति का दर्जा प्राप्त करने की पात्रता रखती हैं, को ऐसा दर्जा प्रदान करने हेतु एक कार्यविधि तैयार की गई थी जिसमें जून 2002 में संशोधन किया गया था। उस कार्य विधि द्वारा राज्य (राज्यसंघ) क्षेत्र से यह अपेक्षा की गई थी कि एक जाति का विनिर्देशन करने हेतु नृजातीय आंकड़ों के साथ पूर्ण प्रस्ताव करना आवश्यक है। हिन्दू बंजारा, बोट, गुरछिया, रायसिख व मजहवीसिख समेत ऐसी कई जातियाँ हैं, जो रहन-सहन, खान-पान सामाजिक स्तर, शिक्षा के स्तर और संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति का दर्जा दिये जाने की पूर्ण पात्रता रखती हैं तथा कइ राज्यों में उन्हें ऐसा दर्जा प्राप्त है। इन जातियों की आर्थिक, शैक्षिक व सामाजिक उन्नति के लिए बंजारा, बोट व गुरछिया जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति का दर्जा दिया जाना आवश्यक है। परन्तु प्रदेश सरकारें सब कुछ जानते हुए भी अपनी राजनैतिक प्राथमिकताओं के आधार पर प्रस्ताव करती हैं, जिससे पात्र जातियों को अनुसूचित जाति/जनजाति दर्जा प्राप्त नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप इन जातियों के लोग आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए इन जातियों को धारा में लाने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति का दर्जा देने की क्रियाविधि में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि इस क्रियाविधि में परिवर्तन करके राज्य द्वारा प्रस्ताव न देने की स्थिति में भारत सरकार स्वयं संज्ञान लेकर उक्त जातियों द्वारा दिये प्रस्तावों का स्वयं सर्वेक्षण कराकर पात्र जातियों को अनुसूचित जाति/जनजाति का दर्जा प्रदान करके, उक्त पात्र जातियों को न्याय प्रदान करने का कार्य करे।

(iii) Need to provide funds for undertaking gauge conversion of railway line between Narkatiyaganj and Raxaul in Bihar

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): पूर्व-मध्य रेलवे, हाजीपुर जोन के अंतर्गत आने वाली नरकटियागंज-रक्सौल रेलखण्ड जो कई वर्षों से छोटी से बड़ी लाईन में परिवर्तित हो रही है, लेकिन 10 वर्ष से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी धनराशि के अभाव में इस रेलवे लाईन का निर्माण काय अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसके कारण मेरे बाल्मीकि नगर लोक सभा क्षेत्र के लोगों के अलावा नेपाल, उत्तर प्रदेश और बाकी बिहार के लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह रेल लाईन नेपाल व उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ती है।

मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि नरकटियागंज-रक्सौल रेलखण्ड को पूरी धनराशि जारी कर जल्द से जल्द इस अति महत्वपूर्ण कार्य को पूरा कराएं।

(iv) Need to take suitable measures to prevent the damage to crops and disruptions in traffic due to intrusion of Nilgais in Chandauli Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : उत्तर प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र चन्दौली में वाराणसी एवं चन्दौली के अनेक गाँवों में नीलगायों (घडरोज) की बहुतायत से किसान परेशान हैं। कमोवेश यही हाल सम्पूर्ण पूर्वांचल के जिलों का तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य भू-भागों का है। नीलगायों के झुण्ड के झुण्ड खड़ी फसलों को पूरी तरह नष्ट कर देते हैं और इनके चलते सब्जी की खेती तो बर्बाद हो ही जाती है दलहन और तिलहन की फसलें तो इन इलाकों में पूरी तरह समाप्त हो गयी हैं। अब तो ये गेहूँ की फसलों को भी नुकसान पहुॅचा रहे हैं। वैसे ही कृषि क्षेत्र में किसान परेशान हैं, ऊपर से कर्ज लेकर खेती करता है और नीलगायों के आतंक से फसलों के बर्बाद हो जाने के चलते पैदावार न होने की परिस्थिति के चलते कर्ज की भरपाई न कर पाने की वजह से वह बर्बाद हो रहा है। वहीं दलहन व तिलहन की फसल नष्ट होने से आर्थिक नुकसान भी देश को हो रहा है क्योंकि इनकी कमी के चलते हमें आयात करना पड़ता है। पहले तो नीलगाय रात में फसलों का नुकसान करते थे,अब इनके झुण्ड इतने बढ़ गए हैं कि दिन-रात में किसी भी समय फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, साथ ही साथ में इनके झुण्ड के झुण्ड भी तेजी से दौड़ते हुए सड़कों को क्रॉस करते समय प्रायः दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, जिससे भारी जन-धन की क्षति होती है।

अतः मैं सरकार ये माँग करता हूं कि केन्द्र व राज्य के समन्वय से दो स्तर पर योजनाएं बनायी जायें। 1- ट्रेंकुलाइजर का प्रयोग करके इनकी प्रजनन क्षमता को कम किया जाए जिससे इनकी संख्या घट सके। 2- एक निश्चित धनराशि सुनिश्चित कर केन्द्र व राज्य समन्वय करते हुए वन विभाग के साथ योजना बनाकर इन्हें आबादी वाले इलाकों से उठाकर घने जंगलों में छोड़ा जाये जिससे किसानों को राहत मिल सके।

मैं पुनः बल दे रहा हूँ कि यह राष्ट्रव्यापी समस्या है। इस समस्या पर विशेष कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता है।

(v) Need to include Bargi dam project in Jabalpur, Madhya Pradesh in the scheme of national project

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश की बरगी परियोजना के दायीं तट नहर को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के संबंध में दिलाना चाहता हूं। इस नहर से महाकौशल प्रांत के जबलपुर, कटनी, सतना तथा रीवा की 2,45010 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई प्रस्तावित है तथा 81,53684 जनसंख्या लाभान्वित होंगी। इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के संबंध में प्रदेश सरकार ने मार्च 2010 में सभी नियमों व मानदंडों को पूरा करके केंद्र सरकार के पास 3796 करोड़ की वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए भेजा था परंतु पिछली यू.पी.ए. सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों से लगातार इस विषय को लटकाया जा रहा था। मैं पिछली तीन अवधि से लगातार लोक सभा का सदस्य हूं और लोक सभा में लोक हित में इस विषय को उठाता आ रहा हूं कि उक्त परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया जाए परंतु अभी तक इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं हुई है जबकि मध्य प्रदेश सरकार पिछले चार वर्षों से लगातार इस परियोजना को प्राथमिकता की सूची में रखकर केंद्र सरकार को भेज रही है परंतु केंद्र सरकार की ओर से लगातार इसे अनदेखा किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत सरकार, जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार तथा अन्य अधिकारियों के साथ लगातार पत्राचार किया परंतु अभी तक इस विषय में कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई है। वर्तमान में भी मैंने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री तथा केंद्रीय वित्त मंत्री जी को इस संबंध में पत्र लिखा और इस विषय को पिछले दो सत्रों में लोक सभा में भी उठाया। इसमें भी पिछली यू.पी.ए. सरकार की तरह ही प्रश्नचिन्ह लगाकार 7 जनवरी, 2015 को पुनः मध्य प्रदेश सरकार को भेज दी गयी है।

अतः केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि महाकौशल प्रांत के गरीब किसानों की लम्बी चली आ रही इस मांग को तथा इससे जुड़े उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का एक समय सीमा के अंदर निर्धारण कर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने की कृपा करें।

(vi) Need to provide rail connectivity between Sambhal and Gajraula in Uttar Pradesh

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल) : मैं सरकार का ध्यान ऐतिहासिक नगर अपने लोक सभा क्षेत्र सम्भल की ओर आकृष्ट करा रहा हूँ जहाँ 68 तीर्थ हैं। उत्तर प्रदेश में सम्भल एक ऐसा जिला है जहाँ से आगे रेलवे लाइन न होने के कारण ट्रेन वापस आती है। मुरादाबाद से केवल एक पैसेंजर ट्रेन सम्भल जाती है। सम्भल से किसी भी ओर आगे लाइन नहीं है जिस कारण ट्रेन मुरादाबाद से जाती है और मुराबाद ही वापस आती है। इस कारण पूरे क्षेत्र के लोग रेल यात्रा से वंचित हैं और कारोबारी व्यक्ति भी अपना कारोबार नहीं कर पाते हैं जिसको सम्भल से गजरौला मेन लाइन से जोड़ा जाना आवश्यक है जिससे अन्य ट्रेनें भी सम्भल होकर गुजर सकती हैं और क्षेत्र के लोग उसमें यात्रा कर सकते हैं। अपने कारोबार के लिए भी बाहर आ-जा सकते हैं।

अतः रेल मंत्री से मेरा निवेदन है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र सम्भल के लोगों की भी चिंता करते हुए इस बजट में शामिल कर सम्भल से गजरौला तक रेलवे लाइन यथाशीघ्र बनवाने की कृपा करें।

(vii) Need to revive multipurpose projects for development of various facilities in Ballia Parliamentary constituency, Uttar Pradesh

श्री भरत सिंह (बलिया) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र बलिया के बसन्तपुर ग्राम सभा में बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट को पुनः सुचारू रूप से संचालित करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

मेरे संसदीय क्षेत्र बलिया के बसन्तपुर ग्राम सभा में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अत्यधिक राजस्व व्यय करने के बाद भी 215 एकड़ भूमि पर बने बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं ठप्प पड़ी हैं, जैसे कृषि अनुसंधान केंद्र, एशिया का सबसे बड़ा फौव्वारा, गेस्ट हाउस (वन विभाग), पौधशाला, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैंटीन, भोजपुरी सांस्कृतिक केंद्र , तारा मंडल हिस्ट्री म्यूजियम, वृद्धा आश्रम, चिल्ड्रेन पार्क, ऑडीटोरियम, दूरसंचार विभाग का गेस्ट हाउस, कृत्रिम झील, कृत्रिम पुल आदि कुछ वर्षों से बंद पड़ा है। यह बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट उचित देखभाल के अभाव में जंगल परिवर्तित हो रहा है।

अतः केंद्र सरकार से मेरा आग्रह है कि बलिया के बंद पड़े बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट को पुनः सुचारू रूप से संचालित करने के आदेश संबंधित विभाग को देने की कृपा करें जिससे क्षेत्र के चहुँमुखी विकास के साथ-साथ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, युवाओं को रोज़गार मिलेगा और नवयुवकों का पलायन बंद होगा।

(viii) Need to augment railway services in Mahasamund Parliamentary Constituency in Chhattisgarh

श्री चंदूलाल साहू (महासमन्द) : मेरे संसदीय क्षेत्र महासमन्द, छत्तीसगढ़ में जनता की कठिनाईयों को देखते हुए माननीय रेलमंत्री कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें :

1. रायपुर से धमतरी छोटी लाइन को बड़ी लाइन किया जाए।
2. रायपुर से राजिम छोटी लाइन को भी बड़ी लाइन करते हुए इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए गरियाबन्द, मैनपुर होते हुए देवभोग से उड़ीसा कर दिया जाए।

गरियाबन्द, मैनपुर एवं देवभोग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं जो विकास से कोसों दूर हैं। रेल सुविधा होने से इन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासी भाईयों को विकास की गति मिलेगी।

(ix) Need to revive Barauni Fertilizer Factory in Bihar

डॉ भोला सिंह (बेगूसराय) : नेप्था आधारित बरौनी उर्वरक कारखाना चालू अवस्था में ही 2002 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में यह कहते हुए बंद किया गया था कि इसे चलाना लाभप्रद नहीं हैं और जब गैस आधारित उर्वरक कारखाने खोले जायेंगे तो बरौनी उर्वरक कारखाने को प्राथमिकता दी जायेगी। इस कारखाने को बंद हुए 13 वर्ष हो गये हैं, पर इस दिशा में अपेक्षित कदम उठाने में अभी भी तत्परता नहीं बरती जा रही है। हल्दिया, जगदीशपुर पाइपलाइन जिसकी शाखाएँ गोरखपुर, बरौनी की ओर से भी जाने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, और इसके लिए लगभग 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट भी तैयार किये गये हैं, पर अभी तक उर्वरक कारखाने बनाने के लिए किसी प्रतिष्ठित एजेंसी के साथ इकरारनामा जिम्मेदारी तथा कार्य करने के आदेश नहीं दिये गये हैं। इस दिशा में गोरखपुर उर्वरक कारखाने को चालू करने के लिए एजेंसी निर्धारित हुई है। पूर्व के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के आश्वासन अभी भी आकृति ग्रहण नहीं कर पा रही है। इससे बिहार की जनता में आक्रोश व्याप्त है। मैं केंद्रीय उर्वरक कारखाने को खोलने की तत्काल व्यवस्था करें।

(x) Need to send a medical team to contain the spread of Monkey Fever disease in Wayanad district in Kerala.

SHRI M.I. SHANAVAS (WAYANAD): There is a sudden and alarming rise in Kyasanur Forest Disease (KFD), or Monkey fever in various parts of Wayanad district in Kerala. Most importantly several tribal hamlets have been affected by the outbreak of this disease. Taking into consideration the gravity of the issue, I would urge the Union government to immediately send an expert team of doctors and specialists to supplement the state government's efforts in launching preventive measures against the spread of Monkey fever in Wayanad. In addition to this, the families of the deceased must be granted a solatium of Rs. 3 lakh each.

As regards the preventive steps to be taken, I would urge the government to establish a permanent facility with the help of National Institute of Virology or other relevant centres for regular surveillance and testing of virus at regular intervals.

(xi) Need to impress upon the Government of Kerala to undertake repair of Shenbagavalli dam to facilitate release of water to Tamil Nadu

SHRIMATI M. VASANTHI (TENKASI): Shènbagavalli Dam situated in Kerala was constructed after arriving at an agreement between Sivagiri and Tiruvangur Samasthan in the year 1773 on Shenbagavalli River. Tens of thousands of farmers in Sivagiri Sankarankoil taluks in Turnelveli district and Rajapalayam taluk in Virudhunagar district have been affected because of the non-availability of water from the dam. People are fully depending on this Dam for drinking water and irrigation. Steps are being taken by the Government of Tamil Nadu and a sum of Rs. 10.29 lakh was deposited with the Government of Kerala as per their request to repair the Dam. But no fruitful action has been taken till now.

Later on, Kerala Government had taken a stand not to carry out any repair work based on the amendment to Kerala Irrigation and Water Conservation Act, 2003. But the amendment was struck down by the Supreme Court in the Mullaperiyar Issue.

Therefore, in this situation I urge upon the Government to intervene and take swift action to solve the issue amicably to help Tamil Nadu to protect the livelihood of the general public and the farmers who are solely depending for drinking water and irrigation of 35,000 acres of land on this dam.

(xii) Need to grant permission as well as financial assistance for replenishing ground water in arid zones of Coimbatore, Erode and Tiruppur in Tamil Nadu

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR):The ground water level in the arid zones of Coimbatore, Erode and Tiruppur has gone to an alarming depth of 1000 to 1500 feet. If this situation continues, there may be a need to notify them as desert areas. Paucity of drinking water has not only affected the human population in these areas but also flora and fauna.

The Public Works Department of Tamil Nadu has come out with a novel proposal to recharge ground water in 75 lakes, 438 small ponds at a proposed cost of Rs. 1862 crore by supplying 2 Tmc of excess water collected in Bhavani Dam through the Athikadavu-Avanashi water distribution system.

The application for permission as well as financial allocation for the above scheme was prepared by our Hon'ble Chief Minister of Tamil Nadu and submitted to the Hon'ble Prime Minister of India on 3 June 2014. Technical flaws and difficulties in this scheme are being seriously reviewed by PWD officials and very soon the details of the scheme will be handed over to the Government of Tamil Nadu for implementation.

To fulfill the long standing demands of 35 lakh people of four Parliamentary constituencies of Tiruppur, Erode, Coimbatore and Nilgiris and 13 Assembly constituencies, I would request our Hon'ble Prime Minister to grant permission as well as financial assistance for successful completion of this project at the earliest.

(xiii) Need to check the steep hike in prices of thread and yarn

DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY): I wish to bring to the notice of the Government exorbitant hike in the prices of thread and yarn particularly in the last couple of years. It is a very serious matter as it has affected acutely thousands of weavers in the handloom and powerloom sector of rural West Bengal. It would not be an exaggeration to state here that the hike in the prices of thread and yarn has created a crucial problem, as these are the only raw materials for the handloom and powerloom industry in West Bengal. Prices of cotton yarn have gone up steeply. Of late, the price of Tussar silk too has gone up. So is the case with other materials. There is a need to initiate immediate and urgent measures to check the price hike otherwise weaving industry would suffer a great deal and the poor weavers would have to the face the brunt of this huge hike. As the Hon'ble Minister is aware, the West Bengal is a major producer of thread and yarn and next to agriculture, weaving is the major industry in West Bengal. Hence, I strongly urge the Government to take measures on war-footing to address this issue.

(xiv) Need to sanction financial as well as technical assistance to provide safe drinking water in the Nuapada district of Odisha

SHRI ARKA KESHARI DEO (KALAHANDI): According to the Ministry of Drinking Water & Sanitation, the fluoride content in water has been found in 229 villages in Nuapada district of Odisha as per the 2014-15 report. The people of Boden, Komna, Sinapalli, Nuapada & Khariar blocks of the above said district are not able to get safe drinking water. I request the Government to sanction financial as well as technical assistance to provide safe drinking water in the above mentioned blocks of Nuapada district.

(xv)Need to address the problems of physically challenged STD/PCO booth operators at railway stations including the hassles being faced by such railway passengers in trains

SHRI RAHUL SHEWALE (MUMBAI SOUTH CENTRAL): I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister of Railways towards the financial hardships faced by Handicapped persons who have been allotted STD/PCO booths on Railway Stations/platforms. Due to vast increase in communication services like mobile etc. the business of STD/PCO booths has gone down heavily. As a result, the handicapped persons who are solely dependent on these services are finding it difficult to make a livelihood. In view of the above, a number of Parliament Members have suggested to the Ministry of Railways for granting permission to STD/PCO booth operators to sell certain items like packed snacks, biscuits, popcorn and drinking water etc. to enable them to supplement their income. No action has been taken so far on this proposal.

I am given to understand that recently the permission for the sale of above said certain items has been granted to the Miscellaneous Articles Contractor vide Ministry of Railways (Railway Board) order No. 2006TG-lll/461/3 dated 2 November, 2012. So the benefit can also be given to handicapped STD/PCO booth operators.

I would like to also point out the problem of handicapped passengers being faced by them on Suburban Railway and long distance trains. That the seats/berths reserved for them are being occupied by general passengers. Also the coach reserved for the handicapped persons in local trains is being occupied by general passengers. My request to the Hon'ble Minister is to kindly look into the matter seriously and make arrangement to give relief to the handicapped persons.

(xvi) Need to bring in more transparency in implementation of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): The Government's financial inclusion scheme, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, is an empty shell at the moment. As on January 7, banks have collectively opened 10.84 crore basic savings bank accounts under the Yojana. About 73 per cent (or 7.88 crore) of these are zero-balance accounts. Is this a financial inclusion in true sense? There are many misconceptions about the benefits provided under this scheme. There are endless anecdotes about how unbanked persons rushed to open accounts assuming it would immediately give them Rs. 5,000 in cash (overdraft) and the ability to encash Rs 1 lakh in insurance. Moreover, all accounts with zero balance (73%) cannot even avail this benefit as the facility is available on the basis of credit and transaction history. The pressure behind achieving the numbers was so strong that bankers were taking the same set of people from one bank to another to open multiple accounts. Multiplicity of accounts in the name of same person is a serious operational risk. It will take huge time and money later in weeding out of dormant and multiple accounts. I urge the government to take immediate action to bring more transparency and effective implementation of the scheme to ensure financial inclusion and not just achieving targets.

(xvii) Need to take effective steps to make river Yamuna pollution free

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): The Central Water Commission has recently declared that the water of river Yamuna is safe neither for irrigation nor for domestic use due to its 50 times more contamination level of biochemical oxygen demand than the permissible limit. The untreated industrial and sewage effluent is polluting the Yamuna basin continuously leading to various lethal diseases including cancer, Hepatitis C among people residing in Faridabad, Palwal of Haryana. Haryana has been affected due to Delhi contaminating this river. Therefore, I urge the government to initiate project on the line of River Gang to clean River Yamuna and allocate adequate fund in the current Budget. I also request the government to instruct the government of Haryana and other state governments to take effective steps to protect this river and to shift industries releasing chemical residues into the river.

(xviii) Need to review the Dr. Meena Kumari report on deep-sea fishing

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The recommendations of Dr Meena Kumari committee are against the interests of fisher folk in the country. The Government implemented the recommendations of the committee even without considering the suggestions of the stake holders. Deep sea trawling was permitted in violation of the assurance given in the House. The suggestion is that Indian crew may not be qualified enough to man operations in this water and foreign hands should be deployed. The panel ignored the fact that Indian fishermen are already operating in water beyond 500 meters. The recommendations of the committee are against the spirit of Murari committee. The present report will help to lease out the marine territory of India to foreign ships and foreign crew.

Hence I urge upon the government to reject the Dr Meena Kumari committee report.

14.02 hrs

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS – Contd.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up further consideration of the following motion moved by ShriAnurag Singh Thakur and seconded by Shri Nishikant Dubey on 24th February, 2015:

"That an Address be presented to the President in the following terms:-

'That the Members of the Lok Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the President for the Address which he has been pleased to deliver to both Houses of Parliament assembled together on February 23, 2015'."

Shri Arvind Sawant to continue.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, कल जब मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट कर रहा था तो लैंड एक्वीजिशन कानून पर आया था। हम जनतंत्र को मानते हैं। किसानों की सहमति के बिना उनकी जमीन अधिग्रहण करना उचित नहीं होगा। हमारी सरकार कहती है 'सबका साथ सबका विकास' तो क्या हम नहीं चाहते कि हमें किसानों का साथ भी चाहिए, किसान भी हमारे साथ रहें? मुझे नहीं लगता कि किसानों को दुखी करना हमारी सरकार के लिए उचित होगा। हम एक तरफ कहते हैं कि किसान हमारी खाद्य सुरक्षा का प्रहरी है। 'अन्नदाता सुखी भव:' इस संस्कार को लेकर हम किसान को धन्यवाद अदा करते हैं। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की बात करती है। हमने मृदा वर्ष घोषित किया और प्रधान मंत्री सिंचन योजना भी घोषित की। जब मेरे पास जमीन ही नहीं रही तो प्रधान मंत्री सिंचन योजना का क्या होगा। यहां कृषि मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बाहर माहौल बहुत गंदा हो रहा है। वे बहुत दुखी हैं। हम एक तरफ उन्हें खुशहाल देखना चाहते हैं, उन्हें प्रधान मंत्री सिंचन योजना के तहत लाना चाहते हैं, फसल अच्छी हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण के तहत उनसे बिना पूछे, बिना सहमति, बिना कानून उनकी जमीन ले लेंगे, यह जो भय उनके मन में निर्माण हुआ है, उसका निराकरण हमारी सरकार को करना होगा। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार उस तरफ भी अपना कदम उठाएगी और आगे चलकर, क्योंकि, उसमें कुछ अच्छी चीजें करना चाहती थी, लेकिन जनतंत्र को लेकर वे काम नहीं हो रहे हैं, वे जनतंत्र के आधार पर होने चाहिए। किसानों को दुखी करके ये काम न हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है।

माननीय सदस्य निशिकांत दूबे जी ने लोहिया जी की बात याद दिलाई और यूनीफार्म प्राइमरी स्कूल की बात की। दूबे जी, मैं आपको याद दिलाता हूं कि जब मैंने पहली बार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपना मत व्यक्त किया था, उस वक्त भी मैंने यही कहा था, प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में सिलेबस सेम होना चाहिए। भाषा का माध्यम कुछ भी हो, तमिल हो, मराठी हो, हिन्दी हो, जो भी माध्यम हो, लेकिन सिलेबस सेम हो। आज जो डिस्क्रिमिनेशन पैदा हुआ है, उसकी वजह सिलेबस है, क्योंकि, सिलेबस सेम नहीं है। आज गांव में रहने वाला छात्र इन सारी चीजों से वंचित है। दूसरी तरफ सरकार ने एक अच्छी बात की है, अब शिक्षकों को भी अच्छी शिक्षा देने के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम तय किया है। मैं इसकी सराहना करता हूं, स्वागत करता हूं। अगर आधुनिक शिक्षा देनी है तो उसके लिए शिक्षक को भी पात्र होना होगा। मेरी सरकार उस तरफ ध्यान दे रही है, सरकार को सिलेबस के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तभी प्राइमरी स्कूलों में यूनिफार्मिटी आएगी। आई.सी.एस.ई या सी.बी.एस.सी या सेन्ट्रल बोर्ड की

शिक्षा का स्तर ऊंचा करना है। हमारे पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों में जाने वाले छात्रों को उनकी शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के लिए एक वर्चुअल क्लास रूम शुरू किया है, वर्चुअल क्लास रूम में सबसे अच्छे शिक्षक को बुलाया जाता है, जो उस विषय के विशेषज्ञ माने जाते हैं, एक ही साथ 200-250 स्कूलों में दसवी कक्षा के बच्चों को किसी एक विषय में पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद अगर उनके मन में शंका होती है, उनकी शंकाओं का निराकरण भी वर्चुअल क्लास रूम से ही होता है।

महोदय, आप खुश होंगे कि म्यूनिसिपल स्कूल में जाने वाले बच्चों के पास होने का स्तर बढ़ गया, उनके अंक बढ़ गए और स्कूलों में पास होने का परसेंटेज भी बढ़ गया। यह सरकार उस तरह से अच्छा काम करेगी, यह मैं अपेक्षा करता हूं। मैं रूडी साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि आप कौशल विकास के मंत्री भी हैं, मैं बहुत खुश हूं। Let me appreciate you wholeheartedly. An young and dynamic leader like you should take keen interest in that. आई.टी.आई. अलग-अलग क्षेत्रों में बंट गया है, आधुनिकता आ गई है, तंत्र ज्ञान भी बढ़ गया है, उसको लेकर आई.टी.आई. में आना चाहिए। एक बात मुझे हमेशा दुखी करती है, जब हम रास्ते पर जाते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, हमारे देश में भीख मांगने वाले बच्चों की संख्या बहुत है, सरकार ने क्या इस बारे में कभी सोचा है? उसका बचपन खो गया, वह रास्ते पर सोता है, रास्ते पर पढ़ता है, जो कपड़े मिल जाए उसी को पहन लेता है, नंगे पांव रहता है, धूप में, बरसात में घूमता है, हम लोगों को उसके लिए कुछ करना होगा। उसका रिफ्लेक्शन यहां नहीं है। मैं सरकार का इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम बच्चों को भीख मांगने में नहीं लगाएंगे, इस देश का कोई भी लड़का, कोई भी बच्चा भीख नहीं मांगेगा, इसको लेकर कुछ योजना आनी चाहिए। आपने हुनर के बारे में बात की, हुनर है, लेकिन उसे ढूंढना पड़ेगा, आप स्पोर्टस में भी देख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक बात याद आती है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि दसवी कक्षा पास हो गया, अगर वह बच्चा आई.टी.आई. में पास होता है तो उसका भी मूल्य दसवी कक्षा पास जैसा समझना चाहिए। बाजार में उसकी वैल्यू कम नहीं होती, उसको कहा जाता है कि तुम आठवी कक्षा पास है, यह कौन सी बात है If he passes the ITI training course or something like that, then we should treat that he possess the ITI certificate. स्वास्थ्य सेवाओं में भी बाल मृत्यु दर घटाने की बात हो रही है, खासकर आदिवासी लोगों में इसकी दर बहुत ज्यादा है। जब हर्षवर्द्धन जी स्वास्थ्य मंत्री थे, तब आयुष विभाग शुरू हुआ था। बचपन में मां के पास जड़ी-बूटी की दवा रहती थी, ग्राइप वाटर आता है, उसी तरह बचपन में मां खिलाती थी, आज जड़ियां-बूटियां नहीं हैं। उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पारंपरिक दवाओं को लेकर आयुष विभाग ने जो योजना शुरू की है, मैं उसका

स्वागत करता हूं। छोटी-छोटी चीजों पर हमारी सरकार ध्यान देती है। एक बात स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई है। हाल ही में मैं कैंसर अस्पताल के डॉयरेक्टर से मिला, उन्होंने कहा कि जब हम जांच करते हैं तो शहरों में रहने वाले लोगों में कैंसर होने की संख्या कम हो रही है और गांवों में ज्यादा बढ़ रही है। क्योंकि, स्वच्छता का अभाव है, इसके लिए मैं प्रधान मंत्री जी की सराहना करता हूं। लोगों को यह बहुत छोटी सी चीज लगी होगी, लेकिन उन्हें पता नहीं कि स्वच्छता के कारण उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम श्रमेव जयते की बात करते हैं। हमारे पास इम्प्लायमैंट एक्सचेंज एक्ट है, जो आज भी अस्तित्व में है। हमारे युवा बच्चे आज इम्प्लायमैंट एक्सचेंज में रजिस्टर करने नहीं जाते हैं, क्योंकि, अब जॉब देने का तरीका ऑन लाइन हो गया है। कौन कहां से आता है, कहां जॉब मिलता है, इसका पता ही नहीं चलता। सरकार के पास कोई आंकडे नहीं हैं कि कितने बच्चे अनएम्प्लायड हैं और कितने बच्चों को जॉब मिला। इम्प्लायमैंट एक्सचेंज होने की वजह से पहले रजिस्ट्री होती थी, जिससे पता चलता था कि कितने बच्चों को जॉब मिली। हमने जो आतंकवादी बच्चे पकड़े हैं, वे आई.टी. की किस कम्पनी में काम करते थे, इसका हमें पता नहीं था। वे कहां से आये, कैसे नौकरी मिली, उसकी कोई भी इन्फोर्मेशन हमारे पास नहीं है। मैं वैंकेया नायडु जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि if the Employment Exchange Act is existing, it should be adhered to. Nothing is being implemented according to that Act. It is almost like abolished. People are getting job, wherever they want it. They are going for interview on-line. The registration is not there as to where that boy has come from and whether he belong to ISI or something. Nothing is known. We have found that the people who are working in the IT sector are prone to that ISI activity and other things. The care should be taken.

मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं । हम लेबर इंश्योरेंस बिल लेकर आये। मैं पी.एस.यूज. को मजबूत करने की बात बार-बार करता हूं, क्योंकि, उसकी एक वजह है। आज सुबह मैं माननीय कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब का उत्तर सुन रहा था। जब डिजीटल इंडिया की बात आयी, तो केरल के एक सांसद ने कहा कि बी.एस.एन.एल. प्रॉफिट में है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। इस सदन में उनके दोनों जवाब आये हैं। छः महीने में हम आगे नहीं गये हैं। हम अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहते हैं, उनकी तबीयत अच्छी देखना चाहते हैं। अब पी.एस.यूज. हमारी सरकार के बच्चे हैं और उन्हें उसे संभालना चाहिए। पी.एस.यूज. डेंजर में हैं, यह बोलना आसान है। एयर इंडिया को डुबाया, यह बोलना आसान है। एयर इंडिया को इस संकट से बाहर लाना ही

आपकी क्षमता है और यह आपकी ताकत बतायेगी। हमारी सरकार उस संकट से एयर इंडिया को बाहर लायी, उस संकट से बी.एस.एन.एल., एम.टी.एन.एल. और बैंकों को बाहर लायी। अगर जन-धन योजना चालू हुई तो वह पब्लिक सैक्टर के बैंकों की वजह से लोगों तक पहुंची, न कि प्राइवेट बैंकों की वजह से पहुंची। ...(व्यवधान) मैं यह अपेक्षा करता हूं कि पी.एस.यूज. की तरफ सरकार ध्यान दे और उसे मजबूत करे। उसके लिए जो भी करना है, वह करे। आज हमारे सहयोगी सदस्यों ने पूछा कि कब टावर लेंगेंगे, तो कहा गया कि अभी लगने वाले हैं। पिछले छः महीने से सब सांसद इस सदन में पी.एस.यूज. के बारे में कह रहे हैं कि एम.टी.एन.एल., बी.एस.एन.एल. की सेवा खराब हुई है। क्या एक टावर नहीं लगता? आठ-आठ महीने तक टावर नहीं लगता। उसकी सैंक्शन के लिए टाइम लगता है। जब मैंने हैंड इन ग्लोव की बात की तो बुरा लगा। मैंने यह बात कही कि कैसे अधिकारी प्राइवेट कम्पनियों से हैंड इन ग्लोव हैं। ...(व्यवधान) मैं दो-तीन छोटी-छोटी बातें बताकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं उन पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, क्योंकि, ये मेरे खुद के विषय हैं। अभी हाल ही में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में जासूसी करने पर काफी लोग पकड़े गये। इसका क्या मतलब है? There are people who are hand in glove with the private sector. They existed in the telecom sector also and still they are existing. जिस दिन कोई रिटायर होता है, उसके दूसरे दिन ही वह प्राइवेट कम्पनी में नौकरी कर रहा होता है। इसका क्या मतलब है? आज कोई बी.एस.एन.एल. से रिटायर हुआ, तो उसके दूसरे दिन ही वह रिलायंस, एयरटेल में नौकरी कर रहा होता है। उन्हें कैसे जॉब मिलती है? They were in touch with them from the beginning. They do not see the well-being of their own company, but they see the well-being of the private entrepreneur. That is what is happening. Therefore, I would request you to take care of this.

मैं एन.टी.सी., यानी नैशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन की बात करना चाहता हूं। हमने टेक्सटाइल में प्रगति की है। पहले मुम्बई शहर टेक्सटाइल मिलों का शहर माना जाता था। आज टेक्सटाइल मिलों के मजदूर रास्ते पर हैं, वे घरों की मांग कर रहे हैं। टेक्सटाइल मिलों के पास जमीन नहीं है। सरकार को उस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह उस तरफ ध्यान दे। हमारी सरकार ने एक अच्छी बात कही, जिसके सुनकर बड़ा गर्व हुआ। यूनिटी का स्टेचू आप वल्लभभाई पटेल जी का बना रहे हैं। इसे देखकर बड़ा गर्व हुआ, अभिमान हुआ। मैं उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे राज्य की सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैच्यू बना रही है, वह उसे समुद्र में बनाना चाहती है, उसके लिए क्या केन्द्र की हमारी सरकार मदद करेगी या नहीं? हमारी सरकार ने वहां पर बाबा साहेब डाक्टर अम्बेडकर के लिए एन.टी.सी. मिल की जगह मांगी, वह आपके पास प्रलम्बित है। इन दोनों के बारे

में इसमें जिक्र नहीं आया है, मैं चाहता हूं कि इन पर भी हमारी सरकार ध्यान दे। सोलर एनर्जी के ऊपर ध्यान दें।

आखिर में, मैं इतना ही कहूंगा कि नमामि गंगे की जब बात आती है, गंगा की तरफ जो ध्यान दिया गया, मैं उसका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में नासिक में अभी कुम्भ मेला होने वाला है। गोदावरी नदी प्रदूषित हुई है। त्रयम्बकेश्वर में उसका उद्गम है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। साधुओं ने आंदोलन का आह्वान किया है, अगर सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी तो वे गन्दे पानी में स्नान नहीं करेंगे, ऐसी धमकी उन्होंने दी है। आप उस पर ध्यान दें।...(व्यवधान) मैं एक वाक्य और कहना चाहूंगा।

HON. DEPUTY SPEAKER: All Members are interested to have rivers in their States cleaned; they want the Government to look into the matter.

श्री अरविंद सावंत : फिर भी मैं इस सरकार पर विश्वास रखता हूं, मुझे लगता है कि हमारे प्रधान मंत्री जी इसके बारे में ध्यान देंगे। मेरी सरकार कोशिश करने वाली है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा:

"लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।"

HON. DEPUTY SPEAKER: Hon. Members, those who wish to submit their written speeches are allowed to do so. They can submit their speeches at the Table. That is to be allowed.

Shri M. Venkaiah Naidu, Hon. Minister, to intervene in the debate.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Hon. Deputy-Speaker, Sir, I would like to intervene in this discussion for conveying thanks to the hon. President for his valuable address to this House.

Sir, the President's Address started with the words, "The greatest strength of India is her rich spiritual and civilisational heritage." We Indians feel proud of our culture, our heritage; and we always talk about it. Some people unfortunately do not like this, but we cannot help it. This is a vision and this is the commitment of this Government that we have to preserve the cultural and spiritual heritage of this land which is given to us by our forefathers over thousands of years of civilization. आदिकाल से, वेद काल से, पुराण काल से, जो हमारे पूर्वजों ने लिया और दिया, विरासत में हमें मिला, उस पर हमें गर्व महसूस करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी फिलॉसफी है - सबका साथ, सबका विकास। All together, development of all. ...(व्यवधान) यह अच्छा नहीं है। ...(व्यवधान) हमें अपनी जिम्मेदारी याद है। इतना भारी बहुमत हमें जनता ने दिया, हमारी जिम्मेदारी क्या है, यह हमें मालूम है।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : भारी बहुमत दिया था, लेकिन दिल्ली चुनाव में भा.ज.पा का क्या हाल हुआ? ...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : अगर मुझे अभिनन्दन करना है तो मान का अभिनन्दन करूंगा, उनको सम्मान मिला, आपको अपमान मिला। आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं?

Sir, eight State Assemblies went to polls after Parliament elections. In seven States, the BJP and the NDA have won the clear mandate. This has to be understood. And the people who are objecting and who are trying to interrupt me are being reduced, reduced and reduced. They have to understand this. I do not want to join a slanging match, but my friends must have some patience.

We had patience for fifty years. All these people who are sitting here, they all sat in patience for fifty years, have undergone all the suffering. You enjoyed

the power. Please have patience for another five years. That is my suggestion to you.

SOME HON. MEMBERS: Another fifteen years.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The main issue today is poverty elimination. That is the issue today. And that is the Mantra and that is the guidance that our leader hon. Prime Minister has given to us. That is what the President's Address also stresses upon. How do you do it?

Sir, poverty is a bane to dignified human existence. Development is accentuated only when the last person gets a sense of fulfillment. It did not happen in the last 50-60 years. After 68 years of independence, 68 per cent of rural India has no access to some of the basic needs like toilets and 26 per cent are below poverty line, 38 per cent cannot read and write. What is more saddening, at certain places hunger deaths are happening and at certain places farmers are committing suicide. It is a challenge to all of us and this entire House and this Parliament should accept the challenge and concentrate our efforts and focus in seeing to it that these challenges are addressed to. If we start blaming each other, I can only tell you that will end in a futile exercise because people have seen who has been in power out of 68 years; how many years that side was in power, how many years this side was in power and how many years the people who are sitting in the middle also joined power. So that is a fact of history. I am not going to change it. I am not going to talk about a particular Member.

Today morning, while replying to a question, I said there is shortage of 1.8 crore housing units in the country. This is a challenge. At a number of places, power is supplied only 4 or 6 or 8 hours in a number of States. That is a challenge. Some of our friends were talking about lack of potable water. That is a challenge before us. Some of our friends were complaining about the quality of the mid-day meal, that is a challenge. Some of our friends have been complaining about the treatment given to women. That is the biggest challenge for all of us. My point is, we must now focus on development. That is what the President's

Address is stressing, that is what the Prime Minister of India wants. The focus should be on development and speedy development and development alongwith good governance. केवल विकास से ही काम नहीं होगा, विकास के साथ-साथ सुशासन भी होना चाहिए, नहीं तो जनता तक फायदा नहीं पहुंचेगा, आम आदमी तक फायदा नहीं पहुंचेगा। इस बात को हमें गम्भीरता से स्वीकार करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद अभी तक जो भी काम किया, सुशासन की दिशा में ही काम किया और आगे भी उसी दिशा में करते रहेंगे।

मेरे मन को बहुत खुशी हुई, मैं कल रात बहुत इम्मोटिव था, कारण यह है कि कल सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने का जो निर्णय हुआ और उसे सदन के समक्ष रखा, उससे पूरी दुनिया में भारत के फैडरल सिस्टम के बारे में चर्चा हो रही है।

हमारे प्रधान मंत्री जी पहले मुख्य मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। उस समय भी उन्होंने जो अनुभव किया, वह हमेशा बताते रहे। उनका तब भी यही कहना था और अब भी कि जब तक राज्य मजबूत नहीं होंगे, देश को मजबूत करना सम्भव नहीं है। हम उस पर विश्वास करते हैं। जब तक तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, वैस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, कहने का मतलब यह है कि सब राज्य मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश मजबूत होना सम्भव नहीं है। प्रदेश के बिना देश अधूरा है, इस बात को हमें गम्भीरता से लेना चाहिए।

For the first time, 42 per cent of the Union tax receipts will be devolved to the States. This is a historical decision. Also, Grants to local bodies and municipalities are increased. The 73rd and 74th Amendments which were brought during Shri Rajivji's period have not become a full reality because many of the States have not devolved funds, functions and functionaries to the local bodies. Whether it is this Government or that Government is a secondary issue but the fact of the matter is, 29 subjects were supposed to be devolved to the local bodies, but that has not happened fully. They are also starving for funds. Being a municipal administration minister or Urban Development Minister, I have been receiving representations. That has also been taken care of. Nearly 4 to 5 per cent of funds are now sent directly to the local bodies and they are going to be strengthened.

The third one is the States which are having Revenue deficit for other reasons, historical or whatever they may be. States which are continuously

affected by natural calamities are also being considered. States which are performing better and have a better fiscal discipline have also been taken care of.

The Khusro Commission recommended 29.5 per cent; the Rangarajan Commission recommended one per cent increase; the Vijay Kelkar Commission recommended two per cent increase. This time, during this Government, there is ten per cent increase for the first time in the history. It is ten per cent plus what goes to the local bodies, plus what goes to disaster mitigation and relief, plus what goes to the well performing States, plus what goes to cover revenue deficit. In the history of India, this will be a golden letter day and the people in the States will all be enjoying it. This has happened in spite of one of the Members of the Finance Commission giving a dissenting note cautioning the Government that the States will be rich but the Centre will be poor. It was Shri Abhijit Sen's view. He has got every right to have his view but the Government in its collective wisdom and the Cabinet presided over by our hon. Prime Minister who believes in the philosophy of strengthening the States and then strengthening the country has accepted these recommendations fully and they are now going to be implemented.

There is going to be a sea change with regard to the finances of some of the States. Compared to 2013-14, States would now get Rs. 1,75,000 crore-plus extra money and local bodies will get Rs. 2.87 lakh crore in the next five years. As an Urban Development Minister, as I told you, I am very happy about it and the entire country is also rejoicing. All the Chief Ministers, whichever party they belong to will also be more than happy at this radical altering in the Centre and States' relations. The total transfer will now amount to 47 per cent of divisible pool tax and also five per cent for local bodies and also the other things I have said. Rs. 1.94 lakh crore grant will be given to 11 revenue deficit States like Andhra Pradesh, West Bengal, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, etc. Andhra Pradesh will get an additional money for revenue deficit for the coming five years because it is revenue deficit not because of any other reason. The country will move forward only when the States develop as I said. Earlier, it was

devaluation; now, it is devolution. It is a revolution. It is the evolution of the Narendra Modi Government that this devolution has taken place in such a short time. People used to call our Prime Minister 3D; they used to say, 'Modi means 3D'. … (*Interruptions*) I said people, not you. Your leader is not here; you cannot say anything. They used to say, 'Mr. Modi means 3D'; he is 4D now – decisive, dynamic, development and devolution to the States. That is the revolution he has brought. That is why he will be seen as 4D. … (*Interruptions*) He may talk about his leader. I have no objection. His leader is not there. He is out of the country. … (*Interruptions*)

You see the objective of the NITI Aayog, the National Institution for Transforming India. It is a very important thing – transforming India into a developed country, into a strong country, into a strong economy and a self-respecting economy. That is the idea behind NITI Aayog. That is why we call it, National Institution for Transforming India.

Today, all the Chief Ministers are equal partners in the Governing Council of the NITI Aayog for the first time because the hon. Prime Minister said that we have to work as 'Team India'. We have to really implement co-operative federalism. That is the spirit with which we have to work. Even in the President's Address also that point has been stressed because we want to have development of all the States together, we want all to work with all the States together, we want them to be equal partners in development and we want to work as 'Team India'. We are committed and have initiated measures to stir action in every field right from sanitation to smart cities, poverty elimination to creation of wealth, skill development to conquering space, tapping demographic dividend to diplomatic initiatives, enhancing ease of doing business to putting in place a stable policy framework, empowering individuals to ensuring quality infrastructure, ending financial untouchability to making the country a manufacturing hub, containing inflation to stimulating economy, igniting minds to ensuring inclusive growth,

promoting cooperative federalism to encouraging a competitive spirit among the states.

- Igniting minds to ensure inclusive growth.
- Promoting cooperative federalism to encourage a competitive spirit among the States.

This is the direction in which we are moving. I do not know why anybody should have any objection.

In the last nine months, the overall inflation, which was at 11.16 per cent in November 2013, has dropped to a record low of 4.38 per cent. Wholesale Price Index (WPI) inflation which was at 6 per cent in 2013-14 declined to 0.1 per cent in December 2014. Food inflation, which was at 9 per cent in 2013, has declined to 4.1 per cent in December, 2014. Consumer Price Inflation (CPI) – not our CPI – which was 12.5 per cent in 2013 has declined to 4.8 per cent in December, 2014. It had come down to 5.6 during last 10 years. Now growth in GDP during 2014-15 is estimated at 7.4% as compared to 6.9% in 2013-14. Growth rate of GDP was 4.6 per cent when we left the regime. At this rate, going by the spirit of the Presidential guidance given by the Government to this House, the country will progress. I am sure, in the coming years India will be reaching the highest growth rate in this entire region. That will become a reality. I am sure about it.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, can I interrupt for a minute?

HON. DEPUTY-SPEAKER: Let him finish.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, you spoke for 60 minutes. I did not interrupt you. If you want to speak, I do not mind.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : I am asking for your permission. I will never interrupt you. In a parliamentary democracy, if you will yield then only I will speak. You have quoted 7.4 per cent growth rate. I have already explained it. Probably at that time you were not in the House but the hon. Prime Minister was here. Which is the base year for the 7.4 per cent growth rate and which is the base

year for 5 per cent growth rate under the UPA Government? You are taking 2004-05 as the base year for 5 per cent growth and the base year you are taking for 7.4 per cent growth is 2011-12. So, if you take 6.9 per cent growth rate of the UPA Government and your growth rate of 7.4 per cent the difference, even if you exercise too much, is hardly 0.4 per cent.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This has happened in nine months.… (*Interruptions*) Sir, please have patience. You are not able to accept any small criticism. Having been in power and having been responsible for all the ills of the country, you are not able to even have a small criticism. You are saying that we achieved growth rate of 0.5 per cent in nine months. Is it an ordinary achievement? 8.4 per cent was what Vajpayee ji's Government had left and you have successfully brought it to 4.6 per cent.

In the last Budget the income tax exemption ceiling was enhanced from Rs.2 lakh to Rs.2.5 lakh under 80C. Sir, the investment limit was also enhanced from Rs.1 lakh to Rs.1.5 lakh. The idea was to encourage small savings.

For improving the road connectivity in rural areas, Rs.14,389 crore was sanctioned under PMGSY. Allocation for National Housing Banks increased to Rs.8000 crore to support rural housing. Under Ajeevika, a provision of bank loan for women self help groups at 4 per cent was extended to another 100 districts. Women, youth, poor and farmers are our real targets and we want to strengthen and enable them to become equal partners in the life of the country. Everything my Prime Minister does, he thinks particularly about the poorer sections. After 68 years if this is the situation, it is a challenge to all of us.… (*Interruptions*) I am coming to that, Sir. I will tell you what your Government has done and what we want to do. Some development to be included in the list of Corporate Social Responsibility and that is also an initiative taken by our hon. Prime Minister.

Now financial inclusion is critical to poverty alleviation. Our Government has launched an ambitious programme called Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana under which 13.2 crore new bank accounts have been opened with around

Rs.11000 crore being deposited. The beneficiaries will get Rupay Debit Card with in-built insurance cover of Rs.1 lakh. This is the initiative taken for the common man and for the poor people. If it is so simple, why did the other Government not take it up all these years?

They are saying that it is not cent per cent coverage. When we talk of cent per cent or 99 per cent, we are talking about families. We never claimed that each and every individual is covered 100 per cent. Our Prime Minister's aim is to see that every person of India will have a bank account in India. That is the purpose of our Government and I am sure we will be able to reach it also. The other regimes have allowed bank accounts to be opened outside India. We have allowed bank accounts to be opened here in India. That is the difference.

The Direct Benefit Transfer Programme is being expanded to different parts of the country. The biggest Direct Cash Transfer Programme in the world has been taken up by this Government of Shri Narendra Modi. The biggest Direct Cash Transfer programme in the world, PAHAL, for transfer of LPG subsidy, has been extended across the country from 1st January, 2015, so far covering 76.6 per cent of the user-households and Rs.5920 crore has been transferred since announcement of the scheme. The poor people need not pay any money. The BPL people will get the connection. The money will be put in their bank account. Around 76.6 are covered and we want to link it with Adhaar so that there is no problem at all. It will be a hassle-free availability of LPG to all people.

'Swachh Vidyalaya' launched to construct a toilet in every school before 15th August, 2015. That is also an ambitious programme of our Prime Minister. जो हमारी बालिकाएं स्कूल जा रही हैं, हमारे गरीब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए टायलेट की व्यवस्था करना भी हमारी प्राथमिकता है।

For skilled India" - 'Skill, Scale and Speed' that is the *mantra* our hon. Prime Minister has given. It is the need of the hour. That is what has been mentioned in the President's Address also. A separate and full-fledged Ministry of Skill Development has been created for the first time in the history of the

country and a young and dynamic Minister has been given that responsibility also. In the coming days, all the skill development programmes will be coordinated.

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : वह मुश्किल डिपार्टमैन्ट है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : मुश्किल डिपार्टमैन्ट यंगस्टर्स टेकल कर सकते हैं, भर्तृहरि जी आपको मालूम है। ...(व्यवधान) मुश्किल है, मगर असंभव नहीं है। ...(व्यवधान) मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, बेकार चिंता मत करो।...(व्यवधान) स्किल है, दिल है, विल है, सब कुछ है।

For SC, ST, OBC, and minority communities, a new scheme "Upgrading the Skill and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD)" is being launched to take care of the vulnerable sections. That is also our programme.

Van Bandhu Kalyan Yojana for the welfare of our tribal friends who are living in the forest area has been launched. Then "Housing for All" by 2022 to cover all the poor both in the urban areas as well as in the rural areas is also launched.

Coming to agriculture, we are all concerned about the health of the people. My Government is not only concerned about the health of the people, we are also concerned with the health of the soil. It is because soil is the basic input for the agriculture. That being the case, we are introducing Soil Health Card.

Then, a corpus of Rs. 500 crore has been set up for perishable commodities. Tomatoes, potatoes and onions, they are seasonal and get perished. We do not have refrigerated vans. We do not have cold storage units. We do not have much needed food processing units. To take care of all this, the Ministry of Agriculture has come forward to take care of the vulnerable sections of farming community who are depending on the perishable products.

Sir, for creating infrastructure in rural areas, a special fund of Rs.2000 crore to provide affordable credit to units, in 72 notified parks have been made operational in the entire country. That is for the farmers.

Nanaji Deshmukh Scheme is being launched for construction of hostels, for De-notified, Nomadic and Semi-Nomadic Tribes. They are the poorest of the poor. Our Government is concerned for the poorest of the poor. That is why, we are giving more importance to them.

We have launched *Padhe Bharat Badhe Bharat*. As I told you, after this many years of Independence, even today 38 per cent of our children do not know how to write and how to read. It is a national shame. That is why the '*Padhe Bharat, Badhe Bharat'* scheme has been launched." पढ़े भारत" बच्चों को स्कूल भेजना और उसके द्वारा आगे बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना, यह भी हमारा स्कीम है। *Sukanya Samridhi* Account has been notified for enabling education of the girl child. Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teacher's Training to empower and increase the capacity of our teachers has been launched. To reduce the preventable deaths, India New Born Action Plan has been initiated and four new vaccines have been approved. This is one area where the infant mortality is going up. Keeping that in mind, this particular scheme has been initiated. National Ayush Mission has been initiated to promote fast effective Ayush services. We have the State of Kerala as a shining example in Ayush. We have to popularise it. We have to popularise our Indian medicines and Indian Ayurveda and we have to use the local talent also. The Government is committed to do that. The Government is taking all possible steps to stop the generation of black money both domestically as also internationally. I will be coming to that also. There is a story which has appeared in *The Indian Express* and other newspapers today. I will tell that story to my friends here. In the story it has been mentioned that earlier the Income Tax people wanted to enquire into the accounts of the HSBC. The then regime did not give permission. That is the report. They are asking us now. हमने आने के बाद अनुमति दी है और जो होना है, वह होगा। आप चिंता मत कीजिए, होगा। ...(व्यवधान) Now, new standards have been set to improve the quality of roads बैठ कर बोलना अच्छा नहीं है। ...(व्यवधान) यह शोभा नहीं देता है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : आपने भी अकाउंट्स का खुलासा नहीं किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऐसा करने के लिए कहा। ...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : देखिए, अभी तक जो हुआ, जो गलतियां हुई हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। यहां नहीं कर पाए तो वहां दूर जा कर करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। ...(व्यवधान) The other point is on the minimum pension scheme. आत्मचिंतन करने में कोई दोष नहीं है। हरेक को करना पड़ेगा। हमको भी करना पड़ेगा। सात स्टेट्स जीतने के बाद दिल्ली में ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हमको भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आपकी हालत ऐसी क्यों हुई, आपको भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। लगातार स्टेट के बाद स्टेट क्यों जा रहे हैं, उसके बारे में भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। इतने साल के बाद वह मिनिमम रिक्वायरमेंट देश के लिए नहीं मिला। वह क्यों नहीं मिला इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए भी आत्मचिंतन करना पड़ेगा। इसलिए आत्मचिंतन किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का नहीं है, पूरे देश के लिए आत्मचिंतन होना चाहिए मगर जितना आटा, उतना रोटी, जिसका जितना कोटा, उनका उतना आत्मचिंतन का जरूरत होगी। Minimum pension has been enhanced to Rs. 1000. I was in a programme in Hyderabad. One lady came to me and while giving pension to her I asked her as to how much she got and she replied that she was getting Rs. 30 as pension per month. After 68 years of Independence she was getting a pension of Rs. 30 per month. That is why the hon. Prime Minister said that the poor should be supported and be given a minimum pension of Rs. 1000. Now, around 50 lakh people are going to be benefited out of this. I did it in Hyderabad. … (*Interruptions*) They are not criticizing … (*Interruptions*) सुनिए, वह कौन सी पार्टी है, वह भी आपको मालूम नहीं है। ...(व्यवधान) वह टीआरएस है। ...(व्यवधान) उन्होंने आपसे वीआरएस लिया है। ...(व्यवधान) वे अच्छी खबर बता रहे हैं। चंद्रशेखर राव जी ने केंद्र सरकार द्वारा अनाउंस करने से पहले ही 1000 रूपये पेंशन दे रहे हैं और उसमें भी वृद्धि किया है। आप क्यों हँस रहे हैं, यह हमें समझ नहीं आ रहा है। ...(व्यवधान) The statutory ceiling under EPF has been enhanced to Rs. 15,000 benefiting lakhs of people across the country. The Government has taken significant steps with regard to the river Ganga, the life line of India by launching the *Namami Gangey* project which is an integrated Ganga conservation mission set up with a Budget target of more

than Rs. 2000 crore. गंगा प्रक्षालन करने के लिए हमने शुरूआत की है। इसमें आपका भी सहयोग चाहिए।

As regards oil prices, retail selling price of petrol, which was Rs. 73.60 in July, 2014, has been reduced by Rs.16.29 per litre since then. Similarly, diesel prices, in August, 2014, was Rs. 58.97 per litre and it was reduced by Rs.12.35 per litre and the current retail selling price is Rs.46.62.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Your leader has already spoken yesterday.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the historic decision of reduction of petrol prices and diesel prices was done by our Government headed by Shri Narendra Modi, our honourable Prime Minister of India. … (*Interruptions*) Sir, these people who have been in power were only increasing the prices. They never thought of reducing the burden of the common people. हमारी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है।...(व्यवधान) इसे वे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं।...(व्यवधान) वे उसे पचा नहीं पा रहे हैं, मैं क्या करूँ?...(व्यवधान)

With regard to Ordinances, they are saying that Ordinances are against the Constitution. They are saying that Ordinances are undemocratic.… (*Interruptions*) करूणाकरण जी, आप बैठिए।...(व्यवधान) Sir, I am happy that my Congress friends are accepting that Ordinance is a democratic provision. I am thankful to them. … (*Interruptions*) Shri Jyotiraditya Scindia, this is not the way to speak. If you want to come up in life, please have some patience.

A total of 637 Ordinances were promulgated during the last 62 years. This works out to be 11 Ordinances per year which means almost one Ordinance per month as a long term trend. A total of 456 Ordinances were issued during the Congress rule during the last 50 years. Sir, three Ordinances were issued..… (*Interruptions*) Shri Karunakaran, your record is more worse than the Congress Party. I will come to that. लेफ्ट का रिकार्ड वर्स्ट है, इसलिए जनता की करूणा आपके ऊपर नहीं हुई।...(व्यवधान) मैं बताना चाहता हूँ, There is nothing personal here, Sir. I am talking of

the factual situation. If I am wrong factually, somebody can correct me and I am ready to be corrected. … (*Interruptions*) You can do it. I will give you an opportunity. After five years, you will get an opportunity, if you work hard. … (*Interruptions*) I am talking about myself. Sir, he asked me.… (*Interruptions*) यह बुलडोजिंग नहीं चलेगा।...(व्यवधान) लोकतंत्र में यह तरीका नहीं चलेगा।...(व्यवधान) वैंकैय्या नायडू के साथ किसी हालत में नहीं चलेगा।...(व्यवधान) आप कृपया बैठ जाइए। … (*Interruptions*) A total of three Ordinances were issued. If you have patience, please hear me. Sir, they cannot digest the facts. ये सत्य को पचा नहीं पा रहे हैं, क्या करें?...(व्यवधान)

पाँच साल के बाद चुनाव होगा।...(व्यवधान) पाँच साल में हम अच्छा काम करेंगे तो और 10 साल आगे जाएंगे, अगर और भी अच्छा काम करेंगे तो 15 साल भी हम राज कर सकते हैं।...(व्यवधान) आप ठीक तरह से व्यवहार करेंगे तो आपको मौका मिलेगा, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Minister is saying.

… (*Interruptions*)*

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, on 26th January, 1950, the very day the Constitution came into being…… (*Interruptions*) Please do not talk about Parivar. Then you will have to face problems. ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं?...(व्यवधान) What is your problem now? I am not able to understand your problem. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, please sit down. Please go to your seats.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: After having been in power for more than fifty years, they must have more patience. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Let there be order. Then only can I say something.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If they do not have patience, then what shall we do? … (*Interruptions*)

---

* Not recorded.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Any one of you speak please. If all of you shout together, how can I listen?

… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mallikarjun Kharge is on his legs.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): With your permission, I would like to say that the Minister has got every right to interrupt, interfere and explain his position. But he has no right to insult others. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mallikarjun Kharge is speaking. Why are you shouting? Let him make his point and then the Minister will reply. Why all of you are shouting? When your own leader is speaking, why are you shouting? I cannot run the House if you behave like this.

… (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : He has every right to explain his position, defend his Prime Minister, defend his action. But he has no right to insult other Members. He should also listen to what other person says because when you are making allegations, when you are insulting, we are not going to tolerate that here. We are here to reply. You give us a chance to reply to you. But you are not yielding. In a parliamentary democracy, the Minister of Parliamentary Affairs should have more patience than other Members. Instead he is instigating. … (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, truth is unpalatable. … (*Interruptions*) Kharge ji spoke for 60 minutes. We did not do anything. There is no question of any personal insult to anybody. They are insulting me. They are insulting the Minister. Please go through the records. … (*Interruptions*) Three Ordinances were issued on 26th January, 1950, the very day the Constitution came into being. They were, the Parliament (Prevention of Disqualification) Ordinance, 1950; the High Courts (Seals) Ordinance, 1950; and the Judicial Commissioner's Courts (Declaration as High Courts) Ordinance, 1950. … (*Interruptions*) They were all

issued on the very first day of the Republic. … (*Interruptions*) Over 100 Ordinances were promulgated between August 15, 1947 and 26th January, 1950. … (*Interruptions*) Around 77 Ordinances issued during 1971 to 1977 at the rate of three Ordinances every two months. … (*Interruptions*) That being the record, they cannot criticize others. … (*Interruptions*) During Rajiv Gandhi's period, 35 Ordinances were issued. … (*Interruptions*) The CPI (M) backed United Front Government passed 61 Bills during 1996 – 1998, but issued a record 77 Ordinances at a strike rate of more than three Ordinances per month. That is the record of the United Front Government. … (*Interruptions*) That being the case, we must be ready to hear the other side also. We must have some patience to hear the other side also. … (*Interruptions*)

Having made allegations, when you get an opportunity you can definitely talk about it. … (*Interruptions*) They are trying to find some alibi to escape from criticisms. But that is not acceptable. … (*Interruptions*) I have not taken anybody's name. I have not made any personal insinuations. I will never do it in my life. I have not done it. The entire Parliament has been watching and seeing.

So, this CPI (M) backed United Front Government passed only 61 Bills during the period 1996 to 1998, but issued a record of 77 Ordinances at a strike rate of more than three Ordinances per month. Thus the Opposition has no moral right to criticize us. … (*Interruptions*) They are insulting democracy.

HON. DEPUTY-SPEAKER: They want to walk out.

… (*Interruptions*)

14.55 hrs

At this stage, Shri Mallikarjun Kharge and some other hon. Members left the House.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the Minister's remarks.

… (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Sir, the Congress regime was responsible for hundreds of Ordinances.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please take your seat.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION (SHRI BABUL SUPRIYO): Sir, Shri Kalyan Banerjee is abusing her. He is using bad language against a lady Member.… (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except the hon. Minister's speech. Please take your seat. He is on his legs.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Who is using bad language against some hon. Members, the entire House has watched now. It has also gone on record. Who is doing it? There is no question.… (*Interruptions*) महोदय, देश में स्थिर सरकार चुनाव के माध्यम से बनी है। बार-बार वैल में आकर बोलने का क्या तरीका है?

HON. DEPUTY-SPEAKER: He has gone.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: It should not go on record.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record. Only the hon. Minister's speech will go on record.

(Interruptions) ...[*]

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Let the entire country scrutinize if there is one word which is objectionable, one behaviour which is objectionable. What is the behaviour? When the Minister is on his legs, then he is talking, he is intervening in the Discussion on the President's Address. They try to insult me. They try to accuse me. Then, they make comments as they like. I have not taken anybody's name. My point is very simple. People who are criticizing the Ordinance route have resorted to Ordinance umpteen number of times. This is what I am saying.

---

[*]Not recorded

With regard to the Left also, I said the CPM Backed United Front Government passed only 61 Bills. Facts must come on record. It must go to the people. As I said, the CPM backed United Front Government passed only 61 Bills during 1996 to 1998 but issued a record number of 77 Ordinances at a strike rate of more than three Ordinances per month! That is the record of the Left Parties. Now, they are criticizing us.… (*Interruptions*)

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Should you now use it wrongly?

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We should not use it like that. You do not worry. We will not repeat that at all. You do not worry about it. That is why I said I am there for five years… (*Interruptions*) That is why we said that we are here for five years.

I now come to the Land Acquisition Ordinance. Ordinance is a constitutional provision available in case there an emergency situation. We thought helping the people is the need of the hour. That is why, we have gone on promulgating the Ordinance. Please see the Coal Ordinance. Why this Coal Ordinance was promulgated? What happened? It is because of the Coal Ordinance that the country has benefited to the tune of Rs.80,000 to Rs. 1 lakh crore after the auction of 18 mines. It has come not only to the country but to the States like Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and West Bengal. They are all immensely benefited by the most transparent auction bid by this Ordinance. That being the case, this Ordinance is also very much justified. It is helpful to the States. It will really enhance and strengthen the federal structure of the country.

With regard to the fair and transparent e-auction of coal, I would say that only 18 of the 204 coal blocks have been auctioned resulting in a potential revenue of more than Rs. 1.2 lakh crore. This will bring down the fuel cost resulting in reduction in the cost of power considerably.

This is democracy. This is a Parliamentary debate and discussion. I try to raise a point. You try to raise a point. Let the people hear us and then they decide about it.

Sir, they say: "We will speak. You cannot speak. You cannot intervene. You cannot pinpoint. You cannot highlight things." What is this? How can it happen? This is really an insult to democracy. It is not an insult to one Minister but it is an insult to democracy.

Over the next 30 years, six coal-rich States like Odisha, Madhya Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Jharkhand and Chhattisgarh will get, through e-auction and royalty, a sum of Rs.1,08,000 crore approximately. These States are also likely to get power tariff concession of Rs.30,000-plus corre. This is the estimate. When the C&AG has made this estimate, people said that this is a notional loss. One Finance Minister at that time said: "Coal is there in the womb of the mother earth. Not even something has been taken out. How do you calculate this?" They tried to criticize the C&AG. Now, the C&AG's stand has been vindicated. The BJP's stand has been vindicated. The then combined Opposition's stand has been vindicated that there is a huge revenue loss which has happened to the country, particularly to the poor people. Because of the coal auction, the States which are economically not strong will be benefited. If they are benefited, people in those States will be benefited.

15.00 hrs.

ओडीशा वासी, झारखण्ड वासी, वेस्ट बंगाल वासी, मध्य प्रदेश वासी, महाराष्ट्र वासी जो गरीब लोग हैं, उन्हें फायदा मिलेगा। उन्हें सस्ते में बिजली मिलेगी और सस्ते में कोयला मिलेगा। इस कारण उन प्रदेशों का उत्थान होगा। साथ ही साथ, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि एक तरफ कोल का आबंटन और दूसरी तरफ बिजली, ये दोनों विषय एक-दूसरे से जुड़े हैं। उधर के लोग इसे सुनना नहीं चाहते हैं। यही प्रॉब्लम है। उन्हें मालूम है कि यह सब होने वाला है, इसलिए वे सुनना नहीं चाहते हैं। यह ठीक है। मैं क्या करूं? लोकतंत्र में उन्हें वॉक आउट करने का, टॉक आउट करने का अधिकार है। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर

सकते।...(व्यवधान) वॉक आउट करना उनका अधिकार है। लोकतंत्र में उन्हें यह अधिकार है। वे टॉक आउट करें, वॉक आउट करें, *बट नो ब्रेक-आउट*।

सर, मेरा लैंड ऑर्डिनैंस के बारे में यह कहना है कि on Land Acquisition Act, I do agree it is an emotive Act; it is an emotive issue. हमारी सरकार ने किसानों के हित में यह कानून लाया है। इसमें कुछ कमियां हैं। अगर कोई इसमें कुछ कमी को महसूस कर रहे हैं तो आप उस कमी को हाईलाइट करें, हमें बताएं। हम आपस में बात करने के लिए तैयार हैं। हम पार्टियों से बात करेंगे, व्यक्तियों से भी बात करेंगे, संगठनों से भी बात करेंगे। इस तरह बातचीत चल रही है, आगे भी चलेगी। हम सब से बातचीत करेंगे। अगर इस पर कुछ अच्छे सुझाव आएंगे, अगर सदन में भी कुछ अच्छे सुझाव आएंगे तो हम उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह मैं हाउस को बताना चाहता हूं।

The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act was passed in 2013. We did support it. हमने उसका समर्थन किया। यह सही है कि हमने समर्थन किया। मगर, समर्थन करने के बाद हमारे ग्रामीण विकास मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने एक बैठक बुलायी। उस बैठक में सभी स्टेट्स के मंत्री वगैरह आए थे। आपस में चर्चा करने के बाद बहुत लोगों ने कहा कि इस कानून के कारण पूरा विकास ठप हो गया है और इसमें किसानों को भी नुकसान हो रहा है, स्टेट्स को भी नुकसान हो रहा है। इसलिए इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसा कई लोगों ने सुझाव दिए। कुछ मुख्यमंत्रियों ने पत्र भी लिखे हैं। कुछ स्टेट्स ने अपना एक सेपरेट कानून भी बनाया। उसे ध्यान में रखते हुए देश के कई अखबारों में इस विषय पर संपादकीय भी आए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा और अनुभव भी किया होगा। उस आधार पर सरकार ने, इस देश को आगे बढ़ाना है, इस दिशा में सोच कर इसे किया।

अभी हमारे शिव सेना के एक मित्र ने कुछ कहा और किसी माननीय सदस्य ने कुछ कहा। कहने में कोई आपत्ति नहीं है। उन्हें अधिकार है। पर, उन्होंने जो कहा, उसमें तथ्य कहां तक है, उस तथ्य को देखेंगे। अगर इसमें कुछ तथ्य है, कोई अच्छा सुझाव है, तो उसे स्वीकार करने में हमारी सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अगर कांग्रेस के द्वारा भी कुछ अच्छे सुझाव आते हैं तो उन्हें स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमें रेलवे लाइन, इलेक्ट्रिकल लाइन, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, ग्रामीण इलाके में अन्य प्रोजेक्ट्स का निर्माण करना है तो हमें इसके लिए ज़मीन तो चाहिए। बचपन से हम लोग देख रहे हैं। इसमें इतने साल की देरी हो गयी। गांव-गांव में लोग डांवर रोड का निर्माण चाहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए जब श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी ने

इनिशिएटिव लिया तो उस समय भी लैंड एक्वीजीशन किया। कांग्रेस के ज़माने में भी लैंड एक्वीजीशन होता रहा है। उनके पचास सालों के राज में उन्होंने लैंड एक्वीजीशन एक्ट के सेक्शन-4, सेक्शन-6 के अंतर्गत नोटिस देकर उन्होंने लैंड एक्वायर किया। उन्होंने कभी इतना कम्पेनसेशन भी नहीं दिया। हम तो केवल नौ महीने से राज कर रहे हैं। हमारे राज्य में अभी तक ज्यादा लैंड एक्वीजीशन नहीं हुए हैं। इसलिए किसानों के साथ कुछ अन्याय करने का सवाल ही नहीं है। Ours is the last party to do any injustice to the farmers. We are ready to go even an extra mile to help and strengthen the hands of the farmers. That is the commitment of our Government. On 27th June, 2014, the Government of India had called a meeting of all Revenue Ministers, and the Ministers concerned were present. Suggestions were given by Uttar Pradesh; and Haryana, which was ruled by the Congress at that time. Madhya Pradesh; and Gujarat have given certain suggestions on PPP projects. They were all there on record. The then Maharashtra Chief Minister written a letter to Shri Jairam Ramesh, for removal of consent clause. Then, the Maharashtra Government went a step forward and reduced the compensation amount from four times to 2.2 times of the market value payable for land, etc. I have the Gazette with me. It was the Congress Government at that time. I do not want to take the name of the Chief Minister, who is not present in the House. But he was the outgoing Congress Chief Minister who had ordered this and there is a Gazette notification.

Here is a letter written on 3rd August, 2011 by the then Chief Minister of Maharashtra – "Dear Shri Jairam Ramesh, I would like to place on record… On closer examination, we found that the provisions of the new Act will increase land and rehabilitation cost up by six times for public amenities like water supply, health facilities, sewerage, infrastructure, roads, irrigation and power projects."

"As the Act is applicable retrospectively, within one year of its enactment, even the on-going public projects where partial land acquisition has already been done will be adversely affected and the cost will go beyond the budget amount. Some examples are enclosed. Major on-going irrigation, drinking water and power projects will be non-viable as cost of land will exceed the rate of economic return.

By making acquisition process highly centralised, litigations and increased cost may result in effective freezing of the current land use and to change current use from…"

So, he said, please focus on removal of 80 per cent consent when Government acquires land for industries and urbanisation purposes. He has signed it and sent it to the Minister at that time and now they are accusing us. हमने कोई काम नहीं किया। फोर टाइम्स का जो कंपंसैशन है ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : इसीलिए तो उनको हटाकर आपको लाए हैं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : हमें लाए हैं, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। आगे भी काम करेंगे, आपको भी साथ लेकर काम करेंगे, आप चिंता मत करिए। हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि try to understand that acquisition of land is for public purpose. Acquisition of land is not for private residence of any individual. Acquisition of land is not for a private hotel. This is going to be for public purpose. When I say public purpose, it means जनता, आम जनता, किसान के लिए, आम नागरिक के लिए उसकी जमीन का उपयोग करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ।

महोदय, मुझे इसे कहने में कोई संकोच नहीं है। अगर इसका किसी ने गम्भीरता से अध्ययन किया, यह उसकी समझ में आया कि अमुक प्रावधान के कारण यह नुकसान किसानों को होने वाला है, कुछ लोगों ने कल मेरी पार्टी वालों ने मुझे कहा कि 15 साल के पहले, 20 साल के पहले जो जमीन अधिग्रहण किया, the land which was acquired 15 years or 20 years back, it is lying vacant. They have not used it for that purpose. How do you allow it? Now that the rate has gone up, they want to use it for other purposes. This is a point to be considered. People said that if no activity starts within five years, then why do you not rethink about that also? Some suggestions have come. All these suggestions, either from this side or that side, whatever valuable suggestions hon. Members give, those suggestions will be considered. But the core of the matter is, this Act is in the interest of the people, in the interest of the country and in the interest of the development of the country.

Sir, there was almost a developmental holiday all these years. We cannot afford to have such holidays. We have to work extra and some people are finding fault with this Government, आपने बायोमैट्रिक्स सिस्टम लगाया, इसलिए आप चुनाव में हार गए। काम करना, समय पर आना और समय पर आने के लिए कहना, क्या यह कोई गलती है? क्या हमने कोई पाप किया? नहीं, किसी को पूछना नहीं, मैं उन लोगों के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं। यह गलत है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। कुछ लोग लिख रहे हैं कि यह एक कारण है। कारण जो भी हो, कारणों की समीक्षा पार्टी लेवल पर होगी। नेतृत्व सही समीक्षा करेगा, जरूर करेगा कि 7 स्टेट्स लगातार जीतने के बाद 8वां स्टेट क्यों हार गए? यहाँ सभी पार्टीज एक साथ हो गईं, तो उस सिचुएशन का मुकाबला करना भी सीखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए और हम सीखेंगे, विनम्रता से सीखेंगे। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो पार्टीज हमारी आलोचना कर रही हैं, उनकी हालत क्या है, यह चीज उनको सोचनी चाहिए। जब मैं कहता हूं तो वे कहते हैं कि आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। अपमान करने का सवाल ही नहीं है। किसी का अपमान क्यों करना है? हम सब लोगों को जिताकर लोगों ने यहां सदन चलाने के लिए, एक दूसरे के प्रति मर्यादा रखने के लिए, चर्चा करने के लिए और जनता के हित में काम करने के लिए भेजा है। These engines of growth have to be kick started. This legislation will kick start the engine of growth. This is our belief. The Coal Ordinance will kick start growth. The E-Rickshaw Ordinance is for the rickshaw of the common people. People try to find objection about that also.

Sir, you know the background. यह अध्यादेश क्यों जारी करना पड़ा, आपने इसे देखा है कि इस सदन में क्या हुआ और बाहर क्या हुआ। ठीक तरह से यह नहीं चल पाया, इसलिए कानून लाना पड़ा। कोई फैशन नहीं है, कोई फैंसी नहीं है, हम कोई आर्डिनेंस नहीं लाना चाहते हैं। सदन ठीक तरह से चले, सदन में ठीक से चर्चा हो। मैं बिल प्रपोज करूंगा, आप अपोज करिए। Let the House dispose it. I propose it, you oppose it, let the House dispose it. I have no problem either way. It is the democratic will of the people. यह बार-बार कहना कि आपको अधिकार आ गया तो अहंकार आ गया, कहां अहंकार आया है? यह क्या है? हमें आए हुए आठ-नौ महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। हमको इतनी गालियां दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहे हैं। आज मुलायम सिंह जी, आप हाउस में हैं। धर्मेन्द्र जी बताइए। उत्तरप्रदेश में कल आपके एक मंत्री ने जिसतरह का बयान दिया है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं मुलायम जी का बहुत आदर करता हूं। मुलायम जी भी उसको स्वीकार नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा है कि सब लोग मोदी जी के *हैं।...(व्यवधान) यह क्या तरीका है? यह पार्टी का नहीं है, मुझे मालूम नहीं, मुलायम जी उसको स्वीकार करेंगे या नहीं? मगर क्या उसको लेकर पार्लियामेंट में चर्चा होगी? उसको लेकर पार्लियामेंट को क्या रोकना है? "UP Minister calls BJP leaders, Modi's*...(व्यवधान)

मेरा यह कहना है कि कुछ लोग बाहर ऐसा बोलते रहेंगे, उनको लेकर अगर हम यहां सदन को नहीं चलने दें, यह अच्छा नहीं है। मैं उनका नाम भी नहीं बता रहा हूं। मैं आपके पास वह भेजूंगा। आप अनुभवी हैं, शीर्ष हैं, हम सब लोग आपका बहुत आदर करते हैं। आपको क्या करना है, आप तय करें। अभी किसी मंत्री ने कुछ कहा, हम जरूर उसका समाधान करेंगे। कुछ लोगों ने कहा, खड़गे जी अभी हाउस में नहीं हैं, खड़गे जी ने कहा, पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने क्रिश्चियन समुदाय के फादर्स मीटिंग में जाकर जो स्टेटमेन्ट दिया, वह स्टेटमेन्ट पहले देते तो अच्छा होता।

सर, प्रधानमंत्री जी को जो भी कदम उठाने चाहिए, वह कदम उठाते रहे हैं। There is one Father Alexis Prem Kumar who was captured by terrorists and was taken as a hostage to Afghanistan. You know, people who are taken as hostage are not ordinarily released. But the Prime Minister took personal interest. Then the Government of India has worked hard and worked in full cooperation with Afghanistan and Alexis Prem Kumar has come back safely without any problem. He belongs to that part of the country. So we must feel happy that the Government is taking such initiatives. You cannot doubt the intentions of the Government; you cannot doubt the credibility of the Prime Minister. You cannot make allegations like this about the Prime Minister and then make casual comments.

Sir, last time, when one of the Ministers made some remarks, the Prime Minister came to this House, came to that House and disapproved those comments of my own Minister.

उन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर, प्रान्त के आधार पर, जाति के आधार पर और मजहब के आधार पर लोगों में भेदभाव करना, अच्छा नहीं है। किसी ने ऐसा कुछ किया तो उन्होंने कहा, यह उनके मानसिक स्थिति के बारे में है। उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। यह उनकी मानसिक बीमारी है।

---

* Not recorded.

हम सब एक हैं। 'सबके साथ सबका विकास' यह भारत की पद्धति है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने खुद हाउस में कहा है। अगर रिकॉर्ड चाहिए तो मैं अभी वह रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार हूं। वह डाक्यूमेन्ट मेरे पास है। वह पार्लियामेन्ट के रिकॉर्ड में है।

उन्होंने कहा है कि आज जातिवाद के जहर ने देश को डूबा दिया है। हम श्रेष्ठ भारत का सपना लाये हैं। अगर किसी को एक भारत में से दो भारत दिखता है तो यह उसकी मानसिक बीमारी का परिणाम है। इतना स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा है। किसी ने कोई स्टेटमेन्ट दिया, अलग-अगल संगठन हैं, लोकतंत्र है, लोग स्टेटमेन्ट देंगे, अगर आपको स्टेटमेन्ट से आपत्ति है तो आप उसको बाहर कन्डेम करें। मगर, सदन में आकर हमको घेरना, हमारी सरकार की आलोचना करना और बार-बार इश्यू उठाना, यह सही नहीं है।

चर्चेज पर अटैक के सम्बन्ध में भी चर्चा हुयी। गृह मंत्री जी उसका समय पर उचित समाधान करेंगे। देंगे। जो जानकारी मुझे मिली है, ज्यादातर केसेज में चोरी का मामला है। पुलिस उसकी इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी पूरी होने के बाद, गृह मंत्री जी संसद से भी वह इन्फॉरमैशन डेफिनेटली शेयर करेंगे, शेयर करना चाहिए, पूरे देश को आश्वस्त करना चाहिए, यह बहुत जरूरी है।

मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि यह देश एक समुदाय का नहीं है। यह देश सबका है। भारत में जो रह रहे हैं, उन सबका है। अटक से लेकर कटक तक, काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इस देश में रहने वाले सभी भारतीयों का भारत है। भारत हमारी मां है। भारत हमारा देश है। यह हमारा विश्वास है। यह हमारा कमिटमेन्ट है। जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया है। जनता ने नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा किया है, इसलिए उन्होंने हमको बहुत भारी संख्या से जीता कर यहां भेजा है। बी.जे.पी. का अपने-आप बहुमत आना कोई मामूली विषय नहीं है। यह लीडर के कारण हुआ है। ...(व्यवधान) नाम जयप्रकाश जी, काम...(व्यवधान) Politics should not be politics *versus* development. It should not be the case. It should be the politics of development.

The only language that all of us should be speaking is the language of development, development and development. All that I want to emphasis is that let us move forward collectively with the new collective conscience that seeks to enable our people to meet their aspirations.

Hon. Deputy-Speaker, Sir, you are in the Chair and you have been observing all that. I have some experience if not that much experience of those great leaders who are standing continuously and heckling me but I never had the

habit of that. I have talked politely to everybody but firmly put my view. That is my strength and that is my weakness also. I feel that my Government have not done anything wrong. I feel my leader is great. Not only me but the entire country today feels that Shri Narendra Modi is a great leader. The entire world is looking towards Shri Narendra Modi. The entire world is looking towards India. India is now resurgent. India is rising. Let us not discredit the name of India. Some comment was made. Comments can be made but what happened subsequently in America that everybody knows. I do not want to take names of the people and what happened there with minorities, blacks and all. These things are happening in different parts of the globe, in different parts of our country and in different regimes of the Governments. We should work together. We should curb this mentality of attack on a Church, Mandir, Masjid or a Gurudwara. This should be condemned with all seriousness. The State Governments must take strongest possible action against those culprit people. That should be the line. That should be the approach. We may have some ideological differences with Samajwadi Party, BSP, TMC, TRS or even with TDP. Although we are partners, we have our own ideology and they have their own ideology. In the larger interest of the people, we came together to work for the welfare of the people. We are trying to do our best. We will try to improve also. This occasion of the Presidential Address is an occasion where all of us have to put our heads together, discuss the issues and then allow the changes.

Lastly, a comment was made that Government has supported the Land Acquisition Bill. We have supported it with good intentions. Afterwards, Chief Ministers made representations. Editorials were written and practical difficulties have come to our notice. In our collective wisdom, we brought this Bill. Sir, 120 times the Indian Constitution has been amended. जरूरत पड़े तो परिवर्तन करना है। इसलिए हमने जनता, किसानों, देशवासियों और विकास के हित में डैवलपमैंट किया।

Sir, the last allegation against the Government and also sometimes against the Prime Minister is that Government is supporting the industry and the business

people. Are the industrialists anti-nationals? Is the business against India? Without the business and without the industry, how can a country prosper? Agriculture and industry are like eyes of a man. We have to take care of both of them. They are also contributing their might to the wealth of the country. If something goes wrong, action should be taken irrespective of छोटा उद्योगपति कौन है, इसके बारे में अलग-अलग डिसक्रिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है। Without producing wealth, how do you distribute wealth? This is the point that I want everybody to ponder. In my 40 years of public life what I have learnt is to produce wealth, create wealth, create development, and then distribute development. Without creating wealth if you distribute the wealth, it will not work. Telugu people say '*Panchaali, panchaali*', which means 'Distribute, distribute'. I say, *'Penchaali, penchaali',* which means 'Increase, increase' production. If you do *'Panchaali'* without *'Penchaali'*, you will be left with '*Puncha*' which means loincloth. That is a reality. You also understand that. India is already having a great stress of debt. We have also inherited certain problems. We should jointly address those problems and take the country forward. That is the message that the hon. President, who is one of the most learned persons of the country, a great visionary, has given to this Parliament. Let us all join hands together in conveying our thanks to the hon. President and follow his advice of conducting the Parliament in a better manner. We should avoid Ordinances to the extent possible. If Parliament functions effectively, I do not think there will be any necessity for any Ordinance. We do not have any fancy for Ordinances. बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के द्वारा निर्णय होना चाहिए। प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा कि अमृत मंथन होने दीजिए, मंथन से अमृत निकलेगा। सुविचार, मंथन हमेशा बहुत जरूरी है। मंथन करें, चिंतन करें और सब करके हमें जनता के हित में काम करने का प्रयास करना चाहिए।

Sir, this is my humble suggestion. I am sorry. I do not feel that I have used any word but I told one thing. When they were saying: "You give us an opportunity", I said: "Opportunity will come after five years". That is because I

am sure that there would not be any mid-term elections in the country. Nobody should have that apprehension.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Opportunity will be given by the people. … (*Interruptions*)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : कुछ भी होने वाला नहीं है, यह सरकार पांच साल रहेगी, उसके बाद दुबारा भी यह सरकार आएगी, यह मेरा विश्वास है। आपका विश्वास अलग है। हाऊस के अंदर मौका सभापति देते हैं या उप सभापति देते हैं। फिर भी मैंने दो बार मौका दिया, जब खड़गे जी खड़े हो गए, मैं विनम्रता से उनका सम्मान करते हुए बैठ गया। We must respect each other. They should not say: "When we stand up, you should sit down. When you stand up, we will not sit down." यह अच्छा नहीं है, यह भारतीय परंपरा भी नहीं है। मुलायम सिंह जी इतनी देर तक बैठे रहे, मैंने जो भी कहा उन्होंने ध्यान से सुना। अन्य पार्टियों में मतभेद होने के बावजूद हम सब लोगों को मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करना है। अंत में, आप सभी का धन्यवाद। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, जय हिन्द।

[*] **SHRI ABHIJIT MUKHERJEE(JANGIPUR) :** There is nothing much in the address. Several announcement made are about the schemes commenced by the UPA Government. It is a repackaging of UPA Schemes.

Though crores of bank accounts have been opened under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, it is a well known fact that most of these accounts have not had even a single transaction. Thus indicating that 'so called benefits' which the NDA Government desired to take to poor people through these bank accounts are yet to reach the poor and needy. There has been no progress.

The Direct Benefit Transfer Programme is the UPA programme which was already under implementation. There is no contribution of any type of the NDA in this programme.

The Swachh Bharat Mission, since the time it has been launched on 2nd October 2014, has been only a 'photo opportunity' session for the leaders of NDA. This Mission of Swachh Bharat is very far from becoming a people's movement. The way the programme is conducted has not produced any worthwhile result, consequently the dirty environs, unhygienic conditions etc. prevail not only in hinterland i.e. rural areas of the country but right under nose of the NDA Government in Lutyen's Delhi itself. I would like to mention here that much better result was achieved under Nirmal Bharat Abhiyan under UPA. It has been committed in the address that all schools in the country will have a toilet. Here the Government has not spelt out anything about maintenance and operation of the toilets, water supply, sewerage, etc. Therefore, whole lot of issues on which there are no views expressed.

On one hand MGNREGS has been mentioned as a 'powerful weapon to combat rural poverty', in the address by the President, while on the other hand, the NDA Government has reduced funding of the programme and also reduced its access by reducing number of districts to 200. How then can this scheme be powerful weapon.

---

[*] Speech was laid on the Table.

'Sansad Adarsh Gram Yojana' is another example of copying or duplicating UPA had started 'Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana' with focus on villages having predominance of SC/ST. NDA Government should have focused on Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana rather than camouflaging it with a new name and launching its own scheme.

True to its character, NDA Government has only announced housing for all by 2022 without any clear and concrete roadmap of how will this scheme be taken up and from where the funds will be arranged etc.

In the address, it has been stated that this Government cares to safeguard interests of farmers affected by land acquisition. On the other hand this NDA Government has smuggled in amendment in the Land Acquisition Bill to do away 'consent' clause while bringing in amendment of Section 105 regarding 'compensation' which was to be brought in by 31.12.2015. We will resist it tooth and nail.

More appropriate maxim for this Government will be 'Minimum Governance Maximum Government'. There is more centralized decision making observed with very less decentralization. Bureaucrats are very often directly called by PMO for briefing etc. bypassing the Cabinet Ministers. We have deviated from Cabinet system of governance which was conceived by the framers of our Constitution.

The Digital India Initiative too is to go a long way before something concrete is achieved. There is lack of appropriate bandwidth which is the digital operation enabling infrastructure. I wonder how the promise of Digital India Initiative will be fulfilled.

There is no ideology in this Budget. It gives one a picture of patchwork attempt with no cohesive development strategy and lacking focus.

The rate of growth is 7.4% but in the address why there is no commensurate Tax Collection. Why it is stated again and again that tax collection may be less. Figure of 7.4% has been arrived at by changing the base year of

2004-05. Credit off-take has not increased. Therefore, it is difficult to take the figure of growth of 7.4% at face value.

The President's address is not only about announcing schemes and budgetary proposals but it is a statement of intent. Intent means how the Government will focus its policies for administrative action. Worth mentioning here is that the address does not focus or touch upon even the issue of respecting religious freedom and controlling the crony fringe elements.

The Government has announced the 'Make in India' programme with great fanfare, and in the address the old announcement have been repeated. However, no concrete results have been evident on the ground. In Defence Sector, only a few projects announcements have taken place but it is a long way to see real activity commencing on ground.

It is stated that the fuel prices have been reduced by Rs.17. It is a universal truth that there has been steep fall in international crude oil prices due to which fuel prices have come down and it is not the Government's efforts. It is almost halved but the entire benefits of reduction of crude oil prices have not been passed on to consumer. Government is using the opportunity to shore up its tax revenues. I urge the Government to pass on entire benefit to the consumer.

There is nothing stated in the address on issue of improving relations with our immediate neighbours especially Pakistan. What is the Pakistan Policy of the Government . It must outline the same or it will be a knee-jerk reactionary policy of tit for tat as is being done presently without any direction.

Though this Government is only announcing big projects here and there but is not making any effort to expedite completion of several very important infrastructure projects. NHAI had taken up 4-laning of NH-34 running through my constituency the progress of which is very slow. The address does not make any mention of resolving the issues hampering the on-going projects wherein lot of public money has already been spent.

Mega Food Parks were conceptualized and initiated by the UPA Government. However, NDA has announced it as part of its own programme. This Government has not announced any worthwhile incentive for Food Parks like encouraging Food Processing Industry to set up its unit or shift its unit to Food Park etc. Due to this the Food Parks may shortly become unviable.

Minorities are integral part of this country. However, there are several issues of the minorities which need urgent attention. There is absolutely no mention in this address how the concerns of minorities will be addressed with their education, religious freedom etc. will be preserved. This will alienate the minorities. This may create problem. I am compelled to mention this as my constituency is a minority dominated constituency with more than 65% Muslims.

Another area where the intent of the government is silent is about workers in the unorganized sector. They constitute large percentage of labour force. Bidi workers in my constituency fall in this category. Most of these workers do not get their rightful dues. No mention of this in the address will make them live in gloom and despair.

*डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : मैं बजट सत्र 2015 के दौरान भारत के महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में दिए गए अभिभाषण का स्वागत करता हूं एवं इसके पक्ष में अनुमोदन करता हूं। जिस प्रकार महामहिम जी ने अपने भाषण के दौरान एक महत्वाकांक्षी भारत के उदय होने की बात कही है उसमें महामहिम की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व मं सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अभिभाषण में ग्रामीण, किसान, व्यापारी, दलित, मजदूर, युवा, महिलाएं एवं सभी आम आदमियों के हितों का ध्यान रखा गया है। महामहिम के अभिभाषण के जरिए सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य आगे भी इसकी प्राथमिकता में बने रहेंगे। नवगठित कौशल विकास मंत्रालय की मदद से सरकार युवा शक्ति का लाभ उठाने का भरपूर प्रयास करेगी। देश के लोगों को रोग मुक्त बनाने के लिए सरकार का जोर उन सभी इलाकों में टीकाकरण की पहुंच बढ़ाने पर होगा, जहां अब तक इसकी पहुंच बहुत कम है। देश में शिक्षा की गुणवत्ता जैसे गंभीर विषय पर सरकार ने तय किया है कि इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार के सतत प्रयासों व नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था पुनः उच्च विकास के रास्ते पर है। हाल के अनुमानों के मुताबिक हमारी जी.डी.पी. 7.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रही है। जिसने भारत को विश्व में तीव्रतम गति से वृद्धि करने वाली एक बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। सरकार की ओर से कई निर्णायक कदम उठाने के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति में रिकॉर्ड कमी आयी है। पूंजी बाज़ार ऊंचाई के स्तर पर है और हमारे विदेशी मुद्रा भण्डार में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए कड़ी चुनौती बताया और कहा कि सरकार ने चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावित लोगों व प्रभावित राज्यों की सरकारों के समन्वित सहयोग के साथ पूर्णतया प्रतिबद्ध है। जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों का मुद्दा सरकार के एजेण्डे में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सरकार ने राज्य में विस्थापितों के लिए अनुकूल माहौल बनाने का प्रयास किया है। इसमें 60 हज़ार से ज्यादा कश्मीरी पंडित परिवारों के पुनर्वास को सुगम बनाना शामिल है और सरकार ने इस संबंध में कारगर कदम उठाए हैं। जिनमें अन्य कार्यों के साथ-साथ सरकारी नौकरियों, आर्थिक अवसर और सुरक्षा उपलब्ध कराना भी शामिल है। इसके साथ ही सरकार विधायी और प्रशासनिक ढांचों के जरिए काले धन पर नकेल कसने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। देश में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अपेक्षाकृत कठोर कदम उठाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि लोक

* Speech was laid on the Table.

हित में लिए गए सद्भावनापूर्ण निर्णयों को संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि प्रशासनिक तंत्र में विश्वास को बढ़ाया जा सके। "अधिकतम सुशासन-न्यूनतम सरकार" के अनुरूप सरकार आधिकारिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर ध्यान दे रही है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से निर्णय लेने के स्तरों को कम कर रही है।

राष्ट्रपति महोदय ने व्यय सुधारों पर सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला तथा आगे बढ़ते हुए कहा कि सरकार संसद में विधायी प्रक्रिया को सरलतापूर्वक आगे बढ़ाने और प्रगतिशील कानून बनाने की दिशा में पूरी निष्ठा से काम करेगी। सरकार के लिए भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों और उनके परिवारों के हितों की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। किसानों को मुआवजे के हक सहित उनके हितों के संरक्षण पर ध्यान देते हुए उचित मुआवजे का अधिकार और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में पारदर्शिता के इंतजाम किए गए हैं ताकि अवसंरचना से जुड़ी अहम परियोजनाओं और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में ग्रामीण आवास, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण जैसी सुविधाओं के लिए जमीन अधिग्रहण में आने वाली प्रक्रियाओं से जुड़ी समस्याओं को कम किया जा सके।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार के प्रेरणास्रोत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरूषों का प्रमुखता से अपने भाषण में उल्लेख करके उनके प्रति सरकार की कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसकी समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है तथा सरकार के नारे सबका साथ-सबका विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता की कोर वैल्यू में सभी के कल्याण पर ज़ोर दिया गया है। गरीबी हटाने के बारे में राष्ट्रपति जी का कहना है कि विकास को वास्तविक तभी माना जाएगा जब समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की कम से कम न्यूनतम जरूरतें तो पूरी हो रही हों। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों और समाज के वंचित तबकों के कल्याण के लिए काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति महोदय ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय के एकात्म मानवता दर्शन के तहत सभी लोगों के पावन विकास पर जोर दिया तथा सरकार की कई योजनाओं को दीन दयाल उपाध्याय के नाम से लाँच किए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि इनमें दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना और दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शामिल हैं। सरकार ने नानाजी देशमुख के नाम पर भी एक स्कीम चलाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत जनजातियों और घुमंतु लोगों के लिए हॉस्टल बनाए जायेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों से जुड़े पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन, पशुओं की नस्लों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के साथ ही तमाम विकासपरक सरकार के कार्यक्रमों का उल्लेख महामहिम ने अपने भाषण में किया है।

भारत को एक गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में गरीब का विकास, जनशक्ति का सदुपयोग, स्वच्छ भारत मिशन, गरीबों के लिए घर और किसानों की सेवा, बेटियों की प्रगति और महिलाओं की सुरक्षा को शामिल किया है। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से सरकार और माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की यह सोच स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती है कि राष्ट्र और समाज के विकास द्वारा "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" का सपना साकार होकर रहेगा। इसी के साथ मैं पुनः धन्यवाद प्रस्ताव पर अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

[*] **DR. RATNA DE (NAG) (HOOGHLY) :** As usual, President's Address is full of claims of its achievement in its 9 month old Government. But what is the truth? Truth lies elsewhere is a poor or common man happy with this Government? No. Why am I saying this? It is because of ever increasing prices of essential commodities. It is pro-corporate. We can see this in its activities and policy, which is business or corporate-friendly.

It is claiming that it has opened 13.2 crore bank accounts and credited Rs.11,000 crore in the accounts. There is apprehensive about these figures cutting across parties. It has claimed in the speech that it has brought about changes in different sectors. I would like to quote just one sector-farming sector. Farmers are committing suicides in Maharashtra and other states. Farming are not providing with any monetary relief. Land Acquisition Bill is hell bent on deceiving farmers. Anna Hazare is on fast and he is against this Bill and the policies of the Government. So also major political parties, NDA Government has changed colours when it is in Government. They were taking something else. The UPA II Government's Land Bill, which BJP supported was entirely different, and pro-farmer. The current Bill of NDA is pro-corporate. This is the difference.

The earlier UPA Government used the names of Gandhi and Nehru, the NDA Government is using the names of Shyama Prasad Mukherjee, Deendayal Upadhyaay, Nanaji Deshmukh and Vajpayee. In one sense, both UPA and NDA are same. They are not interested in actually ameliorating the sufferings of the poor but indulge in one-upmanship. This would not take the country ahead. The President's Address talk of country's GDP growing at 7.4%, inflation, food inflation are at a record low, etc. But what about the plight of poor, disadvantaged people? The Address also states that it will work for marginalized section of society. Would the hon. Prime Minister elaborate on this?

---

[*] Speech was laid on the Table.

Bitter truth and fact is that people are disillusioned by this Government in 9 months. In spite of petrol prices decreased by Rs.17 per liter, prices of essential commodities, vegetables, fruits have gone up. Would the Government explain this specific aspect? This Government aims for "Sabka Saath Sabka Vikas", which means "All together, development of all". Is this happening on the ground? What is happening is "business and corporate lobbies together with Government, development of corporates."

Swachh Bharat Mission was started with much fanfare. It is moving at a slow pace. Every wish this to be a grand success but the reality is that it has resulted in damp squib. The other aspect of the speech is that it wanted to create smart cities. But is the Government addressing the poor and downtrodden, who constitute 50 per cent of the population? What is the policy initiative of the Government towards ameliorating their pain and agony? The Government is silent on this.

On bringing black money too, this Government has failed to keep up its promise. It promised to deposit Rs.15 lakh in each citizen's bank account in 100 days. How would the Government to go about to reduce unemployment and create more employment?

On health ground too, the Government initiatives have taken a beating. See the grim scenario of Swine Flu. On the one hand, there is shortage of medicine to treat Swine Flu; on the other hand, Government has failed utterly in stopping the spread of Swine Flu. I want the Government to come out with concrete measures to stem this outbreak of Swine Flu before it takes the form of an epidemic.

When the stomach of poor is empty, how can you talk of engaging people in the process of governance and policy-making? The Government has to think of the rejection handed out by the people of Delhi in the recent elections. This is the mandate of the people of Delhi on 9 months governance of NDA.

The speech claims of inclusive growth covering poorest of the poor, and other disadvantaged sections of society. But it is a wishing thinking. It is not

been on the ground. In West Bengal, BJP is trying to disturb the law and other situation. People have taught then lesson in the recent elections, both Lok Sabha and State Assembly. People are with out leader, Kumari Mamata Banerjee. Success in the recent elections are the fruits of good governance given by our leader and Trinamool Congress.

Communal harmony is shaky since this Government took over the reins of the country 9 months back. President of US gave sermons twice in a span of 10 days. This augurs bad omen for this Government. PM kept silence. Even New York Times in its editorial stated that Modi's silence is dangerous. India's image is being tarnished. Our PM has failed to instill confidence among minorities on communal harmony and peace.

He comes up with "Mann ki Baat" on Radio. He is afraid of taking questions from the people. He is hiding behind the shield. He made a remark that our ex-PM, Dr. Manmohan Singh is not speaking at all. Now, he is doing the same thing. It seems he has two different yardsticks. Even our President while addressing the Governors asked them to ensure communal harmony, peace. Why has he made such a statement? Is it not because communal harmony and peace have taken a beating? Our Prime Minister has claimed that India is the fastest growing economy in the world. It is far from the truth when poor are having hand to mouth and not able to get two square meal a day.

Since it came to power, it has promulgated six Ordinances which have to be passed in Parliament. The Governments needs Opposition support but it takes Opposition for granted. It took the Opposition in Rajya Sabha for granted in the Winter Session of 2014 and went ahead for Ordinances, and now it wants the cooperation of Opposition in Rajya Sabha to pass these Bills. Is it not looking like a farce?

There are also rumours of Railways hiking the fares. Immediately after assuming power, Railways has hiked the fares. Now, it is planning to hike fares once again burdening the already overburdened poor. Is it what Government means governance, inclusive growth? We need answers to the issues raised by me? Is this what called 'present progressive' and 'future perfect'.

***डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़ (लातूर):** माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा जो विविध योजनायें शुरु की गई हैं, उनके बारे में अपने दीन-दलित, गरीब जनता के लिए 'जन धन योजना', 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'सबका साथ-सबका विकास' योजनाओं के बारे में कहा है। मैं माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार की विविध योजनाओं के बारे में और काम-काज के बारे में कहा है। आने वाले दिनों में हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाली है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किये हैं, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। भारतवर्ष के सभी वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार का कदम अच्छा है। 'सबका साथ-सबका विकास' का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। देश में अन्त्योदय योजना लागू करने का निर्णय भी स्वागतयोग्य है।

दूर संचार के क्षेत्र में 'ऑप्टिकल फायबर' का प्रयोग करके अच्छा क्रान्तिकारी निर्णय सरकार ने लिया है। इससे दूरसंचार के क्षेत्र में अच्छा काम होगा। जिन लोगों के पास घर नहीं है उन लोगों को घर देने की महत्वाकांक्षी योजना भी हमारी सरकार लागू करने वाली है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री, मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि वह हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई देशों के साथ भी अच्छा सम्बन्ध प्रस्थापित किया है। हमारी सरकार ने बी.पी.एल. के लिए भी एल.पी.जी. देने का काम किया है। 'स्किल्ड इंडिया' का नया प्रोग्राम माननीय मोदी जी ने शुरू किया है। इससे देश में सारे समाज के लोगों को फायदा होगा। यह एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. समाज के सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है।

मोदी जी की सरकार देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। धन्यवाद।

---

* Speech was laid on the Table

*श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : 16वीं लोक सभा का यह ऐतिहासिक क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सफल नेतृत्व में बजट सत्र की शुरूआत हो रही है। आज भारत की जनता को संसद से बहुत ही उम्मीद है। जनता पिछले 10 साल के कुशासन, महंगाई, भ्रष्टाचार तथा लालफीताशाही से परेशान हो गई थी। विदेशी मामले व विश्व मंच पर भारत की जनता सम्मान महसूस नहीं कर रही थी। पाकिस्तान जैसा देश भी भारत में बार-बार घुसपैठ की हिमाकत कर देता था। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा माहौल बदल गया है। विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरीका के राष्ट्राध्यक्ष श्री बराक ओबामा जी सपरिवार 26 जनवरी की परेड में मुख्य अतिथि बनकर गर्व महसूस किया है। आज अंतरिक्ष में भी हमारे क्रियाकलापों में प्रभावशाली प्रगति हो रही है। 24 सितम्बर, 2014 को मंगलयान को मंगल की कक्षा में स्थापित कर भारत पहले प्रयास में ही यह सफलता हासिल करने वाला प्रथम राष्ट्र बन गया है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति का वोट राजनीतिक प्रजातंत्र है तो सबको काम आर्थिक प्रजातंत्र है। आज से नौ महीने पहले सबका साथ-सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हमारी सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया है। पिछले नौ महीने के कार्यकाल को देखने के बाद जनता को लग रहा है कि यह सरकार उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास कर रही है। पिछली सरकार में शायद कहीं न कहीं जनता के साथ संवाद की कमी थी। जनता और सरकार के बीच खाई बन गयी थी। सरकारी योजनाओं में जनता की भागीदारी न के बराबर हो गयी थी। जनता के साथ-साथ केंद्र और प्रदेश की सरकारों के प्रशासन में तालमेल की कमी दिखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया है। मन की बात के माध्यम से जनता भी अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकती है तथा @gov.in पर जनता अपने सुझाव व नई योजनाओं के बारे में अपनी राय दे सकती है तथा प्रशासन की कमियाँ बता सकती है और अपनी परेशानियों से भी अवगत करा सकती है।

आज 67 वर्ष के बाद भी भारत की गरीब जनता, किसान, आधे से अधिक आबादी व परिवारों के पास बैंक खाते तक नहीं थे, इनका देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने का कोई भी चारा नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से गरीबी हटाने के लिए सबको देश की आर्थिक व्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरूआत की जिसने कम समय में 13.2 करोड़ लोगों के नये बैंक खाते खोलकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। आज भारत के अधिकतर गरीब परिवारों के पास बैंक खाते और डेबिट कार्ड हैं। आज भारत की गरीब जनता अपने आप को सरकार से जुड़ा हुआ मान रही है।

---

* **Speech was laid on the Table**

राजस्थान की जनता ने भी इस योजना से अपने आप को जोड़ कर सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र सिरोही की जनता ने राज्य में सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट खोल कर प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का संकल्प लिया है।

हमारी सरकार देश में आधारभूत संरचना के विकास के लिए वचनबद्ध है। इसी कड़ी में रेलवे के आधुनिकीकरण और नवीकरण का कार्य सबसे ऊपर है। यह सरकार हाई स्पीड ट्रेन शुरू करने जा रही है। आज आज़ादी के अनेक वर्षों बाद भी जालौर-सिरोही जिला केंद्र अभी तक रेलवे नेटवर्क से वंचित है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अनेकों लोग दक्षिण भारत में रहते हैं। जिले से दक्षिण भारत सीधी रेल सेवाओं का अभाव है। जिससे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र की तेज आर्थिक प्रगति के लिए कान्डाला से बाड़मेर वाया सांचौर नई रेल लाईन बिछाने की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि रेलवे के विकास के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध रही है जिससे देश के साथ-साथ जालौर-सिरोही क्षेत्र के लोगों का भी समुचित विकास सम्भव होगा।

मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के प्रयासों से नर्मदा नहर के माध्यम से सांचौर व जालौर के अनेक गाँवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से इनका आभार व्यक्त करता हूं। नर्मदा नहर के आने से यहाँ के किसानों की आय में वृद्धि हुई है परंतु इस क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण अनेक बार सूखे का सामना करना पड़ता है। यह क्षेत्र डार्कजोन घोषित है। यहाँ के भूमिजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण पानी पीने के लायक नहीं है। पिछली सरकार नर्मदा का पानी सांचौर से जालौर-सिरोही तक नहीं पहुंचा सकी मैं अपने प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ होने जा रही है जिससे हर खेत को पानी मिलेगा जिससे यह क्षेत्र पेयजल और सिंचाई की समस्या से निज़ात पा सकेगा साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया है और शीघ्र ही खराब होने वाली वस्तुओं के लिए 500 करोड़ की मूल निधि के साथ एक बहुमूल्य स्थिरीकरण निधि स्थापित की गयी है। देशी पशु प्रजातियों के संरक्षण और विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया है। जालौर-सिरोही संसदीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के लोगों का मुख्य कार्य कृषि है। यहाँ की विषम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ की मुख्य फसल जीरा, इसफगोल, बाजरा व मिर्च हैं। इस क्षेत्र में सूखा के साथ-साथ किसानों को पाला का भी सामना करना पड़ता है। बीमा पॉलिसी को दुरूस्त करने की सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। इसी प्रकार किसानों के उत्पादन का सही मूल्य मिले इसके लिए बाज़ार समिति, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस आदि के निर्माण की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए 2000

करोड़ रूपये का विशेष फंड बनाया गया है जिससे 72 अधिसूचित फूड पार्कों का निर्माण कर रही है जिससे कि लाखों लोगों को रोज़गार का अवसर प्रदान होगा। हमारी सरकार हाई स्पीड ट्रेनों की हीरक चतुर्भुज परियोजना शुरू करने जा रही है जिससे जल्दी खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों को परिवहन से देश के एक कोने से दूसरे कोने में आसानी से पहुंचाया जा सकता है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में आवास की समस्या है हमारी सरकार विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस 100 शहर बनाएगी। स्वच्छता और सफाई पर ध्यान देने के लिए आदर्श नगरों में एकीकृत अवसंरचना तैयार की जाएगी। जब देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा तब तक प्रत्येक परिवार का अपना पक्का घर होगा जिसमें पानी का कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति और आवागमन की सुविधाएँ हो इसके लिए Housing for all by 2022 का लक्ष्य रखा है।

आज आज़ादी के 67 वर्ष बाद भी देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की भारी कमी है जिससे सभी को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देखे तो 1000 की जनसंख्या पर मात्र 0.5 डॉक्टर ही उपलब्ध हैं। हमारी सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके इसके लिए नई स्वास्थ्य नीति तैयार कर रही है तथा नेशनल हैल्थ एश्योरेंस मिशन शुरू करेगी। योग और आयुष को प्रोत्साहन देगी। इससे हैल्थ्र केयर प्रोफेशनल की कमी दूर करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण में बदलाव किया जायेगा। यहां पहली बार हुआ है कि आयुष का अलग से मंत्रालय बनाया गया है। राजस्थान के अनेक जिला केंद्र के अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तन करने की दिशा में सार्थक पहल का कार्य शुरू कर दिया गया है।

भारत में पर्यटन की व्यापक एवं अपार संभावनाएं हैं जो हमारी सामाजिक, आर्थिक प्रगति में विशेष भूमिका अदा कर सकती हैं आज हमारी सरकार ऐसे 50 टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए मिशन के रूप में परियोजना शुरू करेगी जो विशिष्ट विषय वस्तु पर आधारित होंगे। मेरे क्षेत्र में माउंट आबू विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। माउंट आबू को जैन तीर्थ के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य शुरू किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में न्यूनतम सरकार-अधिकतम सुशासन के मंत्र पर कार्य करेगी और इस तरह संगठित सुदृढ़ और आधुनिक भारत का निर्माण होगा तब हमारा देश एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनेगा। अंत में मैं अटल जी की पंक्तियों के साथ सबका आह्वान करना चाहता हूँ-

बाधाएँ आती है, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएँ। पॉवों के नीचे अंगारें सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं।
निज हाथों में हँसते-हँसते आग लगाकर जलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा, चलना होगा।।

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने चुनाव में नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और अभी भी आपने बोला है सबका साथ और सबका विकास, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह विकास कुछ लोगों तक सीमित है। आपका नारा निराधार और असत्य है। आपकी सरकार ने जो शुरूआत की है वह कुछ ही लोगों के लिए की है। सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने हमारी सरकार के मंत्री का जिक्र किया है। सरकार के कुछ नेता कैसे बयान दे रहे हैं, क्या बोले हैं, क्या बोल रहे हैं। इस पर संसदीय कार्य मंत्री को गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर हमारे मंत्री ने कुछ बोला है, उसे मैं पता लगाऊंगा, लेकिन आपके नेता जो मंत्री भी है और सहयोग संगठन में हैं, वह समाज के एक बड़े वर्ग के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, इस पर आपको रोक लगाना चाहिए, इन पर नकेल डालनी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह (भदोही) : मुलायम सिंह जी, जो भी इस तरह का बयान देते हैं, वह ठीक नहीं है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Mulayam Singh Yadav says.

… (*Interruptions*)*

श्री मुलायम सिंह यादव : मैंने कहा कि हम अपने मंत्री के बयान को देखेंगे, बात करेंगे। मैंने अखबारों में पढ़ा है, क्या- कहा जा रहा है, क्या-क्या बोला जा रहा है, वह सभी को पता है। आपको नहीं पता है, हमारे बारे में क्या-क्या लिखा जाता था। पुराना समय याद कीजिए, क्या मैं छविराम का साथी हूं, मैं फूलन देवी का साथी हूं, मैं माधव सिंह के साथ डकैती डालता था, क्या नहीं लिखा गया मेरे बारे में। राजनीति में जो संयम और धीरज रखकर रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। माननीय वीरेन्द्र सिंह जी, मेरे बारे में आपको सब जानकारी है, एक-एक बात मालूम है इसलिए मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में स्वच्छ भारत और स्वच्छ मिशन की बात कही गई है। राष्ट्रपति जी वही बोलेंगे जो सरकार या कैबिनेट , भाषण बनाकर उन्हें देगा, यह मैं भी जानता हूं। गवर्नर साहब वही बोलते थे जो भाषण हम उन्हें बनाकर देते थे।

आपने स्वच्छता के बारे में कहा। स्वच्छता या सफाई कैसे होगी, उसका जिक्र आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहीं नहीं किया। यह गंदगी क्यों है? इस गंदगी का कारण गरीबी है। गरीबों के घर गंदे हैं। उनके घर के आस-पास की नाली, सड़क, रास्ता और दरवाजा गंदा है। जो सम्पन्न हैं, पैसे वाले हैं, धन-दौलत वाले हैं, उनके घर में सफाई है, लड़के-लड़की और पूरे परिवार में हर तरह की सफाई है। आपको

* Not recorded

इस बारे में सोचना चाहिए, लेकिन आपने इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह कहीं जिक्र नहीं किया गया कि ये सारी समस्याएं गरीबी के कारण हैं। गरीबी के लिए आप आगे जवाब देंगे कि वह कैसे दूर होगी। यह सब गंदगी गरीबी के कारण हैं और झाड़ू लगाने से यह साफ नहीं होगी। गरीबी मिटाने से सफाई आयेगी।

आप गांव, मोहल्ले, शहर में रहते हैं, तो आपको पता होगा कि कौन से घर गंदे हैं। इसी तरह गंगा की सफाई है। अब आप गंगा नदी की सफाई कैसे कर लेंगे? गंगा में जो नदियां गिरती हैं, वे गंदी हैं। हमें उन नदियों को साफ करना पड़ेगा। जब तक आप उन नदियों को साफ नहीं करेंगे तब तक गंगा साफ नहीं होगी। आप गंगा कैसे साफ कर लेंगे, यह सोच कर मुझे आश्चर्य होता है। इस संबंध में हम लोग बहुत बहस कर चुके हैं। सबसे पहले हिन्दुस्तान में डा. राम मनोहर लोहिया ने वर्ष 1952 में कहा था कि गंगा साफ करो, नदियां साफ करो। जब तक गंगा में गिरने वाली नदियां साफ नहीं होंगी तब तक आप गंगा कैसे साफ कर लेंगे?

माननीय प्रधान मंत्री जी बनारस में अस्सी घाट पर गये थे। उन्होंने वहां सफाई का काम किया। वह घाट कहां साफ हुआ। अस्सी घाट पर सफाई की जो शुरुआत की गयी थी, वह अभी तक चालू है। वह घाट अभी तक साफ नहीं हुआ है। आप हमारे समय का पता लगा लीजिए। मैंने इन घाटों को साफ करवाया था और घाटों को नहाने-धोने के लायक बनवाया था, चाहे वह अयोध्या, फैजाबाद, बनारस, या मथुरा का हो। हमने इन घाटों का साफ कराया था और वहां नहाने-धोने का इंतजाम भी ठीक से कराया था। उसके बाद आप सरकार में आ गये और हम हट गये। ...(व्यवधान) उस समय कुछ काम अधूरा रह गया होगा। हम उसे पूरा करना चाहते थे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि सफाई झाड़ू से न होकर गरीबी मिटाने से होगी। जब गरीबी मिटेगी तब सफाई हो जायेगी। यहां सभी मैम्बर्स बैठे हुए हैं। पार्लियामैंट के सब मैम्बर्स गंदे क्यों नहीं होकर आते? गांव के किसान, गरीब, मजदूर कैसे कपड़े पहनते हैं, यह सब जानते हैं। वे पूरे कपड़े न पहनकर आधा कपड़ा पहनते हैं। वह नहा कैसे लेंगे, साबुन कहां से लगा लेंगे, तेल कहां से लेंगे? आजकल नहाने के बढ़िया-बढ़िया साबुन आने लगे हैं, वे उन्हें कैसे लगा सकेंगे। यह सफाई गरीबी मिटाने से होगी। आपके झाड़ू लगाने से नहीं होगी, यह मैं आपको राय दे रहा हू।

गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए आपको सख्त कानून बनाना पड़ेगा। गंगा में अधजली लाशें डाली जाती हैं। यदि घाट पर मौत होती है तो अधजली लाश को गंगा में ही फेंक दिया जाता है। लोग इसे पवित्र मानते हैं और यह मानते हैं कि हमने इसे गंगा में बहा दिया है, तो वह स्वर्ग मे पहुंचेगा और आगे का जन्म अच्छा होगा। लोगों की ऐसी उम्मीदें या भावनाओं को हम नहीं रोक सकते, इसलिए आपको सख्त कानून बनाना पड़ेगा, ताकि लोग अधजली लाशें गंगा में फेंकने न पायें। आपको इसे रोकना पड़ेगा, तब गंगा

साफ होगी। यदि एक जगह गंगा का घाट साफ हो गया, क्या बनारस का घाट साफ हो गया? जो अस्सी घाट की बात हुई थी, क्या वह साफ हो गया? प्रधान मंत्री जी ने बनारस में जो सफाई का काम किया, वह काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। आप जानते हैं कि मैंने अगर शिलान्यास किया है, तो उसी दिन कहते थे कि उद्घाटन की तारीख क्या है? मैंने यह कर के दिखा दिया। आजादी के बाद नदियों पर जितने भी बड़े पुल बने थे, उससे ज्यादा पुल हमारी पिछली सरकार ने बनाये। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, क्वारी, चम्बल आदि नदियों के पुल बनकर तैयार हो गए। यहां उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं। जब हम जाते थे तो लोग कहते कि इस पुल का उद्घाटन कब कराएंगे। जब आपका संकल्प होगा, इच्छाशक्ति होगी, सरकार के अंदर साहस होगा, तब आप यह काम कर पाएंगे। आपके ऐसे बयानों से गंगा साफ नहीं हो सकती है। गंगा के बारे में मैंने बताया है आपको। फिर आपने 15 लाख रुपये भेजने की बात की थी, मैं आप से ही पूछता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। चुनाव घोषणा पत्र उस दल के लिए उतना ही पवित्र होता है, जितना लोगों के लिए गीता, रामायण या कोई अन्य ग्रन्थ पवित्र होता है। आप जनता के बीच वायदा करते हैं तो लोगों के खातों में 15 लाख रुपये अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? कब तक पहुंचेगा, यह भी बता दीजिए। जब आप जवाब देंगे, तब बताइए कि 15 लाख रुपये हर खाते में, साधारण परिवारों की जेबों में या खातों में कब तक पहुंचेंगे? इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाइए। अगर समयबद्ध कार्यक्रम बनाएंगे, तभी यह होगा।...(व्यवधान) जहां तक किसान की खेती का सवाल है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, let him speak. If you are making comments like that, I cannot run the House. A senior Member is speaking. Why are you shouting? He has a right to speak whatever he wants to. If you have any objection, you can reply afterwards.

श्री मुलायम सिंह यादव : बोलने दीजिए, वह अभी अनुशासन की बात कह रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सवाल है किसानों और खेती का, इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार खेती से ही मिलता है। आज 65 फीसदी लोग अपने हाथों से खेती कर रहे हैं। खेती 72 फीसदी से ज्यादा लोगों के पास है, लेकिन उनमें से 65 फीसदी किसान अब भी अपने हाथों से खेती करते हैं। बेरोजगारी कौन दूर कर रहा है? किसान बेरोजगारी दूर कर रहा है। लेकिन किसान का जिक्र कहीं नहीं किया गया। किसान का जिक्र आपके भाषण में भी बहुत नहीं आया, मुझे बड़ी उम्मीद थी आपसे, किसानों की बात नहीं की आपने। पैदावार की कीमत के बारे में कहा था कि डेढ़ गुनी कीमत देंगे। डेढ़ गुनी कीमत दें। यहां उत्तर प्रदेश के सब लोग बैठे हैं, बताइए क्या हुआ उत्तर प्रदेश में धान की खरीद में। ...(व्यवधान) किसी ने डेढ़ गुना दिया? डेढ़ गुना कीमत कौन देता है? भारत सरकार को देना था, मदद करनी थी, लेकिन भारत

सरकार ने नहीं की। उत्तर प्रदेश की जितनी उपेक्षा की गयी, उतनी उपेक्षा किसी अन्य राज्य की नहीं की गयी। मैं यहां कहना चाहता हूं। आप बात कर लेना, मैं आपसे बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के बिना आप कैसे हिन्दुस्तान को बना लेंगे? जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा, हिन्दुस्तान का विकास नहीं हो सकता। वहां पर 21 करोड़ जनसंख्या है, इन 21 करोड़ लोगों की उपेक्षा करके आप हिन्दुस्तान को सम्पन्न और शक्तिशाली नहीं बना सकते। अगर आपको विकास करना है तो उत्तर प्रदेश का भी विकास कर दीजिए। विकास सब सूबों का कीजिए, सब राज्यों का कीजिए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अकेले उत्तर प्रदेश का ही विकास हो, लेकिन अगर देश का विकास करना है तो विशेष सुविधा आपको उत्तर प्रदेश को देनी ही होगी। चार चीजें हैं - शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और बिजली। आप ये चार ही काम तय कर लीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और बिजली, इन चार चीजों का इंतजाम कर दीजिए, हिन्दुस्तान विकसित हो जाएगा। छोड़िए तमाम पोथी-पन्ना, इतना घोषणा पत्र। हमने सिर्फ 21 पेज का घोषणा पत्र लिखा है। आपका घोषणा पत्र में इतने पेज हैं कि उसे पढ़ ही नहीं सकते, हमारा 21 पेज का घोषणा पत्र है, उसे सब पढ़ लेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ, आप अभी कह रहे थे कि अभी आठ-नौ महीने ही हुए हैं। क्या आठ-नौ महीने कम हैं? आठ-नौ महीने कम नहीं होते हैं। नौ महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है। अब बताइए, क्या नौ महीने कम हैं? नौ महीने का समय बहुत होता है। फिर, आपको उत्तर प्रदेश की सरकार से कुछ सीखना पड़ेगा। शपथ लेते ही पहले ही दिन किसानों पर भूमि विकास बैंक के साढ़े सोलह सौ करोड़ रुपये को माफ कर दिया और प्रतिबन्ध लगा दिया है कि चाहे सरकारी बैंक हो या गैर-सरकारी हो, अब उत्तर प्रदेश में किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। प्रतिबन्ध लगा दिया। किसानों को प्राथमिकता देनी होगी। यह बात आपके भाषण में कहीं भी नहीं आई कि किसान की समस्या मुख्य है। जब तक किसान आर्थिक दृष्टि से कमजोर रहेगा, सम्पन्न नहीं होगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता है। आज हिन्दुस्तान के अंदर 65 फीसदी लोग पूरी तरह से खेती पर निर्भर हैं। वैसे तो इससे ज्यादा का प्रतिशत है, लेकिन सीधे-सीधे खेतों में काम करने वाले 65 प्रतिशत लोग हैं। यह मेरा नहीं, आपका आंकड़ा है और आप चाहें तो इसे मंगाकर देख भी सकते हैं।

आपने वादा किया था कि फसलों का लागत मूल्य न्यूनतम से डेढ़ गुना ज्यादा देंगे। क्या वह दिया गया, अगर दिया गया तो किसान को घाटा क्यों हुआ? आप देखें कि धान की पूरी बिक्री नहीं हुई है। काफी धान बिकने से रह गया है, क्योंकि उसे काफी सस्ता कर दिया गया है। इसलिए कि केन्द्र सरकार द्वारा कोई मदद नहीं दी गई। पहले थोड़ी-बहुत मदद दी जाती थी, लेकिन आपकी सरकार ने वह भी नहीं दी। अब आगे देखेंगे कि कितनी मदद आप करते हैं। किसान के बारे में मेरा यह कहना है कि जब किसान को सम्पन्न नहीं बनाएंगे, देश मजबूत नहीं हो सकता।

राष्ट्रपति जी खुद दुखी थे। अगर संविधान से बंधे न होते तो हरगिज भाषण नहीं देते। आपने जैसे ही संसद का पिछला सत्र खत्म हुआ, अध्यादेश जारी कर दिए। कुछ समय बाद ही फिर संसद का सत्र शुरू होने वाला था, तब भी आपने सात अध्यादेश जारी कर दिया। इनकी क्या जरूरत थी? स्वयं राष्ट्रपति जी ने कहा है कि अध्यादेशों से सरकार नहीं चलती है। क्या आपने कोई अध्यादेश किसानों के बारे में भी जारी किया है? आपको सोचना चाहिए कि जब अगला सत्र संसद का आने वाला है, 15-20 दिन में या एक महीने बाद तो फिर क्यों ऐसा किया जाए। आप बताएं कि आपने किस उद्योगपति को सुविधा देने के लिए अध्यादेश जारी किए? क्या वह उद्योगपति देश का विकास करने वाला कोई काम कर रहा है कि उसके लिए अध्यादेश लाना पड़ा? ...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि ये अध्यादेश उद्योगपतियों के लिए ही लाए गए हैं। अगर नहीं लाए गए हैं, तो फिर बताएं कि किसके हित में लाए, क्या गरीबों या नौजवानों के हित के लिए लाए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री जी आप सुन लें कि जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि चार चीजें शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सिंचाई का समुचित प्रबंध जब तक आप नहीं करेंगे, दोबारा सरकार में नहीं आ पाएंगे। इस समय आप ओवर-कॉंफिडेंस में रहे हैं। अभी जो हालत हुई है, उससे आपने सीखा नहीं है और न ही दिल्ली के चुनावों से कुछ सीखा है। आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि दिल्ली की जनता में क्या ऐसा हो गया कि सिर्फ तीन सीट्स विधान सभा की बीजेपी को मिलीं। हम तो सोचते थे कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में विधान सभा की 12 सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे। वे सारी सीट्स आपकी थीं, आपके ही विधायक थे, जिन्होंने लोक सभा का चुनाव लड़ा और यहां जीतकर आ गए। लेकिन जब उन 12 विधान सभा सीटों का उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने नौ में जीत हासिल की और आपके सिर्फ तीन विधायक ही जीत सके, जबकि पहले ये 12 सीट्स आपकी ही थीं। अब वहां लोग कह रहे हैं कि आगे भी आपकी सरकार होगी। अगर आपने उत्तर प्रदेश से इस मामले में सबक लिया होता, तो दिल्ली में आपकी यह हालत न होती, मजबूत होते। अब आपका फिर सरकार में आना मुश्किल लग रहा है। आपकी पार्टी में निराशा है, देश की जनता नाराज है। जिस तरह से आपने लोक सभा चुनावों के समय भाषण दिए थे, वादे किए थे, उन मुद्दों पर आपने कुछ नहीं किया।

मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनावों में आपको 71 सीट्स मिलीं और हम केवल पांच ही जीत सके। हमारी हार हुई। ऐसा कभी हमारे साथ नहीं हुआ था। पहले हम 17 सीट्स, 24 सीट्स और 27 सीट्स भी लोक सभा की जीत चुके हैं। लेकिन अब पांच ही जीत पाए। अगर गौर से देखा जाए कि हमें कितना वोट मिला तो सारे अखबारों के सम्पादकीय में यह लिखा था कि बीजेपी सावधान हो जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत केवल एक प्रतिशत ही कम हुआ है। इस तरह हमारा

वोट कम नहीं हुआ, हां, सीट्स कम हुई हैं। लेकिन उसके बाद प्रदेश की विधान सभा की 12 सीट्स के उपचुनाव में नौ में जीत हासिल की। जबकि ये 12 सीट्स आपकी थीं, आपके ही विधायक थे, जो लोक सभा के लिए चुन लिए गए थे और उनकी विधान सभा की सीट्स खाली हो गई थीं। इसलिए इन 12 विधान सभा सीटों का उपचुनाव हुआ था। यह जो आपका अति आत्मविश्वास है, यह खतरा है और इससे मैं आपको सावधान कर रहा हूं।

सरकार अध्यादेश ला रही है, लेकिन अरूण जेटली साहब ने वर्ष 2013 में यूपीए सरकार के अध्यादेश लाने का विरोध किया था। जबरदस्त विरोध किया था। मैं यहां था, लेकिन अब क्या हो रहा है? आप अध्यादेश पर अध्यादेश लाते चले जा रहे हैं। वह अध्यादेश सरकार और आप? राष्ट्रपति जी ने स्वयं कहा है कि क्या अध्यादेश से सरकार चलेगी? अध्यादेश लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है। सत्ता जाने वाली है, समय ज्यादा नहीं है। लेकिन आपने तो अध्यादेश से ही कानून बना कर काम शुरू कर दिया है। एक अध्यादेश किसान से जुड़ा हुआ है, भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भूमि अधिग्रहण मत कीजिए, पिछली सरकार यह बिल लायी थी तो इस पर बहस हुई थी। मैंने उस चेयर से भाषण दिया था और कहा था कि आप ऐसी भूमि का अधिग्रहण कीजिए, जो खेती लायक नहीं है। जो उर्वरा जमीन है, जो उपजाऊ जमीन है, उसे अक्वायर मत कीजिए। लेकिन अफसर वहां जाकर फीता डालता है जो किसान की अच्छी जमीन है, बढ़िया जमीन है। मैंने कहा था आगरा से लेकर बांदा तक क्वारी, चम्बल और यमुना का बीहड़ है। यह लाखों एकड़ जमीन है। आप वहां के बीहड़ को हटा दीजिए, इससे लाखों एकड़ जमीन उपलब्ध हो जाएगी। वह जमीन उपजाऊ है। मैंने वहां कुछ काम किया है। हमने भूमि सेना का गठन किया है। 65 हजार एकड़ जमीन खेती लायक बनायी है जो उपजाऊ नहीं थी। आज इस 65 हजार एकड़ जमीन पर हरदोई से लेकर कानपुर तक सैंकड़ो एकड़ हरी-भरी फसल दिखायी देगी। हमने भूमि सेना का गठन किया था। क्वारी, चम्बल और यमुना के बीहड़ में आपको लाखों एकड़ जमीन मिल जाएगी। आप बीहड़ को गिरा दीजिए। इससे कानून व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। कुछ काम तो मैंने किया है। इटावा डकेतों के छिपने का सबसे सुरक्षित स्थान था। इटावा में तीनों नदियां एक हो जाती हैं। यहा बीहड़ बहुत दूर तक था और छिपने का बहुत अच्छा स्थान था। हमने डकैत खत्म किए हैं। अब डकैत कहां हैं? हम पहले भी आपको यह राय दे चुके थे। लेकिन आप हमारी राय क्यों मानेंगे? आप मानना ही नहीं चाहते हैं।

आपने बहुमत की बात कही। हमने बहुत बहुमत वाली सरकारें देखी हैं। हमने स्वयं देखा है। हम गिना नहीं सकते हैं। लेकिन सन् 1977 का बहुमत क्या मामूली था? ख़ैर, आप भी उसमें शामिल थे। तब कांग्रेस की तूती बोलती थी। इंदिरा जी की सन् 1971 तक तूती बोलती थी, लेकिन सन् 1977 में क्या हुआ? शायद आप तो बेल्जियम चले गए, लेकिन हम तो एमरजेंसी के टाइम में 19 महीने जेल में रहे हैं। जब चुनाव हुआ, संसदीय कार्यमंत्री जी, चंडीगढ़ से लेकर कोलकाता तक एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। इसलिए आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। आपने बयान दिया है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में जिसने सरकार बनायी है, वह

रोज़ाना ही अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि अहंकार नहीं होना चाहिए। अभी आपकी सरकार के कुछ लोगों को अहंकार है। आपने मेरी सरकार के एक मंत्री का बयान पढ़ा, लेकिन क्या कभी आपने अपनी सरकार के मंत्रियों का बयान पढ़ा है कि एक समुदाय के खिलाफ कैसे-कैसे बयान दिए गए हैं? आपने कटिंग दिखा दी है, हमने नहीं दिखायी है। आप कहेंगे तो दिखा देंगे। आपकी पार्टी के लोग सत्ता में रह कर ऐसे बयान देंगे? ये आपकी पार्टी के जिम्मेदार लोग सत्ता में रहकर कैसे-कैसे बयान दे रहे हैं और वह भी इतनी बड़ी बहुमत संख्या के खिलाफ। यह अच्छा नहीं हो रहा है। जहां तक हमारे मंत्री का सवाल उठता है, हम पता लगाएंगे मंत्री ने किस परिस्थिति में बयान दिया।...(व्यवधान)

श्री बृजभूषण शरण सिंह (कैसरगंज) : खैर, वे माफी मांग चुके हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव: एक ने मांग ली लेकिन क्या औरों ने मांगी? कितने लोगों ने बयान दिया है? क्या एक ने बयान दिया है? हम वहां थे। एक ने बयान नहीं दिया है। रोजाना कोई न कोई बयान दे रहा है। आप पढ़िए। उस बयान में अहंकार है। हमने बहुमत बहुत देख लिया। आपने भी बहुमत देखा। किसी ने अभी कहा कि न जाने आप 1975 में जेल गये या नहीं गये? हम तो 19 महीने जेल में रहे और जेल से छूटने के बाद संभल गये तथा सारी सीटें कांग्रेस हार गई। इंदिरा जी से ज्यादा कोई लोकप्रिय नेता नहीं था। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी लेकिन सन् 1980 में फिर हम लोगों का सफाया हो गया। आपसे भी लड़ गये। आपने आरएसएस को नहीं छोड़ा। आप दो दफ्तर चलाते ही रहे। सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी की एक मांग थी कि राजनाथ जी, आप दफ्तर एक ही रखिए। बीजेपी और आरएसएस एक ही साथ बैठें। आरएसएस का दफ्तर अलग चल रहा है, बीजेपी का अलग चल रहा है। अब भी आरएसएस के निर्देश से ही काम हो रहा है। क्या आप आर. एस.एस. निर्देशों से काम करेंगे? फिर वही हाल हो जाएगा। अब तो चर्चा हो गई कि वास्तव में यह सरकार तो आरएसएस के निर्देशों से चल रही है। उसी के मिनिस्टर बन रहे हैं। उसी के निर्देश पर काम हो रहा है। इसलिए यह आरएसएस और बीजेपी दोनों एक दफ्तर कैसे नहीं बना रही है?

हमारे यहां भी यूथ ब्रिगेड है, बिजय वाहिनी है, महिला संगठन हैं। सब संगठनों का दफ्तर एक है। उसी में सबका दफ्तर है और आपका आरएसएस का दफ्तर अलग है और बीजेपी का अलग है तथा गुप्त बातें जो रात में होती हैं, उसका दफ्तर अलग है। इसलिए आप सोचिए। जनता यह देख रही है। जो आपकी लोकप्रियता मोदी साहब की यहां से वहां तक थी, जिस तरह से आपके द्वारा जनता को कहा गया कि हम सबको रोजगार दे देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सात करोड़ पढ़े-लिखे बेरोजगार हैं। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उनका जिक्र कहां किया गया है कि सात करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उनमें हर साल कितने लोगों को रोजगार दे देंगे और वे पढ़े-लिखे लोग हैं। जो खेतों में काम करते हैं, उनको भी पूरे साल काम

नहीं मिलता है। केवल बुबाई और कटाई के समय पर ही काम मिलता है। वे बेरोजगार लोग हैं। इन लोगों के बारे में अभिभाषण में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। हम बहुत ज्यादा आपसे नहीं लड़े हैं। हम कांग्रेस से लड़े हैं। आपने देखा होगा कि हमारी उनसे कितनी लड़ाई हुई है? लेकिन उन्होंने मनरेगा चलाकर लोगों को कम से कम सौ दिन काम देने का काम तो किया है। लेकिन आपने तो वह भी नौ महीने में छीन लिया। मनरेगा के तहत जो लोगों को सौ दिन का काम मिलता था, वह भी आपने खत्म कर दिया। आप तो पूरी तरह से जन विरोधी काम करने में जुट गये हैं और अहंकार में हैं। मैं आप लोगों को सुलझे हुए लोगों में से मानता हूं। आप इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। हम आपको पहले से जानते हैं। जेटली साहब का काम करने का मैंने तरीका देखा। वह मिनिस्टर थे। एक बहुत बड़े काम के लिए मैंने उनको कहा, तीसरे दिन उन्होंने ऑर्डर कर दिया। अब तो आपके यहां लोग मारे मारे फिर रहे हैं। एमपीज मारे मारे फिर रहे हैं। सरकार में रहकर भी आपके यहां कोई सुनने वाला नहीं है। कोई मिनिस्टर सुनने वाला नहीं है। अब आप लोगों की सुनते होंगे तो मुझे पता नहीं है। शिकायत तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी है। इसलिए जो अहंकार है, उस पर आपको विचार करना चाहिए।

किसान अपनी जमीन को अपने प्राणों से ज्यादा मानता है। क्या आप भूमि अधिग्रहण करेंगे? आप भूमि अधिग्रहण करेंगे तो आप इसका नतीजा देखना कि देश में क्या होगा? किसान इसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। किसान मरना स्वीकार कर लेगा लेकिन ज़मीन नहीं देगा। किसान के पास जमीन के अलावा है ही क्या? किसान के पास जमीन के अलावा न रोजगार है, न नौकरी है, न धंधा है और न व्यापार है, उसके पास कुछ भी नहीं है। उसके पास केवल खेती है। उसके पास केवल खेती है। आप भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं। पहले सरकार कानून लाई तो मैंने बोला था और मैं अब भी आपसे कह रहा हूं कि आप भूमि अधिग्रहण क्यों कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि कई जगह हैं, आप अगर नीचे करेंगे तो हम बता देंगे, लाखों एकड़ जमीन आपको मिल जायेगी, जो गैर उपजाऊ है, वह उपजाऊ हो जायेगी, वहां कारखाने लग जायेंगे। आप वहां जो करना चाहें, करिये। आपको मैंने कह दिया कि आगरा से लेकर बांदा तक का नापना कर लीजिए, क्वारी, चम्बल, यमुना का बिहड़ है, उसे गिराकर कारखाने लगाइये, वहां कितना बढ़िया काम होगा, खेती भी हो जायेगी और आपके कारखाने भी लग जायेंगे, उद्योगपति जो काम करना चाहते हैं, उनका काम भी हो जायेगा, वहां कारखाने लगेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, मैं चाहता हूं कि वहां कारखाने लगें। हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों की जमीन लेकर लगेंगे तो हम उसके विरोधी हैं और हम अच्छी तरह से विरोध करके दिखायेंगे, अगर आपने ऐसा किया तो। इसलिए किसानों की जमीन बचाइये। आप नौ महीने की बात कहते हैं, मैंने बता दिया कि नौ महीने का समय बहुत होता है। मैंने बता दिया है कि नौ महीने में

तो बच्चा पैदा हो जाता है और आप नौ महीने में कुछ नहीं कर पाये। नौ महीने बहुत होते हैं, आपको पहले दिन ही करना चाहिए। लोक कल्याणकारी सरकार वह होती है, जो ओथ लेने के तत्काल बाद देश की जनता के लिए कोई न कोई काम करना चाहती है, जैसा यू.पी. में सरकार ने किया है। वहां साढ़े सोलह सौ करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया और उनकी जमीन नीलाम नहीं हुई न होगी। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई मुफ्त है, दवाई मुफ्त है, सिंचाई मुफ्त है, कन्या विद्या धन अलग से है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कन्या विद्या धन की व्यवस्था है। ...(व्यवधान) आप क्या बात करते हो, आप सचाई को भी झुठला रहे हो। वहां कन्या विद्या धन का भत्ता मिल रहा है, बेरोजगारी का भत्ता मिल रहा है। नौकरी देंगे, रोजगार देंगे और अगर नहीं दे पायेंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपको भी ऐसा करना चाहिए। अगर आप लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं तो जैसा यू.पी. सरकार कर रही है, वैसा कीजिए उसका एग्जाम्पल आपके सामने है। जो यू.पी. कर रहा है, वैसा केन्द्र सरकार को भी करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छे काम कर रही है, मैं आज सदन के अंदर सभी से कहना चाहता हूं कि जो काम यहां नहीं हो रहा है, वहां हो रहा है। ठीक है, मीडिया आपके साथ है और मीडिया के कुछ लोग मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे डकैत बताया था, मुझे छवि राम गिरोह का मैम्बर बताया था, हमें तो फूलन देवी का और न जाने क्या-क्या बताया था। मुझे लोग कहते थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सीधा लड़का है, इसके बारे में ऐसा क्यों लिखते हैं। नतीजा यह हुआ कि वे मेरे पक्ष में हो गये और पक्ष में होने के बाद उन्हीं की बदौलत मैं आज यहां हूं। छठवीं बार लोक सभा में जीते और 11 बार विधान सभा जीते। वह अलग बात है कि विधान सभा से इस्तीफा देना पड़ा और लोक सभा से भी एक बार इस्तीफा देना पड़ा और मुख्य मंत्री बनने चले गये। भले ही हमारी जनता अनपढ़ है, आप वह जमाना याद कीजिए, जब इंन्दिरा जी जैसी लोकप्रिय नेता रायबरेली से हार गईं।...(व्यवधान) आपका मैंने नाम लिया था, आपने मेरा काम हल कर दिया था। मैंने डिनर के समय यह कहा था कि यह काम कर देना, वह कोई मामूली काम नहीं था, आपने बड़ा काम किया था। कोई ऐसा नहीं करता, आपने बड़ा काम किया है। आप न्याय मंत्री थे, याद कीजिए, आपने मेरा काम किया था। मैंने आपको शाम को कहा था और आपने सवेरे काम कर दिया था। आपकी पार्टी में ऐसे लोग हैं। मैं आज तक इस बात को याद करता हूं कि डिनर पर हमने आपसे बातचीत की और आपने काम कर दिया। क्या वह कोई मामूली काम था। नायडू साहब, आप इनसे भी सीखिये। जहां तक यह सवाल है कि विरोधी पक्ष का साथ दिया है, आज आपको कहना चाहते हैं कि क्या बेरोजगारों, नौजवानों और महिलाओं का अभी हमने जिक्र किया, इस देश के अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, हरिजनों को सरकार ने विश्वास में लिया है? सबके साथ चलना है, सबको विश्वास में लेना है। सबका काम करना है। महिलाओं के लिए क्या किया है? बेरोज़गारों के लिए अभी तक क्या किया है? कोई काम नहीं किया है। किसानों के लिए कौन सा काम किया है, जिससे चर्चा हो कि किसानों के लिए काम किया है। अब नौ महीने होने जा रहे हैं, इन लोगों के लिए एक भी काम नहीं किया है। पिछड़ों के लिए, हरिजनों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कोई काम अभी तक इस सरकार ने नहीं किया है।

महंगाई का दावा करते हैं कि हमने महंगाई कम कर दी। लेकिन महंगाई आपने कम नहीं की है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार का जो मामला है, उसकी वजह से आपकी कुछ महंगाई कम हुई है। आप प्रचार कर रहे हैं कि आपने महंगाई कम कर दी है। ...(व्यवधान) वह तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ मजबूरी हो गई है। ...(व्यवधान) इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब तुलनात्मक प्रगति हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैट्रोल और डीजल की कीमतों की कमी से जो राहत मिली है, उस पर सरकार अपनी नीतियों की सफलता का दावा नहीं कर सकती है। इन नौ महीनों में न तो निवेश बढ़ा है न ही उत्पादन में वृद्धि हुई है। नौ महीने निकल गए, लेकिन इनमें से एक भी काम नहीं हुआ है। यहां तक चुनाव के नारे में जो संकल्प था, वह मैंने बता ही दिया। आज हम कहना चाहते हैं कि गंदगी का सबसे बड़ा कारण यह शौचालय है और उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है बृजभूषण शरण सिंह जी, यू.पी. में हमने शौचालय कब बनवाए, कितने साल हो गए हैं? ...(व्यवधान) आपके यहां अब शौचालय का जिक्र हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश के घर-घर में, गांव-गांव में शौचालय बनवा चुके हैं। ...(व्यवधान) अब परिवार में बंटवारा हुआ है। चार भाई अलग-अलग हुए हैं, तो अब थोड़ा होगा, उनका रह गया है, वह भी करवा देंगे। उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में शौचालय बने थे। ...(व्यवधान) हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप 2022 की बात करते हैं, आपका तो कार्यकाल 2019 तक है? ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mulayam Singh Ji, Please wind up.

श्री मुलायम सिंह यादव : आप सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। क्या आपने राज्य सरकारों को विश्वास में लिया है? क्या आपने स्थानीय निकायों को विश्वास में लिया है? क्या हम लोगों को, जो सांसद हैं, उनको विश्वास में लिया है? सबका साथ, सबका विकास, लेकिन साथ किसका लिया है? अभी तक किसका साथ लिया है? अभी तक मुझे यह पता नहीं कि किसान का साथ लिया हो, अल्पसंख्यकों का साथ लिया हो, महिलाओं का साथ लिया हो, बेराज़गारों का साथ लिया हो? जब तक सबका साथ नहीं लोगे तब तक तो यह सही है कि देश विकास नहीं कर सकता है तो सबका साथ लीजिए, सबका साथ लिया है या नहीं लेकिन नारा दे रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास। जहां तक सवाल है 13वें वित्त आयोग के फैसले के कारण राज्यों के हित का 32 से 42 सैंकड़ा बढ़ा है। यह सही है, लेकिन बेरोजगारी पहली प्राथमिकता है और शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई, जो मैंने आपको बताया है। इस पर आप ध्यान देंगे तो सही है कि आप सफल हो सकते हैं और इसमें हम सहयोग दे सकते हैं। ये काम कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे, हम विरोध भी नहीं करेंगे। कोई अड़चन भी नहीं पैदा करेंगे। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Mulayam Singh Ji, Please conclude.

श्री मुलायम सिंह यादव: जहां तक सुरक्षा का सवाल है, नागरिक की सुरक्षा और सीमा की सुरक्षा, कोई जिम्मेदार हो, क्योंकि यह तो लंबी बहस है, सन् 1947 में जितनी जमीन हिंदुस्तान के पास थी, अभी नहीं है, लाखों एकड़ जमीन पाकिस्तान और चीन में चली गई।

16.00 hrs.

मेरे पास आँकड़े हैं। उस वक्त लोहिया जी ने बहुत कुछ ऐसा कहा था, जिसकी चोट नेहरू जी को लगी थी। इसी सदन में उन्होंने कुछ ऐसा शब्द इस्तेमाल किया था कि यह आयातित सरकार है। इस तरह के शब्द उन्होंने कहे तो नेहरू जी उस समय चेयर से उठकर चले गए। जो भी बाद में उनके पास जाता था तो वे उससे पूछते थे कि लोहिया जी और क्या बोले। इसी सदन में राम मनोहर लोहिया जी बोले। अब आप इस बारे में सोचिए। हम लोगों ने उनका भाषण भी सुना है। हम उनके जमाने में एम.एल.ए. भी हो गए। हम एम.एल.ए. थे, बगल में नरेश हैं, वे कन्नौज से पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे। कन्नौज से हम लोग लगातार जीत रहे हैं। अखिलेश सांसद रहे, हम भी वहाँ से सांसद रहे, अखिलेश तीन बार रहे, अब डिम्पल दूसरी बार सांसद हो गई हैं। हम लगातार वहाँ से जीत रहे हैं। एक बार छोटे सिंह हो गए थे।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please finish it now.

श्री मुलायम सिंह यादव : वह सीट हम लगातार अभी तक जीत रहे हैं। जहाँ तक आपका सवाल है, आप सोचिए। आपने पड़ोसी देशों से सहमति बनाई, यह अच्छा काम किया है, ठीक है। आपने पड़ोसी देशों से बातचीत भी की। मैं इस बात से सहमत हूँ कि पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते हों। अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ मेहमान बनकर आए तो उन्होंने क्या कहा, जब आखिरी दिन वे यहाँ से चले तो वे क्या कहकर गए? उन्होंने कहा कि सामाजिक और साम्प्रदायिक सद्भाव के बिना, आप पर आरोप लगा दिया, उन्होंने कहा कि सामाजिक और साम्प्रदायिक सद्भाव के बिना इस देश में न तो सामाजिक समरसता बढ़ेगी और न ही आर्थिक विकास होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जी यह कह गए हैं। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में अल्पसंख्यकों की बैचेनी क्यों बढ़ रही है? आप बताइये कि बैचेनी क्यों बढ़ रही है, अल्पसंख्यकों को आपकी सरकार के आते ही बैचेनी क्यों है? बैचेनी है, आप इस बात का ध्यान रखिए। अगर वह मंत्री वही है, जो मेरे दिमाग में आया है, तो वह बैचेनी का बयान है। आपने कहा कि ऐसा बयान दिया है। अगर वे हैं तो वही होंगे। मैं नहीं जानता कि कौन मंत्री हैं, अभी जाकर पूछूँगा।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : हमने सरकार के पास भेजा हुआ है।

श्री मुलायम सिंह यादव : दिया होगा, हम बात करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में अल्पसंख्यकों की बैचेनी क्यों बढ़ रही है? प्रधानमंत्री जी आश्वासन दें, इसके बिना बिल्कुल काम नहीं

चलेगा। आश्वासन तो दिया है, लेकिन आप उसके अनुरूप काम तो कीजिए। उन आश्वासनों में से एक भी काम अभी तक 9 महीने में नहीं कर पाए हैं। तभी तो मैंने कहा कि 9 महीने बहुत होते हैं। लोक कल्याणकारी सरकार वह होती है, जो ओथ लेते ही कुछ काम करे। जैसे हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जैसे ही ओथ ली, साढ़े सोलह सौ करोड़ रूपए कर्ज माफ किया और जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता। भूमि सेना का गठन, बंजर, ऊसर जमीन, पहले मैंने 65 हजार एकड़ जमीन जो ऊसर, बंजर जमीन थी, उसे खेती लायक बनाया था और भूमि सेना का गठन किया था। अब भूमि सेना का गठन फिर हो गया है, हम जाते ही उत्तर प्रदेश की सरकार से बात करेंगे, जमीन को बढ़ाएंगे। यह बहुत गम्भीर समस्या है। जमीन तीन फीसदी प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। आप नोट कर लीजिए कि तीन फीसदी प्रतिवर्ष जमीन घट रही है। जनसंख्या बढ़ रही है। अब आस्ट्रेलिया, अमेरिका भी आपको गेहूँ नहीं दे पाएगा, वहाँ भी संकट होगा। इसलिए आत्मनिर्भर रहने के लिए जो ऊसर, बंजर, बीहड़ जमीन है, उस जमीन को खेती लायक बनाइए। ऐसा करने से जो लोग बेरोजगार हैं, जो मजदूर, किसान हैं, उन्हें काम मिलेगा। हमने 65 हजार एकड़ जमीन ठीक करके दिखा दी। आप देखिए हरे-भरे खेतों में है। आप कानपुर रोड पर चले जाइए, हरदोई रोड पर चले जाइए, उसे देखकर मैं भी खुश हो जाता हूँ। कहते थे कि वहाँ तो कभी पौधा नहीं जमेगा, लेकिन वह जम गया और लोगों को काम मिल गया। दोनों काम हो सकते हैं, बेरोजगारों को काम मिलेगा, मजदूरों को काम मिलेगा और आपकी खेती बढ़ेगी।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please wind up now.

श्री मुलायम सिंह यादव : खेती बढ़ेगी तो पैदावार बढ़ेगी। हम आपको यह सुझाव दे रहे हैं। आपकी सरकार लोकप्रिय बने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देश उन्नति करे। देश मजबूत करने के लिए आपने सहयोग माँगा, आप काम करिए, आप ऐसे काम करिए, जिससे हम लोग आपका साथ दें। देश को मजबूत करने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोगों का, समाजवादियों का यह चरित्र है कि अगर देश के विकास के लिए कोई अच्छा काम करेगा तो हम अनावश्यक उसके खिलाफ नहीं हो सकते हैं। मैंने जेटली साहब की तारीफ कर दी, मैंने शाम को कहा, सुबह उन्होंने ऑर्डर कर दिए। यह बात होती है।

आज हालत यह है कि हमारे लोग जा रहे हैं। आपके मंत्रियों से काम नहीं हो रहा है। आपके लोग भी जा रहे हैं, वे भी दुखी हैं, हम ही नहीं हैं। हम तो हैं ही नहीं कि आप हमारी बात मान लेंगे। आप हमारी बात मान लेंगे, यह सही है। प्रधान मंत्री हमारी बात मान लेंगे, यह सही है। अगर हम प्रधान मंत्री को अपने गाँव में भेजें तो आप देखेंगे कि बहुत लोगों को परेशानी है। हमारे यहाँ भी, हमारे लोगों को भी परेशानी है। लेकिन हम उनको देश का प्रधान मंत्री मानकर ले गए। प्रधान मंत्री अगर बीजेपी का होता तो मैं कभी नहीं ले जाता। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Deve Gowdaji, you please stand up; then only I can ask him to sit down. If you keep sitting, he will continue. If you stand up, he will conclude.

… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव: मैं तो समझता हूँ कि प्रधान मंत्री देश का प्रधान मंत्री है, हमारा भी प्रधान मंत्री है, इसलिए हम प्रधान मंत्री का आदर करेंगे। आप ऐसा काम कीजिए कि आप हमारे भी मिनिस्टर हैं और जनता के भी हैं। आप अगर बीजेपी के मिनिस्टर रहे तो लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं। यह मैं आपको सहयोग देने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देश को मज़बूत करने के लिए, नौजवानों को रोज़गार देने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं को विशेष अवसर देने के लिए और यदि महिलाओं को विशेष अवसर नहीं देंगे तो देश और समाज में सुधार नहीं हो सकता। यह काम समाजवादी पार्टी ने किया है और नहीं तो आप आ जाइए एक दिन और लखनऊ में बैठकर समीक्षा कीजिए और फिर सवाल बनाकर ले जाइए कि महिलाओं के लिए क्या किया है, बेरोज़गारों के लिए क्या किया है, किसानों के लिए क्या किया है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Mulayam Singhji, please sit down. It is difficult to control you.

… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव: हमने विशेष निधि दी थी, उत्तराखंड को निधि दी थी, बुंदेलखंड को दी थी, पूर्वांचल को दी थी, जो पिछड़े और उपेक्षित इलाके हैं, उनको मैंने बजट के अतिरिक्त विशेष निधि के नाम पर आगे बढ़ाने का काम किया था। मुझे विश्वास है कि आप जो कह रहे हैं और जनता कह रही है, अगर देश मज़बूत करने के लिए सही सकारात्मक कदम आप उठाएँगे और हमारा सहयोग मांगेंगे तो देश को मज़बूत करने के लिए हमने हमेशा सहयोग दिया है और जब-जब चीन ने हमला किया है या पाकिस्तान ने हमला किया है, तब-तब पूरा देश खड़ा हो गया है, जनता खड़ी हो गई है। आज हम फिर दोहरना चाहते हैं कि चीन पर विश्वास मत कर लेना। प्रधान मंत्री जी जब चीन में हाथ मिला रहे थे, तब चीन की फौजें आपकी सीमा में घुस रही थीं और जब यहाँ वे आए तो आपको कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। तब कह तो देते कि चीन क्या कर रहा है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Shri Mulayam Singhji, please conclude.

श्री मुलायम सिंह यादव: अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए लेकिन आपने नहीं कहा। आपने कहा कि यह सब अच्छा काम किया है। मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते हों, यह ठीक है, लेकिन रिश्ते

के मायने झुकना नहीं है। अगर कमज़ोरी की खातिर रिश्ते करेंगे तो वह देश के हित में नहीं है। आप मज़बूत बनिए। अगर आप मज़बूत बनेंगे तो सब आस-पास के आपके दोस्त हो जाएँगे। कमज़ोर को कोई नहीं पूछता है। राजनीति हो या सरकार हो, कमज़ोर को कोई नहीं पूछता है। शक्तिशाली की पूजा होती है, इसलिए आप देश को शक्तिशाली बनाइए। अगर हम देखेंगे कि आप देश को शक्तिशाली बनाएँगे तो हम आपका सहयोग करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

[*] **DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR)** : Hon. President has mentioned so many achievements of this Government in his Address. In this regard, I would like to emphasize upon certain aspects. The people of this country are capable enough to develop emphatically, if an efficient Government is there to lead them from the front. That's why Congress was rejected for their failure to perform and this Government was given the mandate because of their promises made during the time of election. However, over a period of nine months, not a single promise has been fulfilled. The President in his initial address has sated about the welfare of all the human being, that is 'Sabka Saath Sabka Vikash'. But the very concept or ideology behind these words have been defeated by the scrupulous intention of this Government which has been resulted in the initiative of 'ghar Wapsi', religious conversion, riots etc. in various parts of the country. So, at this juncture when we are talking about development of all, it is necessary to think in part of the Government to overcome it in order to send a right message to appropriate the mandate they were given.

The Government has driven the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana to eliminate the poverty. In this regard, the Government is claiming that almost 100% of accessibility to banking facilities has been achieved by them, which is a blatant lie. Keeping their claim in view, I would like to state that my State Odisha is a poor state and almost 23% of its population is Scheduled Tribe and they reside in remote forest areas where there is no Bank Branches, no telecom communication and even no transportation facilities as these areas are affected by left wing Extremists. In spite of repeated requests made by the Government of Odisha no initiative was taken by the Government to open bank branches in these areas. Hence, the project especially in these tribal areas is yet to be fulfilled. So, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is a failure in these areas. So, I request the Government to look into the issue and expedite covering all the areas under Project by ensuring accessibility to bank facilities for people to open their account.

---

[*] Speech was laid on the Table.

In respect of Railways also no due share is being given to my State though Odisha is contributing more revenue in this area. So, my request is that more number of trains should be introduced in respect of Odisha along with laying of more railway tracks in the State.

[*] **SHRI R. DHRUVANARAYANA (CHAMARAJANAGAR) :**People of this great nation has given decisive mandate to this government in the last Parliament general election expecting the change. Similarly, the current ruling party has also made so much of poll promises to the people of this great nation. If you look at the track record of this government's past nine months, nothing was done or no major decisions were made in favour of common man and for welfare of depressed class people. Neither has it had any vision for welfare of depressed classes, women and children. Addressing country man frequently doesn't solve the purpose but it needs an affirmative action and implementation of welfare schemes.

The gap between rhetoric and delivery is widening day by day. Government is failed to deliver his poll promises of bringing changes in the governance. Transparency in the government's major decisions is become zero. I wanted to point out that, the NDA government has been lucky to get a favourable external environment with the fall in global oil and commodity prices. But even then government has delivered nothing in the past nine months are so.

Hence, herewith I urge this Government to look into the following core areas, where country needs special attention at this point of time.

- **NREGA :** It is one of the flagship programs of previous UPA government for the welfare of poor people across the country, which was assured minimum 100 days job for people of this nation. The recent several survey and social audit done by various agencies have accepted fact that, NREGA has made the greater impact on livelihood of Rural India people and also enable them for financially self-sustainable. But the current government is not allocating proper fund and neglected this program just because it was initiated by previous government. It shows that government is not serious about welfare of depressed class people and the welfare of Rural India. The

[*] Speech was laid on the Table.

impact of uneven distribution monsoon and failure of monsoon rainfall change as a result of climate change is impacting large part of the livelihood of families of rural India. The only source of income for these families is government sponsored job schemes and government must understand the fact.

- **Minimum Support Price for Agriculture Products -** Even after decades of economic reform, majority contribution of economy is agriculture. It is duty of every government, every political parties to work for the welfare of farmers. In the today's scenario of changed global and domestic economy the agriculture products produced by these farmer community is not getting the scientific minimum support price from the government.
- **Special Component Plan for SCs and STs -**Based on the latest census (2011), SCs and STs population forms 25% of total population (Scheduled Castes at 16.6 percent and Scheduled Tribes at 8.6 percent). Similarly, the fund allocation for welfare of these communities under special component plan should be increased as per the population growth. The current fund allocation is not justifiable when it compared to rate of growth of population of these communities. Government also makes sure all the allocated funds under the welfare scheme must be properly utilized by various state governments and to other Ministries within the stipulated time plan.
- **Sansad Adarsh Gram Yojana** - Government has launched this program with a loud noise of thinking of creating a great change of livelihood of rural people by improving the basic amenities in the villages. But at the same time, Government is not so much serious when it comes to delivery or implementation of its thoughts. I urge the Union Government to provide appropriate fund allocation for Sansad Adarsh Gram Yojana.
- **Rural Housing** - Government must increase the Central Government fund allocation for construction of houses under Indira Awas Yojana. Currently,

government is providing Rs.52,500/- per house unit construction. When it is compared to current commodities it is very much less. Hence, I urge the Union Government to double the Central Government contribution for per household unit construction. Currently only 50 house units are being allocated for every gram panchayats under this scheme, I request to increase this allocation number of house units for 100 per gram panchayats.

- **New Hostels for SC and ST** - It is a duty of every government to help and upgrade the depressed class communities. This will be done only through providing education, shelter and job for these communities. Even today the condition of these depressed communities across country i.e. especially in rural areas is way behind our imagination. It is very difficult for students of these communities to continue their education due to lack of facilities in their homes and villages. Hence, I urge the Government to increase the number of hostels both for male and female students of these communities by building new hostels. Story doesn't end here, Government should also provide the facilities in the hostel to enable the students to prepare themselves to face the global challenges. As a result Government should also provide the computer education facilities, libraries and training for spoken English classes in their hostel itself.
- **Pre and Post Metric Scholarship for SC/ST**-The survey conducted in the recent years has concluded that, the school dropout rates are higher and become common in SC/ST students due to financial restrictions. Student belonging to these communities often discontinued from their studies and get involved in agricultural jobs and other local jobs for family needs. Currently Government is providing Rs.350/- per month for hostellers and Rs.150/- per month for Day Scholars. This should be doubled to meet the education needs of these students.
- **Women Empowerment -** The need of the hour is inclusive growth of the country and this has been achieved through the welfare of all the classes of

society irrespective of caste, communities and religion. Women empowerment and safety is utmost need of the hour and Government should promptly make efforts for women empowerment. As rightly said by Dr.Baba Saheb Ambedkar the growth of the nation is visible when women of this country were empowered. The atrocities against women, girl child and female foeticide are serious issues and challenges in front of this government. Government must have the vision and action plan to empower women but it is lacking.

I wish the Government will accept the need of the hour and delivers its best.

***श्री पी.पी. चौधरी (पाली) :** माननीया राष्ट्रपति जी का दिनांक 23.02.2015 को अभिभाषण हुआ, परम्परानुसार सबसे पहले अभिभाषण पर चर्चा होती है क्योंकि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण में सरकार के लिए एक वर्ष के एजेण्डे की घोषणा होती है, इसलिए यह अतिमहत्वपूर्ण है।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सभी प्रमुख विषयों का समावेश किया गया है चाहे वह देश की आंतरिक सुरक्षा का हो, विदेश नीति का हो, आधारभूत सुविधाओं का हो, चिकित्सा, शिक्षा, सड़कों, किसानों की समस्या, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, प्रधानमंत्री जन-धन योजना या स्वच्छ भारत अभियान का हो।

इसके अतिरिक्त इस अभिभाषण में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं को रोज़गार देने सम्बन्धी स्किल डेवलपमेंट योजना तथा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जैसी योजना के साथ-साथ नदियों को जोड़ने जैसी एन.डी.ए. की प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया गया है। नदियों को जोड़ने की योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बसी 70 प्रतिशत से अधिक जनता को पीने व सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था की जा सकेगी। पशुओं को चारे तथा पानी भी उपलब्ध होने से ग्रामीण क्षेत्र प्रगति को अग्रसर होगा। उजाड़ हो चुके गाँवों को नई दिशा मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।

हमारे प्रधानमंत्री देश को आयात वाले देश की श्रेणी से हटाकर निर्यात वाला देश बनाने पर बल दे रहा है, इसके लिए दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतगत 1254.73 लाख खाते खोले गए है, जिनमें 10,49962.62 लाख रूपये की धनराशि जमा है।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को सही ठहराया है। घरेलू वातावरण को विदेश के लिए और अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता के साथ-साथ सार्वजनिक निजी निवेश तथा घरेलू व विदेशी निवेश, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य दिलवाने पर भी जोर दिया है।

इन सभी योजनाओं के आधार पर देश उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा तथा अच्छी विकास दर की स्थिरता प्राप्त होगी।

---

* **Speech was laid on the Table**

SHRI H.D. DEVEGOWDA (HASSAN): Hon. Deputy-Speaker, I would like to express my sincere thanks for having allowed me to participate in the debate on the President"s Address.

16.09 hrs (Shri Ramen Deka *in the Chair*)

I watched the hon. Parliamentary Affairs Minister who spoke more than one hour. He has got every right to intervene at any time when the discussion is going on. His whole emphasis was only on the Land Acquisition Ordinance.

I was very carefully watching the proceedings because I was in my house. Some guests had come to my house. Your good self have also mentioned as to the number of Ordinances the Government have brought. I have never opposed the power of any Government to bring Ordinances. Yesterday when the issue was being raised, I kept enquiring because I did not want to cross my limits. The issue before us is that the people of this country have given the mandate. In the Presidential Address delivered in 2014, the hon. President had said that after 30 years, due to the mandate given by the people of this country, a stable Government under the leadership of the present Prime Minister has been formed. There is no dispute on that.

During the entire election campaign, the present Prime Minister went on saying that he is going to bring development, as this was his only agenda, and a corruption-free Government. I am not going to say anything about corruption in these nine months but with regard to development I would like to draw your kind attention to certain facts. I was in the 13 Party coalition Government supported by Congress for hardly ten-and-a-half months. Have we not given any developmental work? Vajpayee ji was also in the Government for six-and-a-half years. Has he not brought any development in this country?

Why people today have given mandate to the present Prime Minister is because a lot of publicity was given by the Media, both electronic as well as print media. I must thank the Media which has supported me. I was closely watching almost all the electronic, print and the social media. It is not that the UPA Government has not given any attention to the development. The same is true with Vajpayee ji. You yourself have titled him as the *Vikas Purush*. Sir, I have great respect for the work Vajpayee ji has

done during his tenure. He may be ill today but the country will remember him for what he has done for the country. My senior colleague is sitting here. I would like to ask him, who has cleared the Delhi Metro project. When I came here in 2002, as a result of a by-election, so much of debate was going on as to who should be invited to inaugurate the Delhi Metro; should it be Shri Madan Lal Khurana or Shri Sahib SinghVerma. The Delhi Metro project was pending for 20 long years.

The Lieutenant Governor, myself, the then Cabinet Secretary and the Secretary, Urban Development, took 15 days to find out how to fund this project. I have all the details. At that time, I had cleared the project with Japan's aid. I do not want to read all those things but I have got everything at my disposal.

About Kashmir, our hon. Prime Minister had gone and shown the green flag to the train from Baramullah to Katra. Who had cleared this project? Who had sanctioned this project? Shri Ram Vilas Paswan is not present here. He had gone and laid the foundation stone of this project. We treated it as a national project. I had cleared it and we had provided Rs.100 crore in the supplementary demands during the same year. Who had cleared the Uri Power Project? Whatever I speak, I speak with some responsibility.

Shrimati Maneka Gandhiji, if I tell anything wrong, please correct me. The Agriculture University for Jammu and Kashmir was also sanctioned by me. I went to Jammu and Kashmir five times. All the traders were crying because the tourism had totally collapsed. I had waived off all the loans. I met almost all the organisations including Hurriyat leaders. I tried to convince them for allowing a free and fair elections. Our neighbour, Pakistan, was making so much of adverse propaganda that India was violating the human rights. All this type of propaganda was going on.

When the late Shri Narasimha Raoji held the parliamentary elections in Jammu and Kashmir, there was not more than six per cent voting. But when we had conducted the elections, there was 54 per cent voting. We had allowed three Ambassadors of three different countries and foreign journalists to go and observe

whether there was a free and fair election or not. The National Conference headed by Shri Farooq Abdullah boycotted the elections. When the parliamentary elections were conducted, we contacted him, he was in London and asked him to come here. We assured him of full support. I am not going to comment on whosoever is going to form a Government in Jammu and Kashmir today.

We had not made any big publicity of what we had done. The Prime Minister alone toured the entire country only with the developmental agenda. He has announced certain programmes and I welcome them. He has launched Swachh Bharat on 2nd October and I also participated in that. But at the same time I am not going to elaborate what we have done in ten and a half months. I have taken decision for the poor to help through Public Distribution System based on Lakdawala Committee recommendations. Thirty-six crore people of this country were provided with 10 kilos of rice, 5 kilos of wheat and one litre of *mitti ka tail*. We did not distribute them on the basis of the *Aadhar* card. It was based on the Lakdawala Committee's Report. The late Madhu Dandavate was the Vice-Chairman of the Planning Commission. We discussed as to how best we could help the poor.

Who initiated the accelerated irrigation programme? On the basis of the recommendations of the Planning Commission, the previous regime dropped the idea of funding the irrigation projects. But we revived the project and decided to fund all the irrigation projects which were started from the Second Plan and not completed during the times of Pandit Jawaharlal Nehru. I can quote the names of the projects. We took a decision to fund all those projects, the small and medium and major irrigation projects to complete them. We did not keep quiet. Who had cleared those projects? On the Tehri Dam, Sundarlal Bahuguna was on hunger strike. I solved the problem In those 10 months I worked 20 hours a day. Some people said that Devegowda was a sleeping Prime Minister. I am aware of such adverse publicities. Do not mistake me. It is not a question of laughing. Sitting in that Office I knew as to when my Government is going to collapse. I accepted that

responsibility with so much of pleasure. I never bothered to come to Delhi. I have spent my whole life in Karnataka. I spent 30 years in the State Legislature. The circumstances after the 13 days of the Vajpayee Government, when he failed to get the support of sufficient number of MPs were such that the leaders of 13 parties offered me this post. I never wanted to come here, but accepted the responsibility.

Sir, having accepted the responsibility, what did I do for my country? We have done our bit. I can quote several things. For example, take the case of the North-Eastern States. Who visited the North-Eastern States? I visited the North-Eastern States continuously for seven days with my officers. I ultimately decided to give a sum of Rs. 6100 crore as a package. I am speaking with responsibility. I announced the package in Guwahati on the last day after my visit to the States was over. What are all the schemes that we announced. We announced airports, highways, power generation projects. I have got the list. I can go on reading it. I also instructed that an Army helicopter at Gawhati to carrying three Departmental officers should visit the North-Eastern States once in a month and they should inspect and a progress report should be submitted to the PMO. There was a cell in the PMO for this purpose. Let the things be examined. I visited all the seven States of the North-East. I also announced a package of Rs. 6100 crore at that time. A further sum of Rs. 600 crore was allocated by Shri Vajpayee during his time of 13 months. Coalition Government has not done anything with regard to development? Only a new slogan has been coined by our Prime Minister and people are watching now.

I am not going to quote the election results of Delhi. It is not an issue. In public life, I have seen ups and downs. I have contested 15 elections and I was defeated in two elections. I may have two Members from my party. I brought 16 Members to this House as Chief Minister of Karnataka. I have told the hon. Prime Minister that I am not going to contest elections anymore. But at the same time, I have personally requested him to see that projects are completed. Some of the

projects which have been sanctioned in 1996-97 have still not been completed. At various stages, they are delayed. That was my request to the hon. Prime Minister. His Mantra for Development should be implemented. I met him and told that I am not going to contest elections any more but to please see that some projects which I have cleared should be completed during his tenure of five years. It is a stable Government. I am not going to think in an adverse way. Where is the need for it? The whole country has given you the mandate. Your party has got about 282 seats or something like that. Such a kind of majority is there. There is no question of anybody expecting that it is not a stable Government and that something will happen to this Government. If anybody thinks like this, they will be in a fool's paradise. So, please see that the Development Mantra is implemented.

As far as land acquisition is concerned, Sir, I will speak elaborately on how things have happened and I can quote any number of instances. It is not so simple to accept the Ordinances which have been issued. Why did Shri Rahul Gandhi take so much interest to bring the amendment to what has been enacted during the British period? Credit goes to him. I was watching here as to what he did. There is no question of praising him. Support to my coalition Government was withdrawn and we demitted office. But more protection was given to the farmers under the Land Acquisition (Amendment) Bill and I do agree to this point.

So far as industries are concerned, he said about irrigation and housing. It is not the question of irrigation or housing. What is the alternative for the person who loses the land? What alternative are you going to give him? It should not be mere compensation. He may lose the compensation by various means of expenditure. Generation to generation has been depending only on agriculture. More than 65 per cent of the work force is living only by agriculture. With the manufacturing sector, industrial sector and service sector put together, we are unable to give 36 per cent or 34 per cent of the work force. What type of jobs are given? It is called outsourcing. The offer is about Rs. 6000 or Rs. 8000. Those are

the kind of jobs which you have created. You have built five star hotels at 6 per cent or 5 per cent interest.

Now, in Karnataka, we have thought of bringing down the rate of interest to the farmers and it has started. I know how the UPA-I Government changed it. I was watching it. They reduced it to seven per cent. With timely repayment, another two per cent exemption was given. That is how things were started.

Sir, I will conclude shortly. I am not going to say anything more about land acquisition. Land acquisition is a very important issue. It cannot be hushed through. I know in the very same House, about 17 Bills were passed in a matter of half an hour. It happened during the UPA period as well as during the NDA period. But in the case of Land Acquisition Bill we may go to any extent to have a threadbare discussion. We want to expose how in the name of development looting is going on in this country. The C&AG has given the Report. What has he said? We cannot accept these things when it comes to our farmers. I have been fighting for the cause of farmers throughout my life. I brought 2,500 farmers in train to meet Vajpayee ji. I am not going to elaborate on these issues. Let that Bill be discussed threadbare. Of course, we have to allot land for development.

What has happened in Vibrant Gujarat? Three corporate houses have come forward to invest. One corporate house said it will invest Rs. 1 lakh crore in five years; the other corporate house said it will invest Rs. 50,000 crore; and the third one said it will invest Rs. 10,000 crore. Around 230 MoUs were signed in Gujarat. Various countries participated in that. But what is the further progress?

You want to build smart cities. What is the concept of smart cities? How much land do they require? You have come out with a scheme, Aadarsh Gram Yojna, according to which each Member will be allowed to choose a village. But where is the fund? We have to meet the expenditure from MPLADS. Where is the fund? I do not know from where our colleagues from BJP are going to get the money. There are eight Assembly constituencies. If we select one village out of

these constituencies, how can we fund that? They may not be able to discuss this issue in the Parliament. At least in the party meetings they can discuss that.

Generally in the insurance scheme, once a person insures his life, if he dies even after six months, he will get the amount for which he is insured. In Jan Dhan Yojna, one must have regular transactions in the first six months. If one is a taxi driver, if he deposits money, only after six months he will be allowed to draw Rs. 5,000 for various other activities, and at premature death, he will get one lakh.

HON. CHAIRPERSON : Sir, please conclude.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I have studied these things. There is a scheme for transferring the money directly to the account of beneficiaries. In how many States has this money been transferred? In my home State, where we review the progress of the use of all the grants sent by the Union Government, like MPLADS, I came to know that this money has not been transferred yet.

I know the position. I know on what basis time is allotted to Members to speak. It is only on the basis of the numerical strength of the political parties that they are given time. The only privilege that I have is sitting in the front row. That is the only privilege that Shri Mulayam Singh Yadav and I have. I am not bothered about this front bench or back bench. I am not playing any politics. I have never asked for this. In 1991, I was alone. But I was allowed to speak for hours together on the issue of agriculture. Shri Shivraj Patil was the Speaker.

Shri Shivraj Patil was the Speaker at that time. From my party only one Member from Karnataka. Sir, the question of restriction of time is something important. Whenever you feel, you call us on the basis of the numerical strength. We are only two Members in this House.

HON. CHAIRPERSON : You are a senior Member. You know it.

SHRI H.D. DEVEGOWDA: I have only two Members. So, what can I do? It is the people who have sent me here. If I have not been allowed to speak, it is better that I should resign. I have not come here for getting Rs.2000 D.A. I must be frank enough with you.

On the Land Acquisition Bill, let the Government convince us. Whether to support it or not, we will think over the matter. The same Shri Rajnath Singh, who is the hon. Home Minister now, and Shri Arun Jaitley went to the Yamuna Express Way. They sat on a *Dharna*. Sitting here, they were speaking volumes after volumes on the basis after Dharna about the conditions of the farmers. Shri Rahul Gandhi also participated in it. He realized the truth and took a strong decision in the Party. A Bill was introduced and it was passed to protect the farmers. If you want to make some change, please convince us first and then we will apply our mind whether to cooperate or not.

With these words, I conclude. Thank you very much.

***श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर) :** महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुल 74 पैरा हैं। समय को देखते हुए यहाँ संभव नहीं है कि सारे बिंदुओं पर चर्चा की जाए, इसलिए केवल कुछ बिन्दुओं पर ही मैं अपनी बात रखूंगा। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी सरकार ने केवल कुछ महीनों के कार्यकाल में ही हर क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास का कार्य किया है।

हमारी सरकार की मूल नीति है सबका साथ-सबका विकास। नौ महीने के कार्यकाल में हमारी सरकार ने कई क्षेत्रों में कार्रवाई तेज करने के उपाय किए हैं जैसे स्वच्छता से लेकर स्माट शहर बनाना, गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त करना, व्यवसाय को आसान बनाने से लेकर नीतिगत ढांचा तैयार करना, लोगों को सशक्त बनाने से लेकर उत्तम बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना, वित्तीय असमानता को दूर करने से लेकर देश को निर्माण का केंद्र बनाना, मुद्रास्फीति को रोकने से लेकर अर्थव्यवस्था को उन्नत करना, नए विचारों को बढ़ावा देने से लेकर समावेशी विकास सुनिश्चित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने से लेकर राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। जैसा कि महामहिम ने कहा कि एक अच्छी शुरूआत हो चुकी है। उज्जवल भविष्य हमारी राह देख रहा है।

हमारी सरकार ने सभी लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए महत्वकांक्षी प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू की है यह अभूतपूर्व लक्ष्य छह महीने से भी कम समय में पूरा कर लिया गया, जिससे यह कार्यक्रम विश्व का इस प्रकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम बन गया।

माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया है। सरकार ने स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है और यह 15 अगस्त, 2015 से पहले हर स्कूल में एक शौचालय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं अपने क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि का अधिक से अधिक हिस्सा स्वच्छ भारत मिशन पर खर्च करूँगा।

जैसाकि महामहिम ने कहा कि भारत गांवों में बसता है। हमारी सरकार की प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रों के सतत् सामाजिक, आर्थिक विकास को सर्वोच्च करना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में पटमदा प्रखंड के अधीन बंगुर्दा ग्राम को गोद लिया है तथा अब तक कई कार्यक्रमों की शुरूआत भी की जा चुकी है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए चलाई जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं को सरल बनाने पर विशेष ज़ोर दिया गया है ताकि लाभार्थियों को

---

* **Speech was laid on the Table**

समय से भुगतान मिल सके। सरकार मेक इन इंडिया पहल के तहत जहाज के डिज़ाइन करने की क्षमता, जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत कार्यों को सुदृढ़ करेगी। शिशु लिंगानुपात में कई दशकों से निरंतर कमी से चिंतित सरकार ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं अभियान जैसी शुरूआत की है जो लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए है जिससे वे बेटियों के जन्म पर खुश हों।

अल्पसंख्यकों में परंपरागत कलाशिल्प के क्षेत्र में कौशल और प्रशिक्षण को उन्नत बनाने के लिए उस्ताद नामक एक नयी योजना शुरू की जा रही है।

प्रत्येक गांव की सिंचाई आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से निरंतर पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की जा रही है।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Discussion on the Motion of Thanks on the President's Address.

First of all, I sincerely thank the hon. President of India for delivering an inspiring and realistic speech in this august House.

The most encouraging factor of Shri Modi's Government is that there is the GDP growth rate of 7.4 per cent. Industrial growth rate is also equally encouraging.

I thank the Union Government for appreciating the high state of disaster preparedness of our Chief Minister of Andhra Pradesh Shri Chandrababu Naidu during the recent Hudhud cyclone. Our Chief Minister camped in Vizag and showed his high state of disaster preparedness to the country. Our Chief Minister has a great track record in disaster management. He best utilized the technology including the social media. Because of our Chief Minister's foresighted approach, the loss of life is very minimal and Vizag has come to normalcy within days. Vizag is famous for its greenery. The greenery of Vizag vanished due to cyclone. Shri Modi ji personally visited the city touched by the impact of cyclone and instantly announced to release Rs.1000 crore. But, unfortunately, only Rs. 400 crore was released till today. I would request the hon. Prime Minister to arrange to release the balance amount immediately.

The cyclone had an effect of the last straw on the camel's back, that is, the State has just been bifurcated and there are insufficient finances.

Sir, due to the unscientific bifurcation, our Andhra Pradesh State is facing great hardships. The revenue loss is alarmingly growing. We are running the administration from another State. I would request the Union Government to fulfill all the promises made during the time of bifurcation. I would request you to grant the Special Status to Andhra Pradesh as promised and assured in the Andhra Pradesh Reorganisation Act. The Assured Special Status will enable us to develop

industrially the backward districts of our Andhra Pradesh. It is the need of the hour of our State.

I congratulate the federal spirit of the hon. Prime Minister who has taken a dynamic and bold decision by increasing the States' share from 32 per cent to 42 per cent as per the spirit of cooperative federalism.

Coming to our State, we have a revenue deficit of Rs.9000 crore. It may touch Rs.15,000 crore by the end of the current financial year, according to a forecast. Andhra Pradesh is in great financial crunch now. The Fourteenth Finance Commission suggested a financial assistance to the tune of Rs.1,94,821 crore to 11 States, including Andhra Pradesh, which have revenue deficit. Andhra Pradesh will receive a financial assistance of Rs.22,113 crore over a period of five years - from 2015 to 2020.

I thank the hon. Prime Minister for extending a small solace to the people of Andhra Pradesh but the peculiar situation of our State is that after getting the financial assistance also, Andhra Pradesh will remain in the revenue deficit States. As far as other States like Odisha, Bihar, Rajasthan, which are demanding Special Status on par with Andhra Pradesh are concerned, they are not resource deficit States. This is the post-bifurcation effect exclusively for Andhra Pradesh. Hence, I appeal to the Union Government to extend Special Status to Andhra Pradesh immediately. The then Prime Minister of India assured Special Status to Andhra Pradesh on the floor of the House. It is justifiable to honour the assurance of the then Prime Minister for the benefit of the people of residuary Andhra Pradesh.

Sir, everybody knows that when an industry is set up, returns cannot be expected immediately. It may take four to five years. If you give Special Status to Andhra Pradesh now, it may take four to five years to reap the fruits. When there is a rail, railways station, railway line, it is easy for a passenger to get a seat in the rail and perform journey. Please imagine the position of a passenger opting to travel in a rail where there is no rail, railway station and railway line. Our State's position is exactly like this. We have neither capital nor infrastructure now. Do not

compare our State with any other State. We are now in shambles after the bifurcation stage. Therefore, I would like to humbly request the Union Government to grant Special Status to our State immediately as assured by the Government. This will help Andhra Pradesh to prosper and to stand on its own legs in the days to come and to fulfil its promises made to Andhra Pradesh electorate jointly with the Bharatiya Janata Party at the time of elections.

Even for construction of a new capital, we need nearly Rs. 4 lakh crore. Sir, Rs.1 lakh crore may be adjusted from the Centre towards Capital. Hon. Prime Minister himself assured the people of Andhra Pradesh to extend a helping hand for construction of new Capital which would be better than Delhi during his election campaign. I would like to sincerely request the hon. Prime Minister to stand by his word.

I would like to request the Union Government to fulfil the assurances made to Andhra Pradesh State on pending Railway projects, and in establishing a new Railway Zone at Vishakapatnam, and also to establish medical and educational institutions, and to extend industrial incentives, special development packages, capital establishments, and industrial corridor in Andhra Pradesh.

Coming to Government's priorities, *Swachh Bharat* is an innovative programme of this Government. Gandhiji's 150th birth anniversary would be celebrated in October, 2019. By that time, we want to achieve Clean and Open Defecation Free India. Under *Swachh Vidyalaya* programme, construction of a toilet in every school before 15th August, 2015 is being taken up. Inspired by our Prime Minister's programme, I immediately convened a meeting in my district, and have taken steps to construct toilets in the schools of my constituency. I am confident that they will be completed before 15th August.

Another good initiative I have taken is, introducing sanitary napkins for the school-going girls. I introduced this for the first time in our entire State. This has become a great success in our area. Attendance of school-going girls have increased remarkably. I would like to request the hon. Prime Minister to give his

voice to this sanitary napkins programme so that wide publicity would be received which in turn benefit the school-going girls.

I would like to congratulate the Government on introducing the *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana,* a financial inclusion scheme which helps eradication of poverty. Integrated and holistic development of our villages, with active involvement of Members of Parliament through Skill India, Deen Dayal Upadhyaya *Grameen Kaushal Yojana,* and Deen Dayal Upadhyaya *Antodaya Yojana* and *Sansad Adarsh Gram Yojana,* are sought to be taken up. They can be used as an instrument for encouraging people's participation as well as decentralized policy making at the village level.

Marking 75 years of our Independence, Housing for All by 2022 is a laudable scheme. It aims at creating dwelling units to the poorest of the poor. It is a welcome step in the right direction.

The fruits of our development have not yet reached the poorest of the poor. This can be achieved through inclusive growth. Mere giving of scholarships and setting up a new Venture Capital Fund for SC entrepreneurs cannot serve the purpose. These downtrodden people of the society have to be brought to the main line through inclusive growth. Voluntary organizations have to be necessarily involved in this task.

Education should be the topmost priority for any Government. Luckily, we have a very good and a pro-active HRD Minister. In my view, mere westernization of education is not suitable for India. I personally feel that value based education, values coming through our glorious past, is the need of the hour. When the foundation is strong, building sustains for a longer period. *Padhe Bharat, Badhe Bharat* is concentrating on foundation level education and it is a welcome programme.

Women empowerment and protection of their dignity is always a subject matter for discussion. One Stop Crisis Centres, one in every State, is a good sign.

To ensure survival, protection and education of the girl child, newly launched programme *Beti Bacho, Beti Padhao Abhiyan* is a good programme.

India has the largest population of youth in the world. A majority of our population is already in the working age group. To tap this, the Government created a new Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. I congratulate the Government for their vision.

I appeal to the Government to take all possible measures to stop generation of black money. The main hurdle for India's development is corruption and red tapism. Stern measures have to be introduced to deal with corruption. Due to corruption and red tapism, qualified youth of India are flying to USA, England and other countries and developing those foreign countries. Even though they have love and affection towards their mother land, they have become helpless to develop their mother land. I observed that Modiji tried to correct this. When he went to USA and also to Australia, the venues where he addressed the gathering were highly thronged by NRIs in those countries. Modiji has given his best appealing speeches. Honestly speaking, I am totally impressed and moved by those two speeches which he has delivered in USA as well as in Australia. I am highly confident that our Prime Minister will best utilize the services of those NRIs for building a vibrant India.

Modiji's foreign policy is highly applauded. Wherever he went, he left an indelible Indian impression. He has taken our country's image to Himalayan heights. I sincerely congratulate our hon. Prime Minister for his mark in Indian foreign policy. I believe that Modiji will get a place for India in the United Nations Security Council. 21st June is declared as the 'International Yoga Day', exactly within 75 days of Prime Minister's call at the United Nations General Assembly. It is a historic decision and I wholeheartedly congratulate our Prime Minister for his gesture.

Digital India, an innovative use of technology, can make enormous difference. I congratulate the Government for preparing India for technology based transformation.

Planning Commission has been replaced with a new body, NITI Ayog. The spirit of cooperative federalism is good. Federalism is the base for any Parliamentary Democracy. States' interests have to be protected.

'Make in India' programme aims to transform India into a manufacturing hub. If it is successful, job opportunities will grow and employment can be generated.Building modern amenities and infrastructure in our urban areas through the National Urban Development Mission and also Smart City Programme are really very good programmes. I request the Union Government to be liberal towards our Andhra Pradesh in these two programmes.

Recently, power sector has made commendable progress achieving 76 per cent capacity addition by January, 2015. Our Government of Andhra Pradesh is concentrating on uninterrupted power supply, 24 hours power supply. I request the Union Government to extend its helping hand.

I request the Government to exercise due consultation while interlinking rivers. We have perennial rivers like Godavari and Krishna. Interlinking of these two rivers will yield good results for Andhra Pradesh. I request the Government to take steps in this direction.

On 24th September, 2014, Mangalyaan was successfully placed in the Mars orbit, making India the first country to do so in the first attempt. I congratulate the scientists, the Government for making Mangalyaan a great success.

Thank you very much, Sir, for giving me this opportunity.

*श्री राहुल कस्वां (चुरू) : एक भारत-श्रेष्ठ भारत व सबका साथ-सबका विकास की भावना लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के पिछले 9 महीने के सफलतम कार्यकाल में बहुत सी जनोपयोगी योजनाओं का आगाज़ हुआ। प्रधानमंत्री जन-धन योजना, स्वच्छ भारत, पहल, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, पढ़े भारत-बढ़े भारत व बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान वे मुख्य योजनाएं हैं जिनका जमीनी स्तर पर बहुत ही बड़ा योगदान हुआ हैं।

सबका साथ-सबका विकास की बात करते हुए जैसा माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा कि हमारी सरकार का मुख्य ध्येय हैं कि किस प्रकार योजनाओं का क्रियान्वयन हो जिससे देश की पूरी उत्पादकता को प्रयोग करते हुए देश के 125 करोड़ लोगों को फायदा मिले। हमारी सरकार देश के चहुंमुखी विकास के लिए हर क्षेत्र के लिए प्रभावी योजनाएं बना रही हैं और जिनका प्रमाण भी सामने दिखने लगा है।

ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जिस योजना का आगाज़ 24 सितम्बर, 2014 को किया गया और मिशन रखा गया कि 25 जनवरी, 2015 तक देश में 7.5 करोड़ बैंक खाते खोले जाएंगे लेकिन सभी को पीछे छोड़ते हुए अभी तक देश में 13.2 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं और साथ ही इन खातों में 11000 करोड़ रूपये जमा भी हुए है और इससे देश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हुआ है, जोकि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है।

पहल योजना का शुभारम्भ करते हुए भारत सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि हर व्यक्ति को सरकार से मिलने वाला उसका हक पूरी तरह से मिले। इसकी शुरूआत भारत सरकार ने एल.पी.जी. की सब्सिडी देने के साथ कर दी है और भारत के 75% जनसंख्या अभी तक इससे जुड़ भी चुकी है। आगे भारत सरकार ने सभी 35 योजनाओं को इससे जोड़ने की ओर अग्रसर हैं और साथ ही आधार को भी जरूरी करने से देश की जनता को बहुत ही फायदा मिलेगा।

इस वर्ष गांधी जयंती के उपलक्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत करते हुए एक नयी क्रांति को जन्म दिया है। भारत की मान्यता हैं स्वच्छता में ही समृद्धि का वास होता है और इस अभियान के अंतर्गत भारत सरकार ने अभी तक 7,00,000 शौचालयों का निर्माण कर एक नया इतिहास लिखा है और मुझे यकीं है कि आम जन के सहयोग से 2019 तक भारत पूरी तरह से कचरा मुक्त हो जाएगा। अगर इस तरफ हम गौर करे तो मेरा संसदीय क्षेत्र चुरू भारत का पहला 100% घरेलू शौचालय वाला जिला बनने की ओर अग्रसर है।

---

* **Speech was laid on the Table**

"हुनर है तो कल्याण है" इसी से प्रेरित होकर भारत सरकार ने स्किल डेवलपमेंट की उपयोगिता को महसूस किया और भारत के हर नौजवान को हुनरमंद बनाने के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरूआत की। आज से पहले जो भी योजनाएं चलाई गई उनमे युवाओं को सिर्फ प्रशिक्षित किया जाता रहा है लेकिन इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित होने वाले युवाओं को रोज़गार भी दिलाया जाएगा। इस प्रकार हुनर के साथ-साथ रोज़गार और समृद्धि दोनों साथ आएंगी।

भूमि अधिग्रहण कानून के द्वारा भारत सरकार ये सुनिश्चित करने जा रही है कि देश का हर किसान खुशहाल एवं समृद्ध हो। इसके लिए भारत सरकार हर प्रयास कर रही है। किसान इस देश का अन्नदाता है। भारत की 60% जनसंख्या कृषि से होने वाली आय से ही जीवनयापन करती है तब ये कैसे हो सकता है कि भारत सरकार देश के किसानों के साथ अन्याय होने देगी। भूमि अधिग्रहण में पूरी पारदर्शिता, किसानों के पुनर्वास एवं उनके रोज़गार की व्यवस्था के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

कृषि भारत की जीवन रेखा है और इस क्षेत्र को बढ़ावा देना भारत सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। जिसके लिए भारत सरकार कृषि में टेक्नोलॉजी का समायोजन कर खेतों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। इस बार भारत सरकार ऐसे स्थानों को चिन्हित कर रही है जहां खेती करना मुश्किल होता है एवं इस ओर प्रभावी कदम उठा रही है कि किस प्रकार ऐसे स्थानों पर भी खेती की जाए। भारत में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अलग से मंत्रालय का गठन किया है और पिछले नौ महीने में भारत में 72 फूड पार्क व 2 मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है जिसमें खेती से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक खेती के उत्पाद को पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ रूपए का प्रयोजन अलग से किया है।

ऊर्जा क्षेत्र में भारत ने बहुत ही शानदार तरक्की की है। दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामों पर खासतौर से ध्यान दिया जा रहा है जहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। इसके लिए भारत सरकार ने लगभग 75,000 करोड़ रूपये की नयी योजनाएं शुरू की हैं। भारत में क्लीन एनर्जी-ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है जिसके तहत 200,000 मेगावाट बिजली सौर, जल, वायु एवं अन्य साधनों से प्राप्त की जाएगा। इसी के साथ-साथ भारत सरकार से होने वाले बिजली उत्पादन की तकनीक व सुरक्षा मानकों को भी उच्च स्तर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक ले जाने की ओर प्रयासरत हैं।

इस प्रकार अनेक ऐसी योजनाओं का रोडमेप तैयार किया जा रहा है, जिनसे भारत प्रगति पथ पर बढ़ेगा। स्किल डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सभी के लिए बन रही योजनाओं से निश्चित ही भारत की जनता को सहयोग और समृद्धि मिलेगी।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Hon. Chairperson, Sir, first of all, let me thank you for giving me this opportunity to speak about the President's Address on behalf of my party, the Telangana Rashtra Samithi.

Sir, we would have been happy if His Excellency, the President had mentioned a special status to our brotherly State Andhra Pradesh and the same to Telangana State. The new Government has made a step in the right direction by taking several positive decisions. As per the President's speech, almost 58 crucial issues have been mentioned. Let me begin by mentioning a few points and its significance for our new State of Telangana.

The President's speech has mentioned that the Government attaches enormous importance to the well-being of farmers and I quote:

> "This will need value-added agriculture, market reform, use of technology and improving productivity in areas with untapped potential. The year 2015 has been designated as International Year of Soils. In view of the critical role of soil for productivity and farm output, a Soil Health Card Scheme has been launched."

I would like to bring to the notice of the Members of the House, through you, Sir, that our hon. Chief Minister of Telangana Shri KCR *garu*, recognizing the importance of agricultural inputs for farmers, has come out with a new scheme to complement the efforts of the Central Government. With an objective to turn the newly formed Telangana State into a seed bowl of the country, the State Government led by Chief Minister K. Chandrasekhar Rao has decided to launch an innovative scheme. The scheme will be called 'Seed Bowl of Telangana'. The main objective of the scheme is to transform Telangana into a seed production capital of the country by augmenting its production capacities and creating basic infrastructure for the purpose. Detailed estimates have been prepared and an allocation of Rs. 50 crore has been earmarked for the purpose. The Government aims to transform the State into a seed capital in the next five years. On behalf of

the State Government, through you, Sir, I would like to seek the support of the Central Government in this venture.

The launch of the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana is especially laudable and special efforts should be taken to strengthen the impetus for farming. In this regard, due to the far-sighted and visionary leadership of our Chief Minister, hon. K. Chandrasekhar Rao *garu*, the State of Telangana has come with an innovative scheme namely 'Mission Kakatiya', which is to interlink all the water bodies in the entire State. The Union Government is planning to interlink the rivers across the nation. But the objective of the State of Telangana is to interlink all the traditional water lakes. For this Scheme, the State Government has estimated the needs of about Rs. 25,000 crore. Since the objective of State and Central Government is almost similar, I strongly believe that there should be cooperation and encouragement from the Centre. Right from the Kakatiya Dynasty to the recent Nizam's rule, the irrigation facilities were intact. It was just because water is the lifeline of human civilization. Unfortunately, a lot of injustice was done to the Telangana region under the United Andhra Pradesh dispensation. Hence, the State Government chalked out to bring back the golden period to rural population by interlinking all the water lakes to have year-long irrigation facilities to all cultivated land. I would like to take this opportunity once again, Sir, though you, to request the Central Government to extend all possible financial help to the State of Telangana on this mission.

Likewise, there is another Scheme namely 'Water Grid', which was aimed by Telangana Government to provide potable drinking water to every household through pipeline. Of course, such programme is in process of implementation in the hon. Prime Minister's home State of Gujarat. The Union Government is implementing such Scheme with the name of National Rural Drinking Water Mission, which is almost similar to 'Water Grid' project of Telangana. It is estimated that the cost of 'Water Grid' Scheme is about Rs. 42,000 crore, in which the share of rural areas is about Rs. 29,000 crore. It is noted that about 80 per cent

of diseases are connected with the polluted water. The Central Government may be aware that the problem of fluoride in water is very severe in Nalgonda and Mahabubnagar Districts of Telangana and it is an acutely justified objective to provide safe drinking water to every household. By making this project successful in the coming years, we can see enormous changes in the livelihood of rural people as well as decline in their medical expenditure.

The President's Speech also mentioned and I quote: "Power sector has made commendable progress, achieving 76 per cent capacity addition by the end of January, 2015, against the target of 17,830 MW". He also said: "In order to provide 24X7 quality power in rural and urban areas, the Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana with an outlay of more than Rs. 43,000 crore and the Integrated Power Development Scheme with an outlay of more than Rs. 32,600 crore have been launched. Special attention is being paid to the un-electrified villages in remote areas. The Government has started major projects for improving transmission and distribution system in the North-Eastern States. We will focus on developing and strengthening the National Grid by developing high capacity power corridors."

I would like to convey the concerns of the State Government of Telangana. For instances, our State is struggling a lot in providing electricity to important sectors like agriculture and industry due to shortage. Though the Central Government had assured to allocate, at least, 500 MW from its unallocated pool to our State, it did not happen because of lack of transmission Grid connectivity. Without completing the Grid connectivity, it is impossible to provide power to every household in our country. Even though there is unallocated power at the Centre, there is no possibility to supply it to the Southern States. It is the need of the hour to make Grid connectivity across the nation at the earliest. Our Party would like to impress upon the Central Government that concrete measures must be taken to ensure the speedy completion of the National Grid Connectivity in a phased and time-bound manner.

Another important issue is housing for all. Our Party appreciates the Government's commitment towards affordable housing for all. In this regard, I would like to proudly mention that the Telangana Government had announced a Scheme similar to this much before the Union Government.

17.00 hrs.

Our Chief Minister Shri K. Chandrasekhar Rao had assured the homeless people in our State to build a double bedroom house with an estimated cost of around Rs.4 lakh in rural and urban areas. With a specific vision, KCR had promised this scheme right in election manifesto and realized it after becoming Chief Minister. Already process has been initiated to identify the beneficiaries. I would request the Central Government, through you, Sir, to provide the flexibility to our State in terms of funding from the Central pool for this housing scheme also.

Another important issue that our Party would like to flag, with regard to eradication of poverty, is the arbitrary decision to limit the MGNREGS in our State. Sir, MGNREGS is being implemented in 8,880 Gram Panchayats in 443 rural Mandals (Taluks) in State, and there are about 55 lakh job cards covering 1.32 crore wage seekers.

17.01 hrs (Hon. Deputy-Speaker *in the Chair*)

Every year, on an average 12 crore pension days are generated under this scheme out of which 45 per cent is under wage seekers from SC and ST category and 50 per cent is under BC category resulting significant positive impact in their socio economic status. If the Government of India restricts the implementation of MGNREGS to only 78 Mandals (Blocks), the State of Telangana, which was newly formed, will suffer a lot, as the vulnerable and backward population of the other parts deprived the benefits of the scheme, and their livelihoods would be adversely affected, and by doing such changes to this scheme, this would defeat the spirit and objectives of this scheme.

Sir, the Central Government has itself recognized eight of the total 10 districts of the State of Telangana are backward in development, and the ground reality is that almost 75 per cent of agricultural labourers are depending on MGNREGS works. Since the irrigated water facilities are very low in our State and most of the farmers are dependent on bore wells for which power is essential, most of the agricultural labourers are the beneficiaries of MGNREGS works. Unfortunately, the Union Government has chosen only three districts to release BRGF funds for the development of backward districts which has come as a double shock to the people of Telangana. Of course, the President's speech categorically said that 'India lives in villages and the Government's highest priority is to sustainable socio-economic growth of rural areas. MGNREGS can be a powerful weapon to combat rural poverty'. It also said that 'at least 60 per cent of expenditure be directed for creation of agricultural infrastructure'. If the Union Government is committed to do this, there should not be restrictions on the implementation of this scheme limiting to only 78 Blocks in our State.

The present Government has promised to empower the States and strengthen the federal structure of the country. Our Party, TRS, has always stood for strengthening the federal structure of the country. We have always championed the cause of empowering the States. We are pleased to note that this Government intends to strengthen the federal structure of the country. The President has rightly outlined it in his speech that States must be accorded their due. Funds must be provided to the States. State Governments must be consulted in matters that pertain to the States. Sir, this intention has to be implemented not only through words but also through deeds. Schemes should be implemented with due planning and States should be consulted. Only then can the States flourish. Prosperous States will lead to a prosperous India. States must be empowered and given their due.

The Central Government's initiative to empower and strengthen the dignity of women by various means is a laudable move. The launching of HIMMAT, a

mobile-based application to ensure the safety of women in Delhi city is one of such attempts. The Telangana Government has also launched a scheme 'SHE', to ensure the safety and security of women in Hyderabad city. A few women special police teams have been formed to provide assistance to women in emergency times.

Sir, our party welcomes the steps taken by the Central Government to bring down the corruption levels. The Telangana Chief Minister is also very serious in fighting corruption at all levels and has established a 24x7 helpline to lodge complaints from the citizens.

Sir, the hon. President had stated that the Government will develop 100 smart cities of the country and upgrade them to world-class cities. Our party welcomes this step and would like to appeal to the Central Government to give special consideration to our new State of Telangana.

Sir, our party wholeheartedly welcomes the thrust of the Central Government for the 'Make in India' programme, which aims to create a wholesome eco-system to transform India into a manufacturing hub. This particularly resonates with the focus of our hon. Chief Minister, who is spearheading a similar initiative. In Telangana, the State Government has attempted something similar with the "In Telangana -- Innovate, Incubate, Incorporate" campaign.

The State Government passed the 'Telangana State Industrial Project Approval and Self Certificate System' known a TS-iPASS, which is meant to speed up processing of the business registration process. It replaces the existing Industrial Single Window Clearance Act of 2002 and make Telangana appear more investor-friendly. Telangana Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao described the old law as 'a single window with grills' and the new Bill as 'a single window without grills'. Our party looks forward to working closely with the Centre in achieving this objective, and we look forward to the times when the brand of 'Made in India' is enhanced and it replaces the 'Made in China' brand.

Sir, our party also welcomes the transformation of the Planning Commission to the NITI Aayog. This is an important attempt in the decentralisation of power, and our party sincerely wishes that the NITI Aayog will play a dominant role in fostering the underlying spirit of the Cooperative Federalism so that the Union and the State Governments come on a platform to forge a common national agenda for development with thrust on empowering the impoverished.

Sir, I would like to just say one thing about the Swachh Bharat. स्वच्छ भारत का जिस तरीके से प्रधान मंत्री जी ने ऐलान किया और उन्होंने झाड़ू पकड़ी, पूरे देश के गांव-गांव के अंदर बच्चों ने तभी सभी जनों ने झाड़ू पकड़ी। Everybody is ready to do Swachh Bharat and everybody is ready to clean India. What I am saying is that all of us, all politicians are together. When the Prime Minister said 'Team India', 29 Chief Ministers also came and joined him. We all politicians are ready for 'Make in India'; we are all ready for 'Team India' and we are ready for the NITI Aayog. I hope that India will really survive. But the only thing I want to add is that the Prime Minister should see that we politicians have already started and we have already fallen into line. But have the bureaucrats fallen into line? Unless the bureaucracy starts and they start implementing these works at the village level and at the country level, nothing will move. Practically, you know that. So, I would request you in this regard. On behalf of our party, I would like to appreciate the initiative taken on various schemes and efforts of the Central Government, and would request the Central Government to take the States into confidence in launching new schemes so that the country can progress together in harmony.

Thank you very much.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have to get the support of all the bureaucrats from the State Government because your Party is ruling. Therefore, you are going to implement it

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : We are already implementing it.

HON. DEPUTY SPEAKER: If you want the support of the bureaucrats, first you have to get the support of the State bureaucrats because most of the schemes are implemented by the State Governments.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Yes, Sir.

HON. DEPUTY SPEAKER: Therefore, if the bureaucracy in the States is not helping, it is not successful.

SHRI A.P. JITHENDER REDDY: Sir, now that all the money and everything is coming down here, we want everybody to be on the line. We have already fallen into the line. All the politicians have fallen into the line.

HON. DEPUTY SPEAKER: All right.

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद ज्ञापन पर चर्चा हो रही है। कल सरकारी पक्ष से अनुराग ठाकुर जी और निशिकांत दुबे जी ने जिस प्रस्ताव का यहां पर उद्यापन किया और समर्थन किया, उस पर चर्चा चल रही थी। लेकिन आज हमें अफसोस है कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जो एक वरिष्ठ नेता भी हैं, शासक दल के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्री की यह जिम्मेदारी है कि पूरे सदन को इकट्ठा करें ताकि हम महामहिम जी को धन्यवाद ज्ञापन कर सकें। जो लांछन, जो गलत बयान विरोधी पक्ष के लिए हुआ, मैं ऑन रिकॉर्ड्स उसका प्रतिवाद कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ, और फिर अपना भाषण कर रहा हूँ, वर्ना हम तो इसे पूरा बायकॉट ही कर देते।

SHRI GOPAL SHETTY (MUMBAI NORTH): Sir, that should not go on the record.

SHRI MOHAMMAD SALIM : Why not? It is part of my speech. You cannot take away my speech. सभापति जी, गलती करते हैं तो ठीक है और उसको दुरूस्त करने को कहते हैं तो कहते हैं कि उसको निकालना चाहिए। अजीब हालत है? हम सब इसकी निंदा कर रहे हैं, यहां छूटेगा नहीं। चूंकि हम महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर यह चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। कुछ सदस्यों का बोलना हो गया है और कुछ सदस्य अभी बोलने बाकी हैं। लेकिन यह मामला यहां खत्म नहीं होता है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस सरकार को अभी नौ महीने और कुछ ही दिन हुए हैं। हमारे मनुष्य समाज में इतने दिनों में तो बच्चा पैदा हो जाता है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि अच्छे दिन की भी डिलिवरी हो जाएगी। सरकार समझी कि चलो पहले ही करना है, दिल्ली का चुनाव जनवरी में है, प्रि-मैच्योयर डिलिवरी हो जाए। इसलिए इंटरनैशनल दाई माँ को बुलाया गया। उन्होंने मरीज़ देख कर कहा, बाकी सब तो ठीक था, मन की बात भी हुई, चाय पर चर्चा भी हुई, शूटिंग-शर्टिंग भी हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से सांप्रदायिकता रहेगी, आपके संविधान में आर्टिकल 25 में अकलियतों को जो अधिकार दिया गया है, अगर उससे छेड़-छाड़ होगी और यह सब जो कुछ हो रहा है तो इससे बच्चा पैदा होना मुश्किल है। अच्छे दिन आना मुश्किल है। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please do not reply. Nothing will go on record.

(*Interruptions*) ... *

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Salim, you address the Chair. You come to the point.

---

* Not recorded.

श्री मोहम्मद सलीम : सभापति जी, कभी-कभी ऐसा होता है, हम अपनी समझ से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर हकीकत बयान कर देते हैं। हम ऐसा नहीं मानते हैं कि वह डॉक्टर अच्छा है। हमने नहीं बुलाया। हमने तो उसका विरोध किया। लेकिन कभी-कभी हमें जो बीमारी है, उसका पता चल जाए तो बुरा भी लगता है।

श्री गणेश सिंह (सतना) : सलीम भाई, माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत पवित्र होता है।

श्री मोहम्मद सलीम: बेशक होता है। मुझे आपसे सीखना पड़ेगा। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ और मैं उस पवित्रता की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि इंसानी समाज में ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

श्री मोहम्मद सलीम : अगर मुझे यह सामाजिक, पारिवारिक बंधन के बारे में शिक्षा लेनी पड़े तो गणेश जी मैं तैयार हूँ। अच्छा है, मैं आपके नाम से ही शुरू करता हूँ। ...(व्यवधान) सरकार क्या कह रही है? यही बात हो रही थी। यह सब समय हम हिसाब में लेंगे।

सभापति महोदय, जो महामहिम जी का अभिभाषण है, उसमें कुछ बातें जो हमारे देश में बहुत ही संकटमय स्थिति पैदा कर रही है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। खुद दिल्ली में स्वाईन फ्लू फैल रहा है। पूरे देश में फैल रहा है। अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बयान दिया था। मैं जानता हूँ कि हमारी यह परंपरा है कि यह सरकार का बयान है। लेकिन उसमें जनता की समस्याएं तो आनी चाहिए। अच्छे काम के लिए बेशक डंका पीटा जाए, लेकिन कुछ शंका भी तो होनी चाहिए। लोग आज जो परेशानी में हैं, सीरियस एपिडैमिक आउटब्रेक हो रही है, उसमें केंद्र सरकार कह सकती थी कि हमने सब कुछ किया, राज्य सरकार की कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन जनता की यह समस्या है। देश की यह समस्या है। यह सदन अगर सत्र में है तो लोग उम्मीद करते हैं कि इस बारे में चर्चा हो और सरकार इसको ध्यान में ले।

दूसरी बात है कि यूपीए 2 के जमाने में जो कुछ भी हुआ, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ी, मैं उस पूरी चर्चा को नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर सरकार पक्ष की ओर से यह कहा जाता है कि आपके जमाने में यह-यह हुआ। हम भी कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार का मामला था, जो महंगाई का मामला था, जो बेरोजगारी का सवाल था और जिस तरह से नई आर्थिक नीति के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर, वैश्वीकरण के नाम पर निजीकरण, एफडीआई का ही तो रास्ता चुना था।...(व्यवधान) लोग यह समझ रहे थे कि इससे अब निजात मिलेगी। इसीलिए लोग चुनाव में एक को हराते हैं और दूसरे को जिताते हैं। उस एसेंस को आपको समझना चाहिए। लव जिहाद करने के लिए या घर वापसी के लिए या दंगा-फसाद को भड़काने के लिए तो आपको लोगों ने राय नहीं दी है। विकास हो, सही मायने में विकास हो, सबके साथ

हो, सबके हाथ हो, यही तो लोग सोच रहे थे। हम जब 9 महीने की सरकार के बारे में जायजा लेंगे, पिछले बजट सत्र में हम सुन रहे थे कि अभी सरकार आई है, हम सही ढंग से अपनी नीति को स्पष्ट नहीं कर पाए हैं, इसलिए अभी स्थिति का जायजा लेंगे। लोग यह उम्मीद करते हैं कि चलो अगले साल इसका कुछ निदान होगा।

इस बार के अभिभाषण में हम ऐसी उम्मीद कर रहे थे। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के वक्त जनता के सामने जो मैनिफेस्टो रखा था, उसके आधार पर हमने जो यह वादा किया था, हम इन नौ महीनों में यह-यह कर पाए हैं, यह बहुत कम समय है, इसमें हम पूरी जाँच नहीं कर सकते हैं, पाँच साल के लिए सरकार चुनी गई है और अगले साल में हम यह करना चाहते हैं। हम हमारे ज्ञानी सरकारी पक्ष के सदस्यों से यह कहेंगे कि आप जो मैनिफेस्टो लेकर चुनाव में भाषण दिए और बोले, तो उसे कम से कम फिर से निकालिए। उसे पढ़िए कि कौन मंत्रालय है, उसकी जो जिम्मेदारी आपने तय की है, उसे वह मान रहे हैं तो ठीक है, अगर उसका डिनाई होता तो हम समझते कि सही है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि घोटाले का काला धन एक सौ दिन में लाना था, वह सब चर्चा हो चुकी है। लेकिन काला धन एक बड़ा मामला था, भ्रष्टाचार एक बड़ा मामला है। घोटाला एक बहुत बड़ा मामला है।...(व्यवधान) अगर हम संक्षिप्त में कहें कि नौ महीने में क्या हुआ, एक सर्किल में मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं अपनी व्याख्या में आऊँगा। सरकार क्या कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अनुराग ठाकुर उसे रेफर किए हैं। पूँजी और श्रम का जो अनुपात है, जो संपर्क है, मैं यह नहीं कहता कि पहले बहुत अच्छा था, लेकिन आजादी के बाद इतने साल में, हमने पिछले 9 महीने में यह देखा कि जो पूँजी की जकड़ है, उसे और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। श्रम का जो हिस्सा है, उनका जो हक और अधिकार है, उसे छोटा किया जा रहा है। यही कारण हैं। आप बोल रहे हैं कि बिजनेस अच्छा करना है, इन्वेस्टर्स को मैसेज देना है। विदेश और देश के बड़े-बड़े पूँजीपतियों को थोड़ा संभालना है, उनकी समझ को पैदा करना है। यह तर्क देने के बाद आप क्या कर रहे हैं कि चलो हम लैंड एक्वीजिशन आर्डिनेंस ले आते हैं। मतलब, जो बहुत से छोटे-छोटे किसानों के पास जमीन है, उसका एक कंसंट्रेशन होगा, किसी के पास हजारों एकड़ है, किसी के पास दो हजार एकड़ है, चाहे जिस भी नाम पर आप बोलिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कहिए, रियल एस्टेट के नाम पर कहिए या किसी और नाम पर कहें, लेकिन यह जो अनुपात है, उसे आप बिगाड़ रहे हैं। यह नहीं है कि इसे आप बिगाड़ रहे हैं, यह पिछले बीस साल से बिगड़ रहा था, आप उसी दिशा पर थोड़ा तेज रफ्तार से चल रहे हो। मैं इनका कोई पक्षधर नहीं हूँ। हम इनकी भी उसी बारे में आलोचना कर रहे थे। लोग यह समझ रहे थे कि अब कुछ नया होने वाला है।

तीसरा, जो राष्ट्रीय संपदा है, कोल माइंस, मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स, आप जो भी कहें, दरअसल जमीन तो गई, जमीन के नीचे जो संपदा है, उसे किस तरह से हम इन पूँजीपतियों के हाथ में और ज्यादा दे दें, उसके लिए आप यह कह सकते हैं कि राज्य सरकार को ज्यादा अनुपात में मिलेगा। अभी अनुराग जी कह रहे थे कि 18 ब्लॉक्स में इतने लाख करोड़ रूपए हो गए। यह तो आप संख्या बता रहे हैं। हकीकत में जो देश की राष्ट्रीय संपदा है, जो खनिज पदार्थ हैं, उन्हें हम लूटने की जगह बना रहे हैं। ये जो 9 महीने में आर्डिनेंस आए हैं, ये उसी दिशा में आए हैं।

चौथा, यह है कि यूपीए सरकार भी यही कर रही थी और यह जो भ्रष्टाचार है, घोटाला है, ये जो चार-छह अफसर बड़ी-बड़ी कम्पनियों के पकड़े जाते हैं, यह क्या दर्शाता है? भाजपा, कांग्रेस या सीपीएम यह सवाल नहीं है। जो रूलिंग पार्टी है और उसके साथ जो ब्यूरोक्रैट्स हैं और जो बड़े कार्पोरेट्स हैं, जो संपदा का हैंडओवर चाहते हैं, उसको स्मूथ करने के लिए, आसान करने के लिए उसमें लुब्रिकैन्ट्स दे रहे हैं, चाहे आप निचली सतह के लें चाहे ऊपरी सतह के लें। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आप आए थे, लेकिन अगर आप यही तरीका अपनाएँगे तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, बल्कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और वही बढ़ने और देखने को मिल रहा है। एक्सपीरिएंस के सवाल को लेकर हमारा सरकारी पक्ष कह सकता है कि हमने पकड़ लिया और दिल्ली पुलिस ने काम किया। हम दाद देते हैं कि बेशक यह अच्छा काम है। यह सही है कि जैसे 9 महीने में शुरू नहीं हुआ, लेकिन पहले भी इनके ज़माने में, मैं नाम लेकर कहता हूँ कि रिलायंस कंपनी के अफसर पकड़े गए थे बजट पेपर्स लेकर, तेल मंत्रालय में पकड़े गए थे, फाइनैंस मिनिस्ट्री में पकड़े गए थे, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? क्या सज़ा मिली? कहाँ गया वह केस और कहाँ गया वह मामला और आपको मालूम है कि जब राजीव गांधी प्रधान मंत्री बने थे तो मैगज़ीन में फर्स्ट पेज में कवर में दिया गया था 'मिस्टर क्लीन' चूँकि वह जो मोल है, उसको पकड़ रहे थे। तो शुरूआत में ऐसा एक माहौल खड़ा किया जाता है। लेकिन यह सदन का काम है। अगर कोई भ्रष्टाचार के विरोध में है, घोटाले के विरोध में है कि इसको एक लॉजिकल कनक्लूज़न तक जाना चाहिए और जिस कारण यह भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोकने के निदान के लिए काम होना चाहिए। जितना ज्यादा राष्ट्रीय संपदा, जनता की संपदा और खेती की जो पूँजी है, वह जितना कुछ लोगों के हाथ में जाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, उसी तरीके में अगर उस सर्कल को आप नहीं तोड़ेंगे, हाँ इतना कर सकते हैं कि आप सर्कल को छोटा करें या बड़ा करें, लेकिन सर्कल वही है। मैं इसको एनडीए गवर्नमैंट नहीं कहता, मैं इसे मोदी सरकार भी नहीं कह सकता। बहुत ज्यादा होगा तो इसे यूपीए-2 के बजाय यूपीए-3 कह सकते हैं। जैसे गाड़ी में नंबर दो गियर से तीन नंबर की गियर पर जाते हैं तो यह उदारीकरण की नीति में आप दो नंबर गियर से

तीन नंबर गियर पर आ गए हैं। इनको सज़ा मिली लेकिन इन्होंने उस वक्त नहीं सुना। आप कहते हैं कि इन्होंने ऐसा किया था तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारा पर्यावरण है, एनवायर्नमैंट है, जो बहुत सीरियस मामला है, उसको आप डाइल्यूट कर रहे हैं। उसके लिए आप विदेश के दबाव में आ रहे हैं और उसके लिए भी काम कर रहे हैं चाहे वह जंगल की ज़मीन हो या ट्राइबल की ज़मीन किस तरह से हड़पी जाए, वह कोशिश कर रहे हैं। टैक्स कनसैशन की बात है। अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि इनवैस्टर्स के लिए, चाहे वह वोडाफोन हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, उनका जो रिट्रोस्पैक्टिव टैक्स का मामला है, हम सबका टैक्स माफ कर रहे हैं। यह नौ महीने में आप बहुत कुछ क्या कर रहे हैं? जो नरसिम्हाराव जी और मनमोहन सिंह जी के ज़माने में शुरू हुआ था, उसी रफ्तार को आप थोड़ा और तेज कर रहे हैं। मैं उन स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों को कह रहा हूँ, उन स्वदेशी का नारा देने वालों को कह रहा हूँ कि आप इसलिए बीस साल से यह कोशिश कर रहे थे कि जो काम नरसिम्हा राव नहीं कर पाए, जो काम मनमोहन सिंह नहीं कर पाए, वह हम कर पाए और वह करने से विरोध होगा। दिल्ली के लोगों ने विरोध दिखाया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? और ज्यादा अथॉरिटेरियन होंगे, *इसलिए आप विरोधी पक्ष को कहते हैं कि आप हार गए, आप बोल नहीं सकते। जो इंदिरा गांधी ने आपतकाल करके किया था और वह गलत था, आप उसको भी यहाँ ला रहे हैं। ये दोनों तब कह सकते हैं जब हम * जब हम कनवर्शन की बात करेंगे, जब हम रामज़ादा और * की बात करेंगे, जब लोगों को बिगाड़ देंगे। इस देश की संपदा लूटी जा रही है, इस देश की जनता की एकता को तोड़ा जा रहा है और विरोधी पक्ष के लोग यदि अपने दल के अंदर तर्क की बात कहेंगे तो आप उनको कहेंगे कि खामोश रहो, *यह चंद लोग चलाएँगे। तो ये तीनों अपराध आप कर रहे हैं, चाहे वह सांप्रदायिकता का सवाल हो, चाहे लोकतंत्र का सवाल हो, चाहे पूँजी का सवाल हो, इन तीनों को आप एक साथ जोड़ रहे हैं। यूपीए-3 का मतलब है कि It is a combination of emergency imposed by Indira Gandhi, the economic policies pursued by Narasimha Rao and Manmohan Singh and, at the same time, communalism का जो मामला आया, जिससे अयोध्या तक जला, मुम्बई तक जला, आप उसको भी उस रफ्तार से ले जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमारे भाजपा के सभी सदस्य इस रास्ते पर हैं, मैं ऐसा लांछन नहीं लगाता। लेकिन यह वक्त है कि अभी एक साल हुआ है, आप स्पीडोमीटर को देखो, थोड़ा इंडीकेटर को देखो और फिर सोचो कि आपने क्या बोलकर सफर शुरू किया था और कहाँ जाकर सफर तय करेंगे। बेहतर है कि गियर चेन्ज करना पड़ेगा अगर रूट चेन्ज नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि धन्यवाद ज्ञापन से पहले हमारी सबसे

* Not recorded as ordered by the Chair.

बड़ी समझ और उपलब्धि होगी यदि हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य यह सोचें कि सिर्फ सत्ता संभालना ही काम नहीं है, बल्कि सत्ता का व्यवहार करके स्थिति को बदलना है। तभी आप श्रेष्ठ भारत की बात कर सकते हैं, तभी आप एक भारत की बात कर सकते हैं, वरना सिर्फ नारेबाज़ी होगी। इस अभिभाषण में सिर्फ नारे हैं और नारे के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं इसका विरोध करता हूँ।

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you hon. Deputy Speaker Sir for giving me an opportunity to speak on the Motion of Thanks to the hon. President for his address to both the Houses of Parliament on 23rd February, 2015. I support this Motion on behalf of my Party – YSR Congress Party.

We are happy that the Address presents a large number of positives in the coming days for the country, mainly on the economic and fiscal fronts.

The country is expected to save 50 billion dollars per annum only on account of fall in global crude prices which means a saving of 3 lakh crore rupees. This year the international coal prices have fallen by more than 50 per cent or that of the previous year.

All these factors have substantially contributed to the reduction on Union Government's outflow on subsidies, as a result, we sincerely hope that the fiscal deficit for the current fiscal does not cross the targeted 4.1 per cent of GDP. We broadly welcome the recommendations of the 14th Finance Commission placed before the House on 24th February, 2015. We welcome higher fiscal space for States with tax devolutions from the Centre to States proposed to go up from the present 32 per cent to 42 per cent for the five year period 2015-2020. We also welcome the additional grants given to Andhra Pradesh for meeting the Revenue Deficit for the 2015-2020. But we feel the figure proposed may not be sufficient to meet the actual gap. We request that the amount to be reimbursed may be kept open-ended so that the actual deficit may be reimbursed. We sincerely hope that the Government will honour its promise of granting special category status for Andhra Pradesh and Telangana also, besides all other commitments made in the Andhra Pradesh Re-organisation Act.

Contrary to everybody's expectation, the Government has not yet passed the entire benefit of global crude prices fall to consumers. The Central Government has been enhancing the excise duties and the State Governments on

their part are increasing the VAT on petrol which is now 35 per cent *ad valorem*. We request the Government to further reduce the petroleum prices in line with the global prices.

I am happy that the address promises to fill up the gaps in agricultural and allied activities. We welcome this. Although this has been talked of several times in the past, nothing concrete has been done so far. We cannot forget that China which set its country on the famous economic reform path in 1978, indeed began with comprehensive reforms in agriculture aimed at increasing per acre incomes of the farmers.

Unfortunately, we started our reforms in 1991 without addressing agriculture. The result is that our GDP growth levels over two decades almost remained stagnant at 6 per cent per annum, except perhaps in those years the base had changed.

Sir, even worse is the fact that as against the annual growth rate of 5.2 per cent for agriculture and allied activities for the decade 1981-1991, the subsequent decade saw the fall in growth rate to 2.2 per cent. This has not substantially improved even in the recent decade. This is naturally a matter of serious concern. The sector like agriculture employing about 60 per cent of the country's workforce is growing only at 2 per cent per annum. Our farmers have been toiling day in day out to give us food security by increasing food production year after year.

We do not even compensate them for input price increase. The increase in MSP for various crops for 2014-15 was the lowest in percentage in the last decade. We do not know what happened to Dr. M.S. Swaminathan formula for fixing the MSP. It is unfortunate that in most parts of the country, even this MSP was not implemented as the off-take from FCI and CCI has been reduced and erratic, forcing the farmers to make distress sale at much below the MSP. For how long should we count our food security on the helplessness of our poor farmers? It is not known as to why the Government has not announced export policy for crops like cotton, where the production has exceeded targets. The cotton farmers

suffered the worst during the current year selling the product much below the MSP.

Take the case with supply of urea for Rabi. There was no proper planning. The five months from June to October in 2014-15 saw only 17.37 lakh tonnes being imported, as against 43.82 lakh tonnes during the same period of the previous year. In other words, imports did not happen in time for planting for the rabi season, from November. There was a flood of imports after November. But by then, farmers had already planted their paddy, wheat, mustard or *chana.*

Given the facts that our population increases at least at 2.5 crore per annum, farm yields almost remaining stagnant due to the failure of various States in the country in exploiting available irrigation potential; and dwindling global tradable surplus of food grains due to the developed countries converting the lands which they hitherto used for food crops to renewable energy plantations for meeting the emission standards. Reforms in agriculture should precede all other things, lest we have to witness Bengal famine days.

The NITI Aayog should entirely concentrate on the reforms in agriculture and allied activities. They must closely work with various State Governments laying higher focus on animal husbandry and fisheries.

While on this subject, we request you to reconsider the proposed amendment to enact the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, exempting compliance with the provisions of Chapters 2 and 3 of the said Act in respect of acquisitions for defence, infrastructure etc. As per the newly inserted section 10(A) of the Amendment Bill, Chapter 3 of the Act dealing with prohibition/restrictions on acquisition of irrigated multi-cropped lands will not apply for the aforesaid purposes. Almost all the opposition political parties have threatened to stall the Parliament if the Union Government does not continue the prohibition in relation to acquisition of multi-cropped agricultural lands even for important public purposes. In India, about 48 per cent of the total land is arable land, that is, land

useful for agriculture. Of this, only 20 per cent is served by under gravitation based canal system. This is a priceless asset, given the fact only way the country has been able to increase crop productivity is by harnessing additional irrigation potential.

SHRIMATI SUPRIYA SULE (BARAMATI): Sir, I stand here to thank the hon. President for the Motion of Thanks. Actually, I have been listening to the various speeches that my hon. colleagues are making. I have read over this entire speech several times. There are very very interesting slogans in this. So, for a minute, I did not even know whether I was reading a magazine which was giving me product-oriented advertisements or whether we are talking about the future of the nation. I had really serious concerns about it. These are very interesting slogans. The first one was *Sabka Saath Sabka Vikas.* The other one was *Ekatm Manavata Darshan (*Integral Humanism). One was *Annadaata Sukhibhava.* And the last one was 'Make in India'. 'Make in India' I felt very confident today because my brother Shri Anurag Thakur had extensively talked about Make in India. But his colleague – I was really very pleased in the morning during the Question Hour -- Dr. Jitendra Singh went out of his way to praise the earlier governance and he finally, on behalf of the BJP accepted that governance is a process of continuity. It is not one thing that I did everything right and everything bad is what my predecessor has done.

Sir, it is like when you cook a *thali,* if the food is good and I serve it to you, I will say I cooked it; and if you say something is bad, I will say my sister-in-law cooked it. It does not work like that.

HON. DEPUTY SPEAKER: Very good! You have good experience in that!

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Sir, I am a joint family product. I know how the game works.

Sir, this is a process of continuity. I thank the hon. Minister who accepted that a lot of these processes have been continuing from before. And it is not really us who do it. We are only policymakers who give probably the direction and the right direction. At least we try.

Khargeji has extensively corrected many of the things which needed to be corrected. So, I will not repeat them. There are just a few points that I would like to flag. In *Sabka Saath, Sabka Vikas* they clearly talked about the Prime Minister's

Jan-Dhan Yojana. We welcome it. We welcome anything that is good for the country. We are all here to build a good and a progressive nation. So, whatever is good, we will definitely support the Government even if we are in opposition because we are a responsible opposition.

They said that PM Jan-Dhan Yojana is for the common man. They said that many many thousands of crores of rupees were deposited. My maths is very bad, I do not know. They were making tall claims that a lot of good money has come. We are very happy about it. But the whole point is that if 68 per cent of those accounts have zero deposits, what is really our achievement? Can we claim that it is very good? I do not think it is morally right. I would not claim it.

The other point is, there are many many children who have been probably taken into this scheme. They said you get insurance. There is an RTI activist who has found information about a young boy in Uttarakhand. This has already come in the newspapers also. He was in the scheme and he unfortunately had an accident and passed away. When his father went to get the claim he was told that unless transactions are done over a period of time, you do not get it. So, if 68 per cent people do not have money in their accounts and if there is no transaction happening, then who is going to get the insurance? Should we all not introspect and find out what really this scheme is all about? We are very happy about the scheme. We are very supportive about it. But there are loopholes in it. And I think if it is really for the *Aam Aadmi* - which is what we are supposed to call but you call it *Sabka Saath, Sabka Vikas,* which means the same thing, the bottom of the pyramid, even the hon. Parliamentary Minister said that this is for the poor, for the youth, for the women and for the farmers – then I think we really need to reexamine the scheme. And if there are loopholes, we should correct them.

The other thing is *Ekatam Manavta Darshan* (Integral humanism). Sir, we talk about diversity. India is full of beautiful languages, different kind of foods, different kind of States, lifestyles. And that is what we are proud of. But today are we really that diverse a society? We really need to think and introspect about it.

Salimbhai talked about it, about the communal issues. I remember in the last speech which the hon. President did eight months ago, he talked about a national plan to curb communal violence. It is missing in this speech. What has the Government decided? What is their line? I really need to know it because we are having serious issues.

Shri Piyush Goyal is sitting here who also comes from my State. Comrade Pansare was shot ten days ago. As a matter of fact, their ally Shiv Sena has also come down heavily on the Chief Minister of Maharashtra. He has got such criticism that I now feel very insecure and concerned. Today it is Comrade Pansare who talks openly. We are all liberal thinking people. Tomorrow it could be my turn or anybody else's turn. Maharashtra is a very progressive State. Things have happened. We have tried to address them. Mr. Dabholkar's case happened. We handed it over to the CBI because people showed no confidence in our Government and said maybe we were not capable of handling it. It has happened again. And what worries me most is, we criticizing as opposition is one thing but their own ally Shiv Sena has come down heavily on them. So, where do we really stand on this and who do I turn to? I am really put in a bind. That is why I am bringing this issue up here. Comrade Pansare's death has really shaken the entire country. He was a Communist thinking man. We ideologically may not agree with him, but he was a very modern man. He brought out issues which were beyond communal barriers. Development, which you all talk about, has to go hand in hand.

When the President of America says cruel things to us, we are also pained. We were happy that our Prime Minister hosted him. It is a proud moment for India. Even if we are in the Opposition, eventually when it comes to foreign dignitaries we take a united stand in front. But do we really need foreign dignitaries to say this to us? I think we really need to introspect what has happened to the national plan which you were talking about on communal violence and diversity. You go anywhere in the world, you talk about all these new

programmes, you talk about national issues, your improving relations with everybody. But unless our whole house is in order and diversity is what we are proud of, if we do not put it into action, how will our country go ahead? I urge the Government that you really need to look into this because India is getting a bad name and then you should talk about integral humanism in the speech. It is a contradiction to what the Government is behaving and what it is doing.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह रिक्वेस्ट था कि वह दीन दयाल उपाध्याय...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: You cannot speak. You have to go to your seat and speak.

SHRIMATI SUPRIYA SULE: Since the other issue is sensitive, he can send me the book and I will then not argue this case. I am a very patient listener and I will definitely hear his point of view. The other point which really concerns me and which I thought was very good was talking about toilets for girls which they have said. In 5 months, they are going to build toilet for every girl which is a wonderful thing and I congratulate the Government on it. For every girl, you will have a toilet in the school. That is what I thought I read. Did you not commit to that?

SHRI NISHIKANT DUBEY : It is for every school, not for every girl.

SHRIMATI SUPRIYA SULE : As per the ASER report which normally does the mapping of all these projects, the provision of toilets in schools is 90 per cent, usable toilets are 65 per cent, toilets for girls are 53 per cent and usable toilets for girls are 45 per cent. So I am very happy about this project. If they are going to do it in 5 months, I welcome the step.

I am just selfishly talking about my State and my constituency and I would like to know where is the funding and the implementation and whom do I follow up with. If you tell me that, I will also want to join this programme because I really want every school-going girl and the boy also in my constituency to have a toilet. So if you tell me whom should I approach, it will be appreciated. Most Members will like it. But I remember the Minister of HRD had written to us that

50 per cent of money from our MPLAD fund should be given to toilets. I am confused and I am asking for your advice. One is, we have to pay for the toilets. Secondly, there is a very good scheme named Sansad Adarsh Gram Yojana which has come up. It is a wonderful project. But no special money has been given for it.

HON. DEPUTY SPEAKER: Unless they increase the MPLADS funds, we cannot do it.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Hon. Deputy Speaker Sir, we support you on this point.

SHRIMATI SUPRIYA SULE : My suggestion is, if we have to give money for Sansad Adarsh Gram Yojana and for toilets in schools from MPLADS fund, we cannot do it with Rs 5 crore. I have 1.8 million voters. Why do you not increase the MPLADS fund to Rs 50 crore? Then we will do every project they want. The MPLADS fund can be increased to Rs 50 crore, we will absolutely welcome that.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI PIYUSH GOYAL): Sir, with the Finance Commission's recommendation which has come out in December, the devolution of funds is going to increase by 10 per cent to all the States. So I am sure the hon. Members will appreciate that rather than giving the money to MPs, it will go to the States and they can certainly get the work done which they are unable to do out of MPLADS through the States. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: The point she is raising is, hon. Prime Minister said 50 per cent of the MPLADS fund should go to the toilets. You are telling about the State Government. That is a different issue. It is high time to persuade the Prime Minister and the Finance Minister to increase the MPLADS fund to Rs 5 crore as she said. In Kerala, MLAs are given Rs 30 crore per tenure i.e. Rs.6 crore per year. When they are doing this and creating assets for the country, why cannot you do that?

SHRI A.P. JITHENDER REDDY : Sir, we support you. We are all for it.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : In our State, an MLA is getting not less than Rs 6 crore per year and an MLA during a tenure of 5 years is getting Rs 30 crore. My point is, either you enhance the amount or scrap it. That is my humble request to the Government.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, do not scrap it. If you are getting some cold or cough, you cannot cut your nose or throat; you have to cure it. You can cure as a doctor. You are the Chairman, the doctor. We appeal to you. Instead of scrapping it, you enhance the fund. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY-SPEAKER: Whatever hon. Members have expressed, as the Chairman of the MPLADS Committee, I will convey to the hon. Prime Minister. I will convey your feelings. There are Cabinet Ministers who are also here. They can convey it to the Cabinet and persuade our hon. Prime Minister to see that it is implemented.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SULE : Thank you very much. … (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I cannot direct anything here; we can only make a request.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SULE : The only other thing worth complimenting that the Government is doing is about the *Padho Bharat, Badho Bharat*. It is a very welcome step. It is an extension of the *Sarva Shiksha Abhiyan*. The only question is, they have been talking about a GSI platform, to spend money on GSI. Are you trying to tell me that the Government of India does not know where the schools are? It is already mapped. The ASER Report is a detailed report. The reply to the question on Mid-day Meal Scheme was also there today. All the information is there. Why are we spending time on this? Instead of duplicating all this, we should focus on the commitment they made in the last Address. In the last Address, there was a commitment for five IITs and IIMs. There is no mention of it. There is no

money also for it. The IIT Act is also not being looked into. The commitment was to start five new IITs and IIMs in June, 2015. Where is it? My only concern is this. Education is a very serious subject. It is close to all our hearts. The IITs and IIMs are very important. It is a commitment made last time. There is really no movement on this. Like the policy about curbing communalism, there is no mention of this. So, I really want to flag it to the Government and ask what the status is because we have not been able to find any information.

Another point which is a welcome step is about the *Sukanya Yojana*. I want to make a request to this entire House, including me. We are all making a mistake when we say, 'girl child'; it is not called 'boy child'. Why should it be a 'girl child'? It is a gender sensitivity. We talk about a gender equal society. We welcome this step. I would like to add one point. In the State of Maharashtra, we have had women's reservation since 1994. We have a very good girls' policy. It is really very good. So, if the Government can get that information on Maharashtra's exceptionally well implemented policy, it will be good. When they turn 21 years of age, the deserving girls get lakhs of rupees. It is a much better scheme than what little I have understood about this scheme. Women are put into such a forte!

I would like to take up the thought that Shri Kharge brought up. Since you are such a pro-women Government, you might as well quickly bring in the Women's Reservation Bill right here on the 8th March and let us tell the nation we are serious about it; otherwise, we only talk about it. … (*Interruptions*) We will give your seat out of it. … (*Interruptions*) I am in an open seat.

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down. Another Member also wants to speak.

… (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SULE : I want to make one quick point. They have talked about One-stop Crisis Centres. It is a very welcome step. We have one Centre in every State. If we are really serious about women's security, we cannot afford to have only one Centre in every State. We should have one Centre in every district

and in every block. Here, we are talking about women's security and specifically domestic violence, which is a topic that is not discussed freely in the country. We need to expand this programme.

I will quickly make two more points. We are today talking about farmers' issues. It is something that is close to all our hearts. They have called it *Annadhata Sukhi Bhava*. The situation has unfortunately come to *Annadhata Dukhi Bhava*. I am not saying this. You will see that is the mood of the entire House. Today, you talk about the Land Acquisition Bill. I am not going to talk about it too much right now but there is only one point that really bothered me. In the Address, it says that the Land Acquisition Bill 'has been suitably refined to minimize certain procedural difficulties'. 'Suitable' to whom? Is it the farmer, the consumer, to the Government? I do not really understand what it is. So, I have my reservations. If they would explain to us, I would be really happy.

There is a passing mention about sugarcane farmers in it. Sir, they have talked about oil companies buying the sugarcane. The reality is completely different. The oil companies are not very supportive to sugarcane farmers. Ethanol prices are tendered. Half the time tenders are cancelled and they are not cooperating at all. Payments are never made. Payments are supposed to be made in 14 days and for two-two months they do not do it. As a matter of fact, a BJP ally, Shri Raju Shetty, the hon Member is not here, was also talking against this yesterday. He is an ally of the ruling BJP and he was talking against the Land Acquisition Bill. He did not even go for yesterday's NDA meeting. Nor did Shiv Sena.… (*Interruptions*) Oh, he was there. I am telling you what he told me.… (*Interruptions*) It is none of my business. I am just telling you the fact because unfortunately you do not know much about farmers. I was born in that family so, I know little more than that.

SHRI PIYUSH GOYAL : You may be missing as you were not invited.

SHRIMATI SUPRIYA SULE : No. I am blessed with so many friends and well-wishers. I am happy to go everywhere but I have clarity. I am never confused.

The other thing which is very-very critical, on a very serious note, is Rs.400 crore which the Government of Maharashtra has been asking for the drought that Vidarbha and Marathwada have had. This is something long pending with the Government. Today, supposedly, the ministerial meeting is there. The hon. Agriculture Minister talked about Rs.500 crore. Our demand is of Rs.4000 crore. So, I take this opportunity to say that this drought issue must be addressed.

They have talked about Yoga. We are very happy that they have got into this.

There is another issue which is really troubling this nation and that is tobacco. I have lost one of my closest colleagues recently due to oral cancer caused because of tobacco. In Maharashtra we have managed to ban gutka. Gutka is one of the very crude things which is available in India and is distributed. It is the biggest cause of oral cancer. If this Government could kindly address the gutka and tobacco issue and help us by banning it and by bringing awareness that will be of great help to the society.

I think I am running short of time. I will not take much of your time. I thank the hon. President for his speech but if there is a little more clarity, I think we would all have felt far more satisfied. Thank you.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाण के बाद जो बहस शुरू हुई है, मैं उसकी चर्चा में भाग लेते हुए अपनी राय रख रहा हूं। 16वीं लोक सभा के गठन के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का 9 जून, 2014 को एक अभिभाण आया। महामहिम के द्वारा 23 फरवरी को दूसरा अभिभाण सामने आया, यह सरकार का आईना है, उसी के आधार पर सरकार अपनी कार्यसंस्कृति को आगे बढ़ाएगी। इसी वक्त दैनिक जागरण के एक पहलू को मैं उद्धृत करना चाहूंगा, जिसमें आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी का एक लेख आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आबादी के एक वर्ग में यह अवधारणा बन रही है कि यह सरकार बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दे रही है और गरीब, मध्यम वर्ग पर उतना ध्यान नहीं दे रही है जितना ध्यान देना चाहिए था। वे बीजेपी के वरिष्ठ माननीय नेता हैं, इसीलिए इसको उद्धृत किया हूं, जब इधर से विपक्ष बोलता है तो आप लोग यह मानते हैं कि मेरा विरोध हो रहा है। हमको इंडिया को क्यों नहीं इंडिया शाइनिंग में ले जाते हैं। ...(व्यवधान) जब अच्छे दिन आएंगे तो जरूर बोला जाएगा।

महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के अभिभाषण में सांस्कृतिक विरासत की बात कही गई है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर या विरासत हमारी एकता, अखंडता, भाईचारा और सद्भावना है। हम सब एक हैं। कहीं से नफरत का बू भी नहीं आना चाहिए। लेकिन नई सल्तनत आने के बाद इतनी नफरत की आवाज क्यों गुंजने लगा, यह पहले भी नहीं गूंजती थी, इसे जब रोका भी जाता है, तब भी नहीं रूकती है, जब टोका जाता है तब भी नहीं रूकती है। इसके पीछे क्या कारण है? इसका मतलब है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, उस पर चोट हो रही है, हमला हो रहा है। एक कहावत कही जाती है कि 'सर्वजन हिताय'। सर्वजन हिताय का मतलब है कि समाज के सभी धर्म, मजहब, जाति का विकास हो, यानी हम इस देश, मुल्क को आगे बढ़ायें। यह चमन हमारा है, बगिया हमारी है, फुलवाड़ी हमारी है और हम सब इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि इसमें बहुत कमजोरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सबका साथ-सबका विकास। हम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण को उद्धृत कर रहे हैं। सबके साथ चलने के लिए आपको बड़ा दिल रखना पड़ेगा, सागर बनना पड़ेगा, हृदय उदार रखना पड़ेगा, लेकिन आपमें उदारता नहीं है। इसी कारण अमेरिकी राष्ट्रपति जाते-जाते अपनी बात कहकर चले गये कि भारत को एक रखना है, अखंड रखना है तो समाज के सभी धर्मों को आदर देना चाहिए। सरकार से लोगों ने जो उम्मीदें रखीं, इन्होंने उसे समाप्त कर दिया। जो बुनियादी सुविधा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। आप कहते हैं कि समावेशी विकास करेंगे। समावेशी विकास गांव से चलता है। गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी, पिछड़े और माइनोरिटीज का हमें विकास करना है। सभी वर्गों के समावेशी विकास के

लिए आपके पास कोई कालबद्ध योजना नहीं है। यह देश नारे से नहीं चलता, काम से चलता है। आपने चुनाव से पहले एक नारा दिया, सब्ज-बाग दिखाया और लोग मुगालते में आ गये। लेकिन आज देश के सभी वर्ग और नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यह क्या हो गया?

आपने श्रेष्ठ भारत की बात कही, एक भारत की बात कही। आदरणीय अनुराग जी और निशिकांत जी ने अपनी स्पीच में सरकार की प्रशंसा की। लेकिन आज काले धन के सवाल पर चुप्पी साधी जा रही है। यह चुप्पी क्यों साधी जा रही है? चुनाव से पहले सबसे बड़ा डंका ये लोग ही बजा रहे थे कि स्विस बैंक से काला धन आयेगा, तो पन्द्रह-पन्द्रह लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में जायेगा। आज इस मुल्क के लोग जानना चाहते हैं कि वह काला धन क्यों नहीं आया? यह बात केवल सदन में ही नहीं उठ रही, बल्कि गांव, गलियों और टोले-मोहल्लों में भी उठ रही है। हमारे जो निरक्षर भाई हैं, उनके दरवाजे तक यह बात चली गयी है। आज आपका यह नारा है कि बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देंगे, हरेक को नौकरी देंगे। लेकिन सात नौकरियां भी आपने नहीं दीं। आपने नौकरी देना बंद कर दिया है। आज नौजवान उत्साह, आशा और विश्वास में है कि हमें नौकरी मिलेगी। पढ़े-लिखे नौजवान जो बी.ए., एम.ए., पोलिटेक्निक, आई.आई.टी. करके बैठे हुए हैं, वे सोचते हैं कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन सब्ज-बाग दिखाकर आवाम और नौजवान के साथ ठगी की गयी।

महंगाई की जहां तक बात है, तो वह आज नहीं घटी है। हर कोई कबूल करता है कि महंगाई नहीं घटी है। सब्जी, नमक, तेल, दाल, चावल आदि घरेलू सामान का दाम नहीं घटा है। ये कहते थे कि हम आयेंगे तो महंगाई घटायेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पेट्रोल और डीजल का दाम आपने नहीं घटाया, क्योंकि इनके दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से निर्धारित होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर यही हुआ, डंका खूब बजा, शोर खूब हुआ, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली कहावत आज बी.जे.पी. के लिए चरितार्थ हो रही है। यही आज स्थिति बन रही है। जन-धन योजना लागू की गयी और कहा गया कि हम अच्छे दिन लायेंगे। ...(व्यवधान) हर हाथ को काम देंगे और हर खेत को पानी देंगे। आज हर हाथ काम मांग रहा है, हर खेत पानी मांग रहा है। हम बिहार के बांका जिले से आते हैं, वहां आज भी इंसान नदी के पानी को पी रहा है।

18.00 hrs.

आज वहां पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, इसीलिए आज वहां स्थिति बद से बदतर हो गयी है। ...(व्यवधान) बौद्ध सर्किट बन रहा है, अच्छी बात है, और सर्किट बने, लेकिन हमारी मांग है कि शेरशाह सूरी, जिन्होंने

ग्रांट ट्रंक रोड बनाई, उनके नाम पर एक परिपथ बनना चाहिए। बिहार को विशेष दर्जा देना चाहिए। लगभग 284 घोषणाएं की गई हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY-SPEAKER: If the House agrees, then we can continue till the speech of the hon. Member is over.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : जिनमें से पांच घोषणाएं भी इम्पलीमेंट नहीं हुई हैं। इसलिए इस सत्ता को खुशी नहीं है, गम करना चाहिए कि आपने बेहतर भारत बनाने का सपना पूरा नहीं किया है। मनरेगा में यही हालत है, निर्मल भारत में यही हालत है, आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात और सारा सब्जबाग दिखाने की बात, आज की तारीख में हम मानते हैं कि यह सरकार घोषणा वाली सरकार है, कर्म वाली सरकार नहीं है, काम वाली सरकार नहीं है, यह सिर्फ सब्जबाग दिखाकर सत्ता में आई है। इसलिए अजेय बहुमत की यह सरकार अध्यादेश लाई है। इसीलिए अध्यादेश यह बताता है कि इस शासक की नीयत ठीक नहीं है। यह बात संसद में भी साबित हुई और दिल्ली के विधान सभा चुनाव में भी यह बात साबित हुई है। इसलिए सत्ता का चिराग बुझता जा रहा है, रोशनी बदलती जा रही है, अजेय बहुमत अब पराजय की ओर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि, लोकतंत्र की खूबसूरती को आपने बर्बाद करने का काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा कि सरकार को कितना भी बोला जाएगा, यह सुधरने वाली नहीं है। अच्छे दिन नहीं आज काला दिन आ रहा है और इसे सभी लोग समझ रहे हैं। आप लोग भी समझ रहे हैं, क्या आप लोगों के काम हो रहे हैं?

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: हम लोग माननीय सदस्य हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं अन्य योजनाओं में क्या स्थिति है।

HON. DEPUTY-SPEAKER: Please wind up.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय ने समय दिया, मैं उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

HON. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m.

18.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, February 26, 2015/Phalguna 7, 1936 (Saka)